सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल चौदह	–	किसी इलैक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हों या धारित हों।
मैनुअल पंद्रह	–	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हों तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित है।
मैनुअल सोलह	–	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिश्टियां।
मैनुअल सत्रह	–	लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना जो विहित की जाये।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – चौदह	किसी इलैक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हों या धारित हों।
मैनुअल – पंद्रह	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हों तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित है।

मैनुअल – सोलह	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।
मैनुअल – सत्रह	लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना जो विहित की जाये।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – चौदह किसी इलैक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हों या धारित

हों।

मैनुअल – पंद्रह	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हों तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित है।
मैनुअल – सोलह	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।
मैनुअल – सत्रह	लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना जो विहित की जाये।

विषय–सूची

क्रम संख्या	विषय
1	प्रस्तावना
	मैनुअल – चौदह
1.	ई–गर्वनेन्स हेतु प्रयास
2.	स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों की निकायवार सूची
	मैनुअल – पंद्रह
1.	शहरी विकास निदेशालय में पुस्तकालय की सुविधा
2.	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों में वाचन कक्ष / पुस्तकालय की सुविधा
3.	नगर निगम द्वारा वाचन कक्ष / पुस्तकालय की सुविधा
	मैनुअल – सोलह
1.	शासन द्वारा शहरी विकास विभाग के लिए नियुक्त लोक सूचना अधिकारी
2.	नगर निकायों में तैनात लोक सूचना अधिकारी
3.	शासनादेश संख्या – 2334 / V / श0वि0–05–145 दिनांक 31–08–2005
	मैनुअल – सत्रह
1.	लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना
2.	प्रगति विवरण
3.	ग्राफिक विवरण
4.	मांग वसूली विवरण

*****

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–चौदह
{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xiv) में निर्देशित}

किसी इलैक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हों या धारित हों।
ई–गर्वनेन्स हेतु प्रयास

ई–गर्वेनेंस

सूचकांक

1.इस पुस्तिका के बारे में

दस्तावेज़ का उद्देश्य इस DIGIT उत्पाद के विविध संग्रह सेवा मॉड्यूल के संचालन में कर्मचारियों की सहायता करना है।

यह मॉड्यूल कर्मचारियों को विभिन्न सेविकाओं जैसे विज्ञापन, पार्किंग, किराए आदि के लिए शुल्क एकत्र करने की अनुमति देता है।

.

2 सामान्य कार्य:

1) सिस्टम में लॉगिन करें:

कर्मचारी नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके सिस्टम में लॉग इन करता है:

https://mseva.bihar.gov.in/employee/

कर्मचारी उपरोक्त पृष्ठ पर उतरता है और क्रेडेंशियल्स दर्ज करता है।

4) अगली स्क्रीन विवरण स्क्रीन है जहां उपभोक्ता के विवरण को जोड़ना होगा।

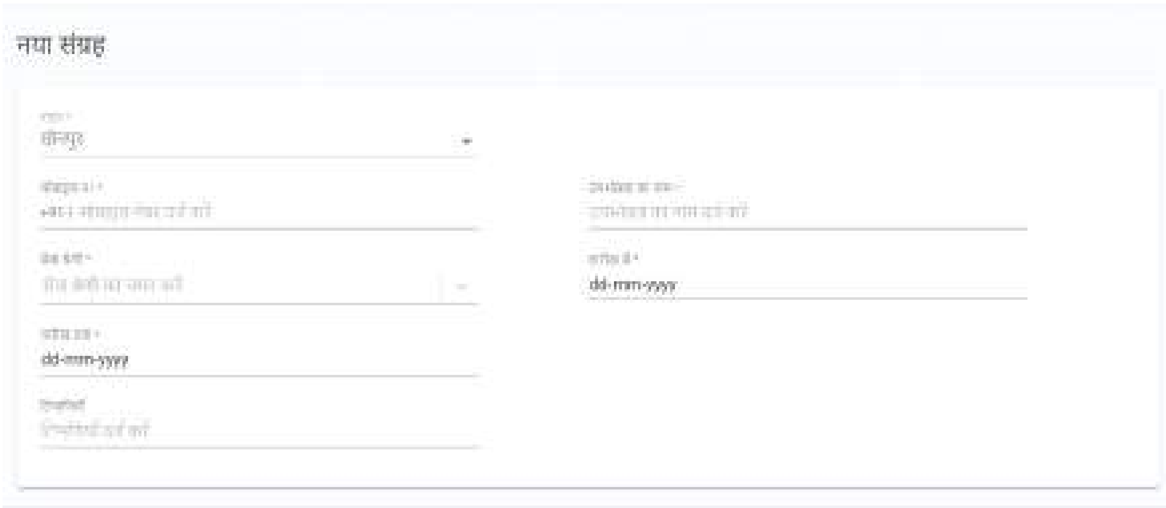

स्क्रीन में जोड़े जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

क्षेत्र का नाम	**विवरण**
मोबाइल न.*	उपभोक्ता का मोबाइल नं।

उपभोक्ता का नाम*	उपभोक्ता का नाम
सेवा श्रेणी*	वह श्रेणी जिसके लिए सेवा संबंधित है
सेवा प्रकार*	सेवा क्या है
तारीख से*	सेवा उपयोग शुरू करने की तिथि
तारीख तक*	सेवा उपयोग को समाप्त करने की तिथि
टिप्पणियाँ	कोई भी टिप्पणी जो कर्मचारी दर्ज करना चाहेगा

* - फ़ील्ड अनिवार्य हैं

जैसे ही आप उस सेवा का चयन करेंगे जिसके लिए शुल्क को 4 और क्षेत्रों में एकत्र किया जाना है जिसके लिए शुल्क जमा करना होगा, प्रदर्शित किया जाएगा:

- **टैक्स:** उस टैक्स राशि को दर्ज करें जो कि इस्तेमाल की जा रही विशेष सेवा के लिए लागू होती है।
- **फील्ड शुल्क:** यदि क्षेत्र निरीक्षण के लिए कोई शुल्क है जिसे शामिल किया जाना है।
- **CGST और SGST:** उपयोग की जा रही सेवा पर लागू राज्य और केंद्रीय माल कर दर्ज करें।

सेवा का भुगतान करने के लिए नीचे दाएं कोने में अगले बटन पर क्लिक करें.

2.भुगतान

अगली स्क्रीन उन भुगतानों के लिए है जहां नियोक्ता भुगतान के लिए विवरण एकत्र कर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है।

उपभोक्ता नकद / चेक / डीडी / क्रेडिट / डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकता है।कर्मचारी अपने अनुसार विवरण भर सकता है और उपभोक्ता भुगतान कर सकता है:

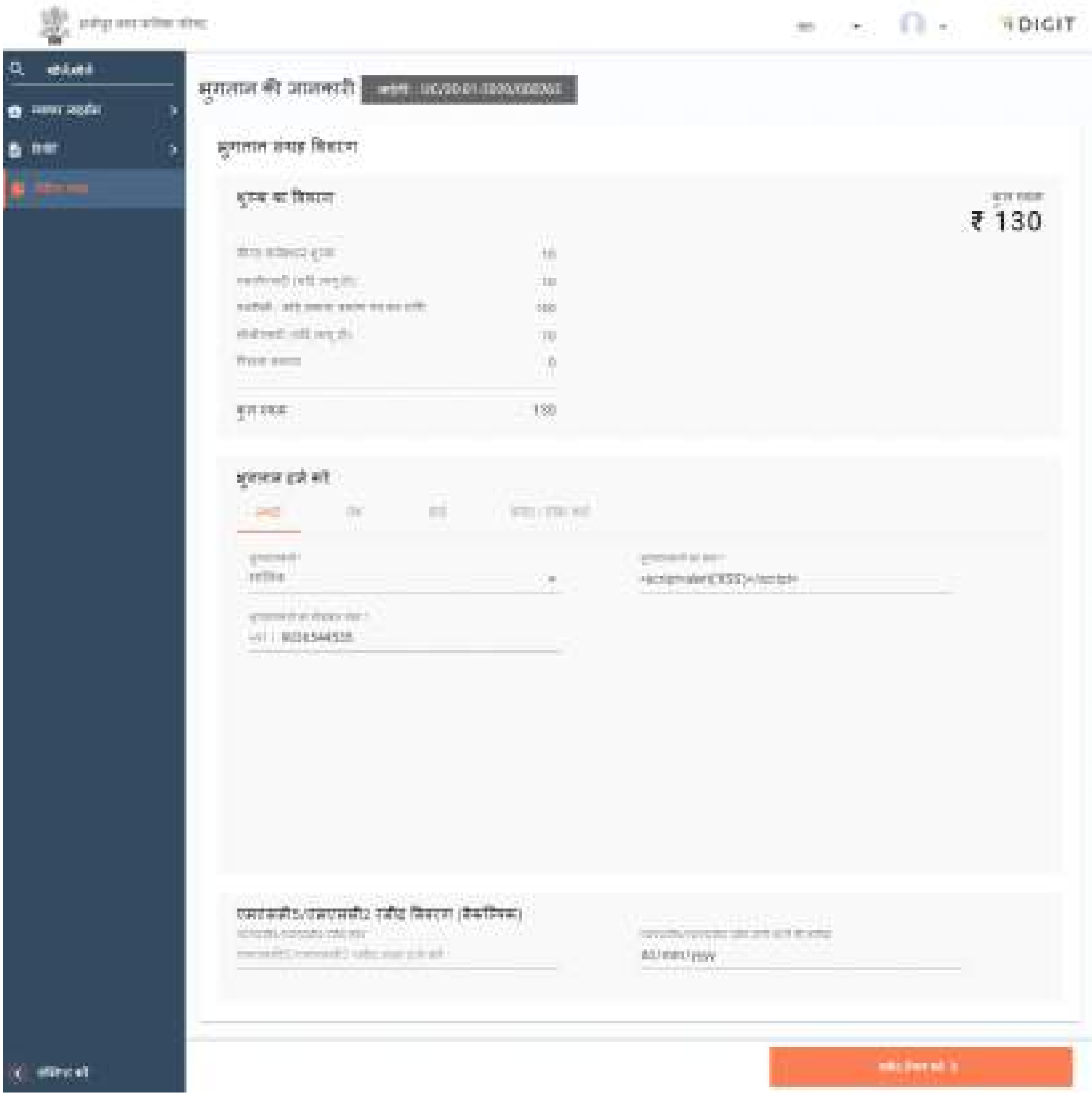

<u>कृपया ध्यान दें:</u> सेवा के लिए भुगतान या तो मालिक द्वारा किया जा सकता है या किसी और द्वारा किया जा सकता है जिसे मैदान में भुगतान किए गए ड्रॉप डाउन से चुना जा सकता है।

3.रसीद डाउनलोड करें

जैसा कि भुगतान किया जाता है नीचे स्क्रीन दिखाई देती है:

<u>रसीद के लिए मानक प्रारूप</u>

सोनपुर नगर निगम

Miscellaneous भुगतान रसीद

रसीद संख्या.	01/2019-20/000226	**उपभोक्ता आईडी**	UC/24-01-2020/000425
भुगतान तिथि	24/1/2020	**भुगतानकर्ता का नाम**	Deep
फ़ोन	8696580640		

सेवा प्रकार	बिजली चुंगी	**बिलिंग अवधि**	25/11/2019 से 3/1/2020
भुगतान की गई राशि	₹ 10795168	**बकाया राशि**	₹ 0
भुगतान का प्रकार	नकद	**लेन-देन आईडी**	sonpur1019231521
एमएससी5/एमएससी2 रसीद सं.	NA	**एमएससी5/एमएससी2 रसीद की तारीख**	NA

द्वारा: UCEmployee

आयुक्त / ईओ

यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रसीद है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

अस्वीकरण

1. चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त भुगतान प्राप्ति के अधीन होगा।
2. यह दस्तावेज़ संपत्ति स्वामित्व और अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण का प्रमाण नहीं है।
3. यह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है, इसलिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
4. आकलन और भुगतान प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण द्वारा सत्यापन / जांच के अधीन है।
5. कृपया पहले के वर्षों के लिए भी बकाया संपत्ति कर जमा करें। यदि पहले से भुगतान किया गया है तो अनदेखा करें।

z

उपयोगकर्ता पुस्तिका

व्यापार लाइसेंस

उत्तराखण्ड राज्य

Powered By egov FOUNDATION

प्रस्तावना

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य नागरिकों को व्यापार लाइसेंस प्रणाली (TLS) के संचालन में मदद करना है। यह एक डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे नागरिक आवेदन कर सकता है
व्यापार लाइसेंस के लिए और बाद में भुगतान ऑनलाइन करें। व्यापार लाइसेंस नागरिकों को अनुमति देता है:

- व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
- व्यापार लाइसेंस के लिए भुगतान पूरा करें।
- व्यापार लाइसेंस की स्थिति का ध्यान रखें।
- किसी भी व्यापार लाइसेंस के लिए किए गए भुगतान की रसीदें डाउनलोड करें।
- एक व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल बनाए रखें।

यह मैनुअल व्यापार लाइसेंस एस की विभिन्न विशेषताओं को शामिल करता है और हर सुविधा को परिभाषित किया गया है।

उपयोगकर्ता की सहायता के लिए स्क्रीनशॉट भी दिए गए हैं।

यदि आपको और मदद की आवश्यकता हो, तो कृपया contact@egovernments.org पर एक ईमेल भेजें।

1.उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल के कार्य

आवेदन के सामान्य कार्य निम्नलिखित हैं:

1.1 एप्लीकेशन में लॉगिन करना

लॉगिन करने के लिए, कृपया निम्न लिंक पर जाएं:

https://nagarsewa.uk.gov.in/citizen

1.2.प्रोफ़ाइल का संपादन

अपनी प्रोफ़ाइल को संपादित करने के लिए नीचे दिखाए गए चरणों का पालन करें। आप ऐसा कर सकते हैं:

- प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपलोड करें
- मोबाइल नंबर को कैप्चर / अपडेट करें

● ईमेल आईडी कैप्चर / अपडेट करें

1.3 नाम, मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी अपडेट करना

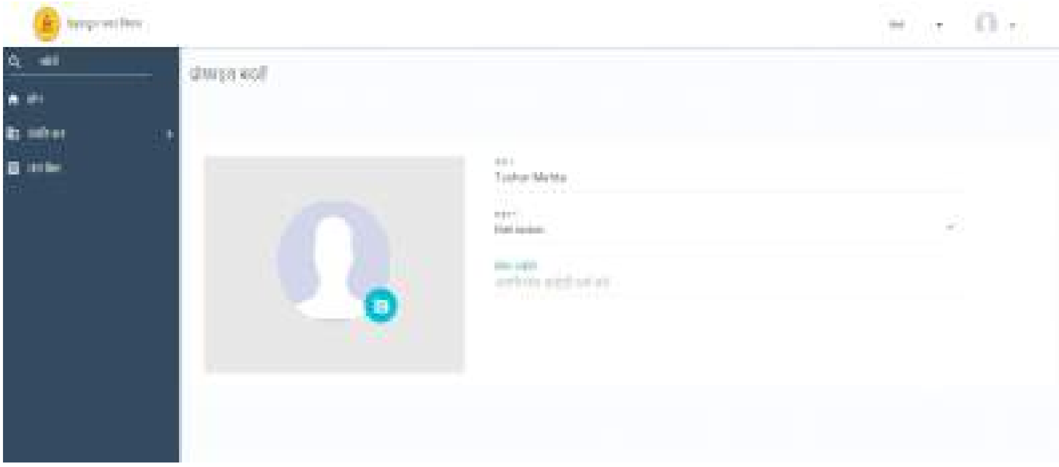

1.4. प्रोफाइल फोटो अपलोड करना

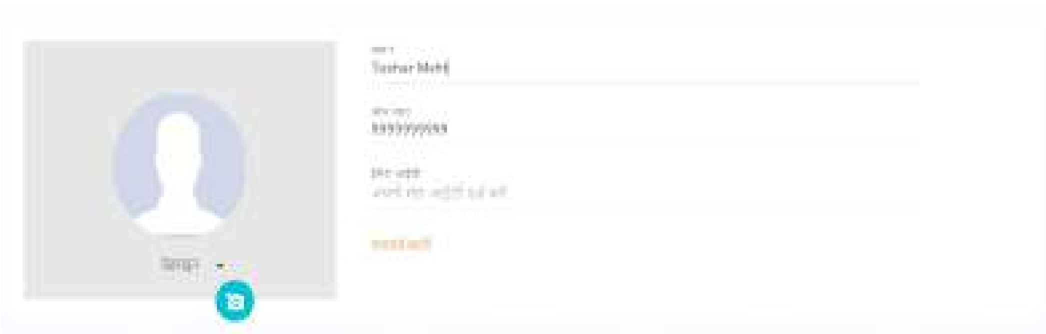

नए/ नवीकरण व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना

आपका स्वागत है Tushar Mehta

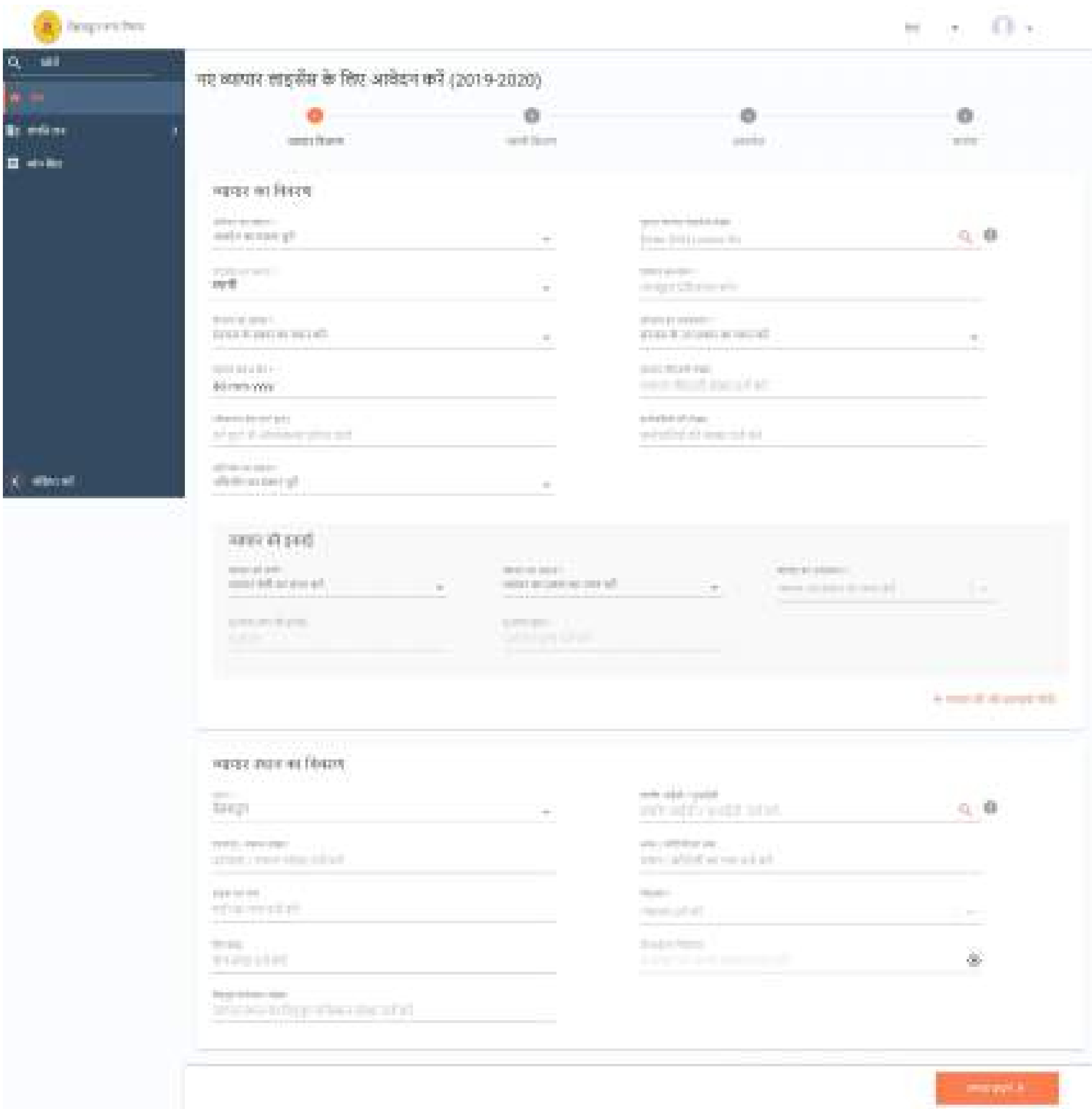

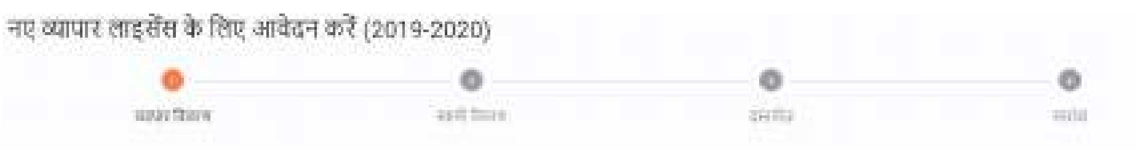

व्यापार विवरण में उप भाग निम्नलिखित हैं:

2.1. व्यापार विवरण उप-वर्ग

व्यापार विस्तार उप-भाग के लिए एक स्क्रीन निम्नलिखित है:

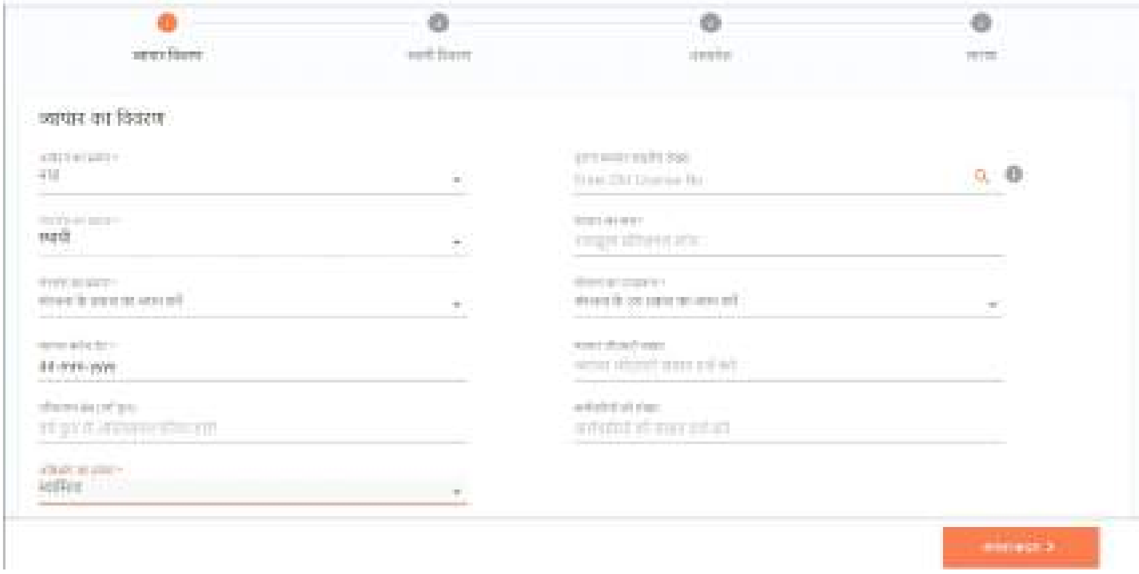

व्यापार सब-सेक्शन में निम्नलिखित क्षेत्र हैं

वित्तीय वर्ष	उस वित्तीय वर्ष का चयन करें जिसके लिए लाइसेंस लागू है।
आवेदन का प्रकार	वेदन प्रकार का चयन करें: ● नया ●नवीनीकरण ((यदि यह नवीनीकरण का आवेदन है तो आवेदन का प्रकार में नवीनीकरण का चयन करें |)
पुराना एप्लीकेशन नंबर	यदि यह नवीकरण है, तो पुराना एप्लिकेशन नंबर अनिवार्य है
व्यापार का नाम *	व्यापार का नाम दर्ज करें
संरचना प्रकार *	ड्रॉप-डाउन से संरचना प्रकार का चयन करें। यह हो सकता है: ● अचल ● चल
संरचना उप प्रकार *	से संरचना उप प्रकार का चयन करें ड्रॉप डाउन। यह हो सकता है: ● शेड ● ओपन लैंड आदि

व्यापार कमिशन डेट *	वह दिनांक निर्दिष्ट करता है जिससे व्यापार होता है संचालन। यहां सिटीजन इनपुट भी दे सकते हैं एक वित्तीय वर्ष के भीतर भविष्य की तारीख।
व्यापार जीएसटी नंबर *	व्यापार से संबंधित जीएसटी संख्या इनपुट की आवश्यकता है।
ऑपरेशन क्षेत्र (वर्ग फीट)	परिसर / संपत्ति के परिचालन क्षेत्र को इनपुट करने की आवश्यकता होती है जहां व्यापार आयोजित किया जाता है।
कर्मचारियों की संख्या	व्यापार में कार्यरत कोई भी कर्मचारी जिसके लिए लाइसेंस लागू नहीं है।
व्यवसाय प्रकार *	ड्रॉप-डाउन से उपयुक्त व्यवसाय प्रकार का चयन करें

* : जब उपयोगकर्ता व्यापार के लेबल पर क्लिक करता है, तो लेबल का रंग बदल जाता है लाल करने के लिए, यह निर्दिष्ट करते हुए कि उस लेबल पर कार्रवाई की गई है। उदाहरण नीचे दिखाया गया है:

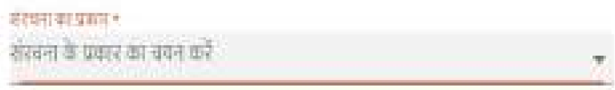

2.2. व्यापार इकाई उप-वर्ग

व्यापार यूनिट सब-सेक्शन के लिए एक स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार यूनिट अनुभाग में निम्नलिखित क्षेत्र हैं:

व्यापार श्रेणी *	से संबंधित उपयुक्त श्रेणी का चयन करें ड्रॉप-डाउन से व्यापार। यह हो सकता है: ● माल ● सेवाएँ
व्यापार प्रकार *	संबंधित उपयुक्त व्यापार प्रकार का चयन करें ड्रॉप-डाउन से व्यापार करना। यह मैदान है व्यापार श्रेणी पर निर्भर। 1) यदि उपयोगकर्ता ने व्यापार का चयन किया है माल के रूप में श्रेणी फिर व्यापार के प्रकार होगा: ● बिक्री / भंडारण ● निर्माण। ● थोक 2) यदि उपयोगकर्ता ने व्यापार का चयन किया है सेवा के रूप में श्रेणी तो व्यापार प्रकार होंगे: ● माल आधारित सेवाएँ ● नॉन गुड्स बेस्ड सर्विसेज
व्यापार उप प्रकार *	व्यापार उप प्रकार पर निर्भर है चयनित व्यापार श्रेणी और व्यापार प्रकार। सूची के अनुसार है ऊपर से चयनित क्षेत्र।

*अनिवार्य क्षेत्र

- विवरण को अंतिम रूप देने के बाद पर क्लिक करें :

2.3 व्यापार मालिक का विवरण

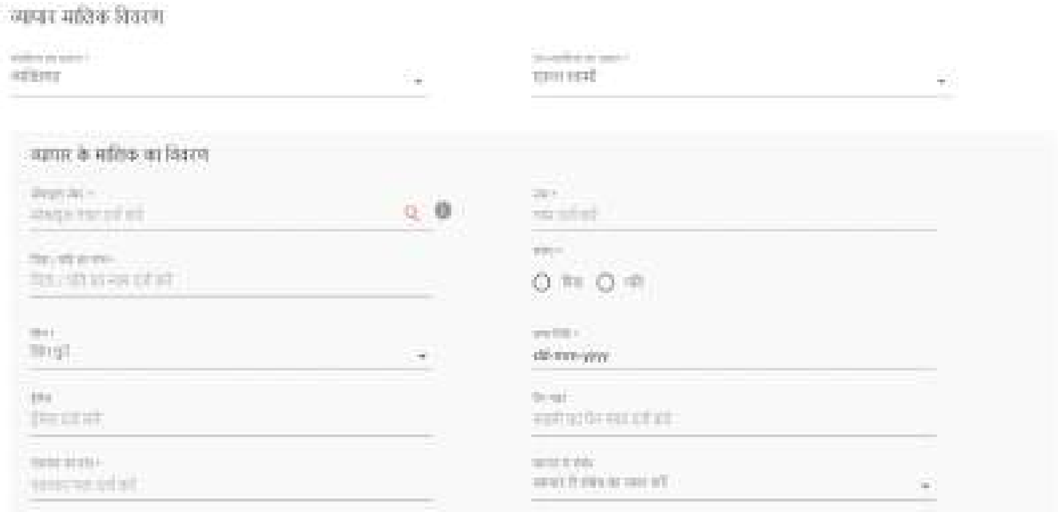

व्यापार विवरण में निम्नलिखित अंश हैं:

2.4. व्यापार स्वामी विवरण उप-वर्ग

व्यापार इकाई उप-खंड के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार स्वामी डिटेल्स सब्सक्रिप्शन में फ़ील्ड निम्नलिखित हैं:

स्वामित्व के प्रकार*	उपयुक्त प्रकार के स्वामित्व का चयन करें उस व्यापार से संबंधित है जिसके लिए लाइसेंस है लागू हो रहा है।.
उप-स्वामित्व का प्रकार *	उपयुक्त प्रकार का चयन करें के लिए व्यापार से संबंधित उप-स्वामित्व जिसे लाइसेंस लागू किया जा रहा है।

*अनिवार्य क्षेत्र

2.5. स्वामी सूचना उप-वर्ग

स्वामी सूचना उप-भाग के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार स्वामी डिटेल्स सब्सक्रिप्शन में फ़ील्ड निम्नलिखित हैं:

मोबाइल नंबर*	प्राथमिक स्वामी का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
नाम *	स्वामी का नाम दर्ज करें
पिता / पति का नाम *	स्वामी पर लागू होने वाले पिता / पति का नाम या तो दर्ज करें।
संबंध *	विकल्प पिता या पति से संबंध चुनें
लिंग *	ड्रॉप-डाउन बॉक्स से लिंग का चयन करें।
जन्म की तारीख*	स्वामी की जन्म तिथि दर्ज करें।
ईमेल	व्यापार स्वामी ईमेल आईडी दर्ज करें
पैन नं	मालिक का पैन नंबर दर्ज करें।
पत्राचार का पता*	उस पते को दर्ज करें जिस पर स्वामी पहुँचा जा सकता है।
संबंध प्रकार	ड्रॉप-डाउन से रिलेशन टाइप चुनें

*अनिवार्य क्षेत्र

- यदि नागरिक ने कई मालिकों का चयन किया है, तो नागरिक इसे जोड़ सकता है कई मालिकों पर क्लिक करके ।
- सभी विवरण भर जाने के बाद, अगला चरण पर क्लिक करें।

2.6.दस्तावेजों को अपलोड करना

निम्नलिखित दस्तावेज़ हैं जिन्हें अपलोड करना आवश्यक है

स्वामी आईडी प्रमाण *	प्रासंगिक स्वामी आईडी प्रमाण अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ाइल विकल्प पर क्लिक करें। जो दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं, वे हैं: 1. आधार कार्ड 2. वोटर आईडी कार्ड 3. ड्राइविंग लाइसेंस मालिकों के आईडी प्रूफ से संबंधित दस्तावेज ULB से ULB तक भिन्न हो सकते हैं।
स्वामित्व प्रमाण *	अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ाइल विकल्प पर क्लिक करें प्रासंगिक स्वामित्व प्रमाण। जो दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं वे हैं: 1) किराया डीड 2) लीज डॉक 3) संपत्ति की रजिस्ट्री 4) अटॉर्नी की सामान्य / विशेष शक्ति स्वामित्व प्रमाण से संबंधित दस्तावेज ULB से ULB तक भिन्न हो सकते हैं।

*अनिवार्य क्षेत्र

* पुनश्च: केवल JPEG और PDF फ़ाइलों को अपलोड करने की अनुमति है, जिनका अधिकतम आकार 6MB से कम होना चाहिए।

- सभी विवरण भर जाने के बाद, अगला चरण पर क्लिक करें।

2.7.सारांश

एक बार जब नागरिक दस्तावेजों को अपलोड कर लेता है, तो अगला चरण सारांश होता है भरे हुए आवेदन पत्र को नीचे दिखाया गया है।

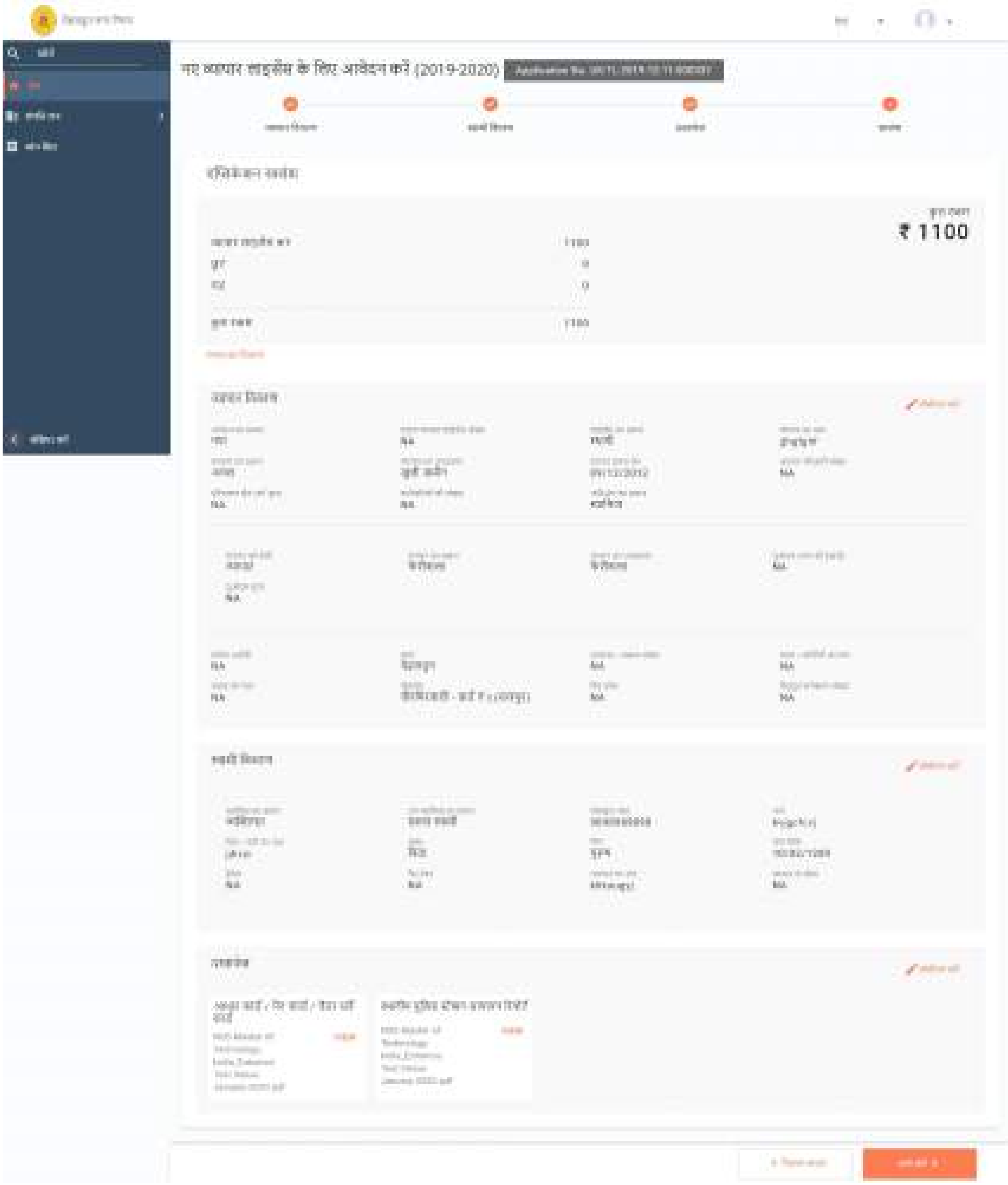

लाइसेंस शुल्क का भुगतान

एक बार जब आवेदन अनुमोदनकर्ता द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो नागरिक 2 तरीकों से लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकते हैं:

1) लॉग इन करके और उसके आवेदन की खोज करके स्वयं भुगतान।

2) ULB काउंटर पर।

ऑनलाइन भुगतान

नागरिक अपने आवेदन के लिए खोज करता है और फिर वह नीचे स्क्रीन पर पहुँचती है:

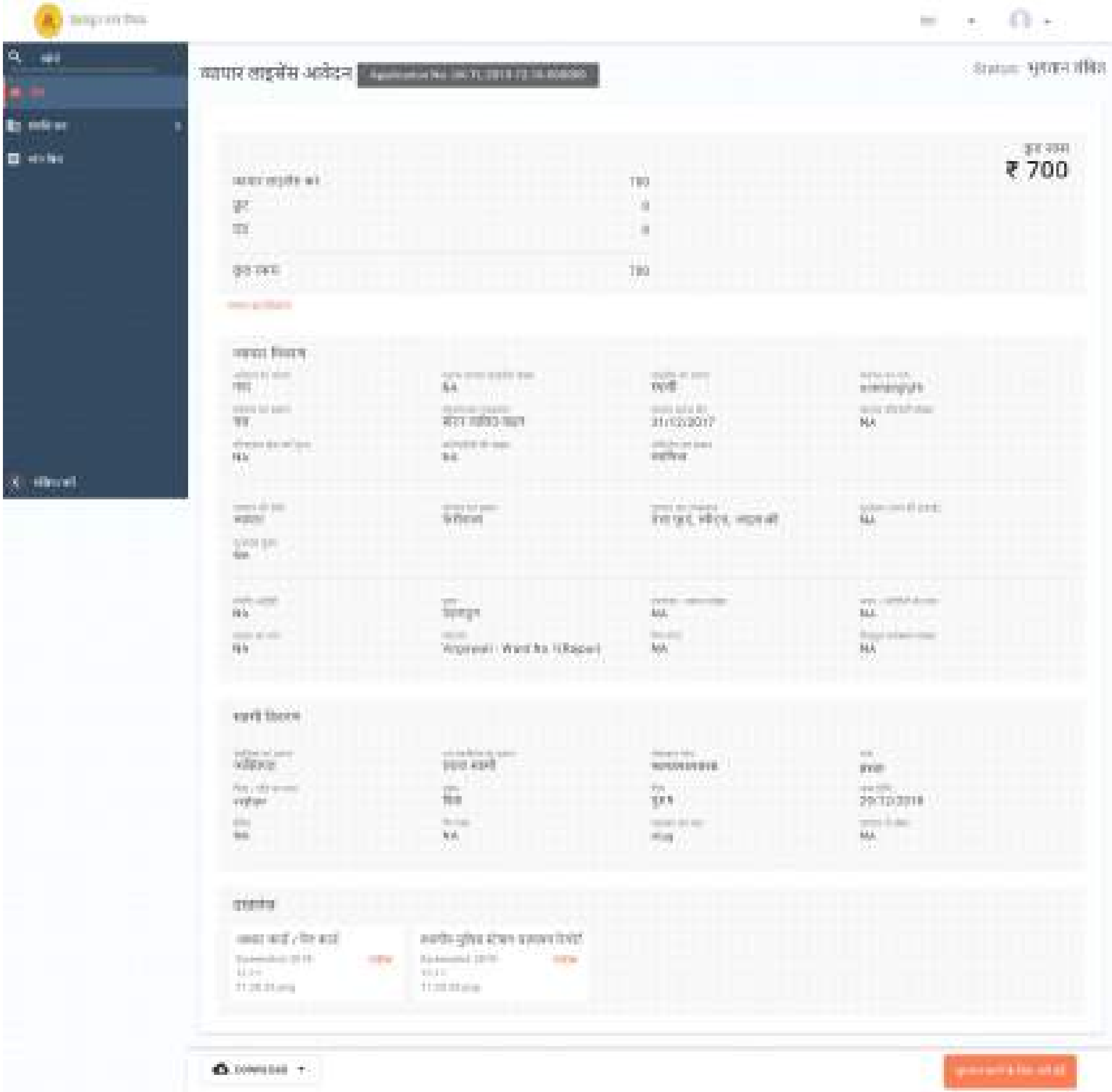

अगली स्क्रीन पर राशि देख सकते हैं और फिर भुगतान करें बटन पर क्लिक करें:

अगले पृष्ठ पर उपयोगकर्ता बैंक विवरण भर सकता है और भुगतान पूरा कर सकता है:

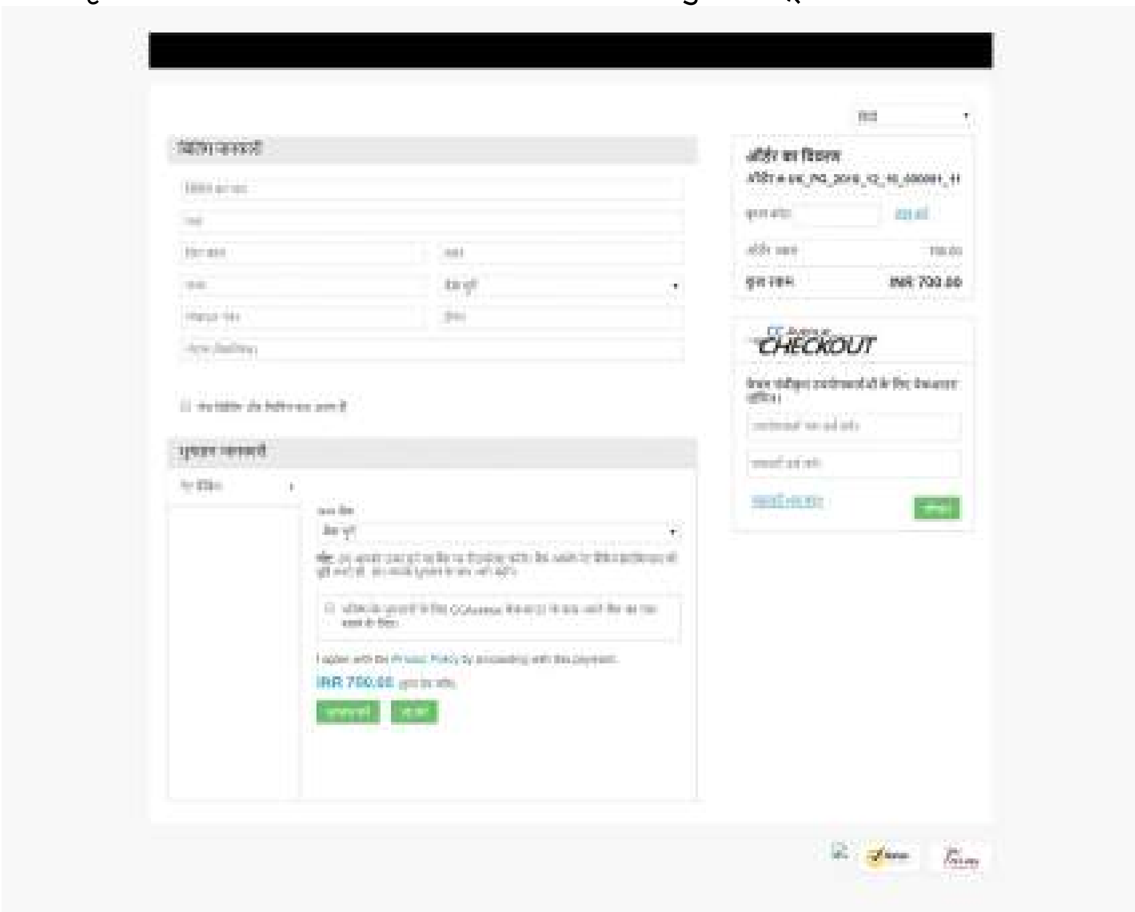

2.7.रसीद डाउनलोड करना

भुगतान किए जाने के बाद उपयोगकर्ता रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं

खोज करने के बाद अपना आवेदन खोलें और नीचे पृष्ठ पर उतरें:

डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से रसीद विकल्प चुनें और आप नीचे दिए गए प्रारूप में अपनी रसीद प्राप्त करेंगे:

	हल्द्वानी नगर निगम व्यापार लाइसेंस भुगतान रसीद	रसीद संख्या 01/2019-20/000143

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण

पुराना व्यापार लाइसेंस संख्या : UK-TL-2018-05-30-000154

आवेदन संख्या : UK-TL-2020-01-04-000257

रसीद संख्या : 01/2019-20/000143

वित्तीय वर्ष : 2019-20

भुगतान तिथि : 4/1/2020

व्यापार विवरण

व्यापार का नाम :	Q B&S	व्यापार की श्रेणी :	व्यापार
व्यापार का प्रकार :	देशी शराब की दुकान	अधिभोग प्रकार :	स्वामित्व

व्यापार स्थान का विवरण

घर / दरवाजा नं :	NA	भवन / कॉलोनी का नाम :	NA
सड़क का नाम :	NA	इलाका / मोहल्ला :	Hydel Gate Damuwadhunga N02 - Ward No. 1

स्वामित्व विवरण

मालिक का नाम :	Akhila	अभिभावक का नाम :	Vasanth

भुगतान योग्य राशि

व्यापार लाइसेंस शुल्क	दंड	छूट	तदर्थ दंड	तदर्थ छूट	कुल रकम
4000	NA	NA	1000	400	4600

भुगतान विवरण

भुगतान की गई कुल राशि :	4600	बकाया राशि :	0
भुगतान का प्रकार :	कैश	बैंक का नाम :	NA
ट्रांजेक्शन आईडी / चेक / डीडी नंबर :	haldwani8129141389	लेन - देन की तारीख :	4/1/2020
एम एस सी 5/ एम एस सी 2 रसीद संख्या :	NA	एम एस सी 5/ एम एस सी 2 रसीद तारीख :	NA

आयुक्त / ईओ

नोट

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

कृपया ध्यान दें: यदि यह नए प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन है, तो आवेदन का प्रकार नया दिखाई देगा अन्यथा यह नवीकरण के रूप में दिखाएगा |

2.7.प्रमाणपत्र डाउनलोड करना

भुगतान किए जाने के बाद प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं

खोज करने के बाद अपना आवेदन खोलें और नीचे पृष्ठ पर उतरें:

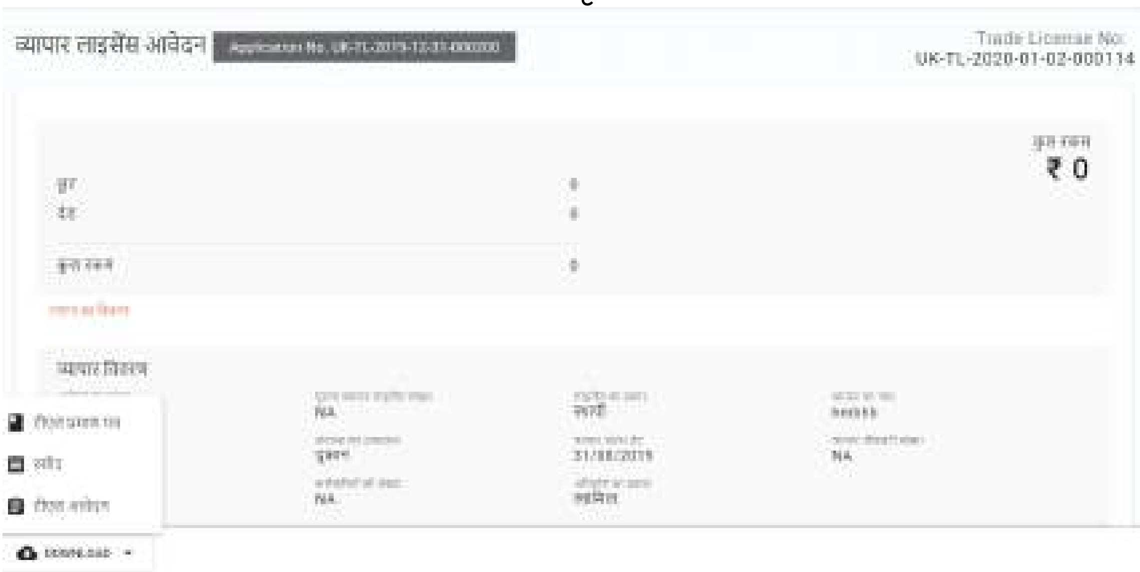

डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से टीएल प्रमाणपत्र विकल्प चुनें और आप नीचे दिए गए प्रारूप में अपना प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे:

नगर निगम देहरादून

पता : Near Doon Hospital, New road, District-Dehradun, Uttarakhand-248001

संपर्क करें : +91 (135) 2653572

वेबसाइट : http://nagarnigamdehradun.com/

ईमेल : nagar_nigam2008@yahoo.com

व्यापार लाइसेंस प्रमाणपत्र

व्यापार लाइसेंस संख्या:	UK-TL-2020-01-08-000136
पुराना लाइसेंस संख्या:	NA
आवेदन संख्या:	UK-TL-2020-01-06-000287
आवेदन का प्रकार:	नवीनीकरण
रसीद संख्या:	01/2019-20/000155
वित्तीय वर्ष:	2019-20
व्यापार का नाम:	asdfvgbvfds
व्यापार के मालिक का नाम:	Akhila
वयापार के मालिक की मोबाइल संख्या:	9999999994
अधिभोग प्रकार:	स्वामित्व
व्यापार का पता:	वीरगिरवाली - वार्ड नं १ (राजपुर), देहरादून
व्यापार का प्रकार:	फेरीवाला
व्यापार लाइसेंस शुल्क:	₹ 770
लाइसेंस जारी करने की तारीख:	08/01/2020
लाइसेंस की वैधता:	01/04/2019 से 31/03/2020

द्वारा स्वीकृत:TLApprover, नगर आयुक्त आयुक्त

यह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है, इसलिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

ह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है, इसलिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।यह लाइसेंस स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।यह ट्रेड लाइसेंस नगर निगम अधिनियम 1959 / नगर परिषद अधिनियम 1916 के तहत इस शर्त साथ जारी किया जाता है कि आवेदक संबंधित विभागों से प्रासंगिक एनओसी प्राप्त करेगा जैसे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / अग्निशमन कार्यालय / पुलिस विभाग / स्वास्थ्य विभाग / आबकारी विभाग / जीएसटी भाग / उपायुक्त (विस्फोटक अधिनियम के तहत) आदि जो भी लागू हो।नगर परिषद / निगम, किसी भी शर्त के उल्लंघन की परिस्थिति में कानून के अनुसार इस ट्रेड लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है।

कृपया ध्यान दें: यदि यह नए प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन है, तो आवेदन का प्रकार नया दिखाई देगा अन्यथा यह नवीकरण के रूप में दिखाएगा |

व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण

एक बार जब किसी उपयोगकर्ता को अपना व्यापार लाइसेंस नवीकरण करवाना होता है, तो नागरिक स्वयं ही अपने खाते के माध्यम से आवेदन कर सकता है। निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- सबसे पहले नागरिक अपने खाते में प्रवेश करता है।
- दूसरे नागरिक नीचे दिए गए स्क्रीन परमेरे आवेदन पर क्लिक करते हैं।

- नीचे दी गई नागरिक भूमि मेरे आवेदन स्क्रीन पर दिखाई देती है, जो उस नागरिक के आवेदन पर दिखाई देती है जिसे उसने अपने खाते से आवेदन किया है / भेजा है:

- नागरिक विवरण / नवीनीकरण अब देखें विकल्प पर क्लिक करता है, जिसे नीचे परिभाषित किया जा सकता है:

4.1 दृश्य विवरण: यदि नागरिक अपने पिछले भेजे गए आवेदन को संपादित करना चाहता है, तो नागरिक इस विकल्प को चुनता है और नीचे दिए गए चरणों का पालन करता है:

4.1.1 विकल्प देखने के विवरण पर क्लिक करने के बाद, हम नीचे दी गई स्क्रीन पर उतरते हैं, जिसमें से आवेदन खुलता है:

* यदि नागरिक उस एप्लिकेशन को संपादित / संशोधित करना चाहता है जो वह संशोधित नवीनीकरण बटन पर क्लिक करता है और पहले प्रस्तुत आवेदन को संपादित करता है और फिर से धारा 2.1 के अनुसार चरणों का पालन किया जाएगा, तो नागरिक एक क्लिक नवीनीकरण से विकल्प चुन सकता है।

- **संशोधित नवीनीकरण**: यह विकल्प नागरिक के लिए आवेदन पत्र में विवरण को संपादित करने के लिए आवेदन पत्र को खोलता है।
- **एक क्लिक नवीनीकरण**: इस विकल्प को चुना जा सकता है अगर नागरिक को आवेदन में कोई अन्य विवरण संपादित नहीं करना है

4,2 यह विकल्प संवाद बॉक्स के पॉपिंग की ओर जाता है जो फिर से उपयोगकर्ता के साथ पुष्टि करता है, यदि सब कुछ ठीक है तो उपयोगकर्ता हां पर क्लिक कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, यदि नहीं तो नहीं और संशोधित और नवीनीकरण पर क्लिक करें।

उत्तराखंड
उपयोगकर्ता पुस्तिका
व्यापार लाइसेंस
उत्तराखण्ड राज्य
Powered By egov FOUNDATION

प्रस्तावना

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य व्यापार लाइसेंस प्रणाली (व्यापार लाइसेंस) के संचालन में कर्मचारियों की सहायता करना है। यह कर्मचारियों को एक डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसके द्वारा व्यापार लाइसेंस ऐप्लकेशन प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न कार्य किया जा सकता है।

व्यापार लाइसेंस कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है:

क्रिया	विवरण
आरंभ	यह क्रिया नागरिक और पटल कर्मचारी के लिए आवेदन शुरू करेगा।
जमा करना	यह क्रिया नागरिक और पटल कर्मचारी के आवेदन को शुरू करेगा और उसे वर्कफ़्लो के अगले चरण के लिए उपलब्ध कराएगा।
सत्यापित करना और अग्रेषित करना	यह क्रिया आवेदन को वर्कफ़्लो प्रक्रिया के अगले अवस्था में ले जाएगा और वर्कफ़्लो में (यदि आवश्यक हो) अगले उपयोगकर्ता को कार्य भी सौंपेगा।
भुगतान करना	यह क्रिया आवेदन शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा।
मंजूर करना	यह क्रिया अनुप्रयोग वर्कफ़्लो का अंतिम चरण होगा जो आवेदन को मंजूरी देगा।
अस्वीकार करना	यह क्रिया आवेदन को अस्वीकार कर देगी।अस्वीकृत आवेदन पत्र को आगे संसाधित नहीं किया जा सकता है। नागरिक उस आवेदन के साथ फिर से आवेदन नहीं कर सकते।
वापस भेजना	यह क्रिया आवेदन को तत्काल उसकी पिछली स्थिति में वापस भेज देगी।
संपादित करना	यह क्रिया उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगी: ● किसी भी चरण में व्यापार लाइसेंस एप्लिकेशन को संपादित करने, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि को सुधारने या नागरिकों द्वारा प्रदान किए गए विवरण को संशोधित करने के लिए। ● विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को इसे संपादित करने का अधिकार दिया जा सकता है। ● उपयोगकर्ता स्वामी, व्यापार और स्थान जैसी जानकारी को संपादित कर सकते हैं। ● आवेदन को संपादित करने पर, नागरिक को एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा।

(**अनुलेख**:ये सभी क्रियाएँ और नीचे उल्लिखित कर्मचारी भूमिकाएँ विन्यास के योग्य हैं और विभाग के पास यह विकल्प होता है कि वे किस भूमिकाओं / क्रियाओं को अपने व्यापार लाइसेंस एप्लिकेशन प्रक्रिया के लिए चुनना चाहते हैं।

व्यापार लाइसेंस में निम्नलिखित कर्मचारी भूमिकाएँ हैं:

भूमिका	अनुमन्य कार्य	विवरण
पटल कर्मचारी	• आवेदन जमा करना • भुगतान जमा करना • भुगतान रसीद डाउनलोड करना • व्यापार लाइसेंस प्रमाण पत्र डाउनलोड करना	• व्यापार लाइसेंस काउंटर कर्मचारी नागरिक की ओर से आवेदन कर सकता है और जमा कर सकता है। • इसके अलावा, वह व्यापार लाइसेंस फीस जमा कर सकता/सकती है और इसे सिस्टम में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए रिकॉर्ड कर सकता/सकती है।
लाइसेंसिंग क्लर्क	• सत्यापित करना और अग्रेषित करना • अस्वीकार करना	लाइसेंसिंग क्लर्क एक कर्मचारी है दस्तावेजों का सत्यापन कौन करता है और जानकारी (यदि है जानकारी / दस्तावेज उपलब्ध कराए गए आवेदक द्वारा फार्म सही है) व्यापार लाइसेंस आवेदन जमा करते समय प्रपत्र।
लाइसेंसिंग दस्तावेज़ सत्यापनकर्ता	• सत्यापित करें और अग्रेषित करें • वापस भेजें • अस्वीकार	• लाइसेंसिंग दस्तावेज़ सत्यापनकर्ता एक है कर्मचारी जो मैदान में जाता है (यानी व्यापार का स्थान) और जानकारी को भौतिक रूप से सत्यापित करता है आवेदक द्वारा प्रदान किया गया है सही है और यह भी देखता है कि क्या सुरक्षा है व्यापार के बाद सावधानियां बरती जाती हैं व्यापारों को चलाने के लिए मालिक। • यदि निरीक्षण में पाया गया संतोषजनक, वह आगे कर सकते हैं अनुमोदन के लिए एक आवेदन या कमी पाए जाने पर अस्वीकार करें।

लाइसेंसिंग अधिकारी	• भुगतान करें • वापस भेजें • अस्वीकार • रद्द करें	• लाइसेंसिंग अधिकारी एक कर्मचारी है जो अंतिम प्राधिकरण को जाता है आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करें। • यदि अधिकारी को आवेदन मिला संतोषजनक हो, वह / वह कर सकते हैं आवेदन को स्वीकार करें या यदि अस्वीकार करें कमी पाई गई।

यह दस्तावेज़ उपयोगकर्ता सहायता के लिए स्क्रीन-शॉट के साथ व्यापार लाइसेंस की विभिन्न विशेषताओं को शामिल करता है और हर सुविधा को परिभाषित किया गया है। यदि आपको और सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया contact@egovernments.org पर ईमेल करें।

1.उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल के कार्य

आवेदन के सामान्य कार्य निम्नलिखित हैं:

1.1आवेदन में लॉगिन करें

लॉगिन करने के लिए, कृपया निम्न लिंक पर जाएं:
https://nagarsewa.uk.gov.in/employee

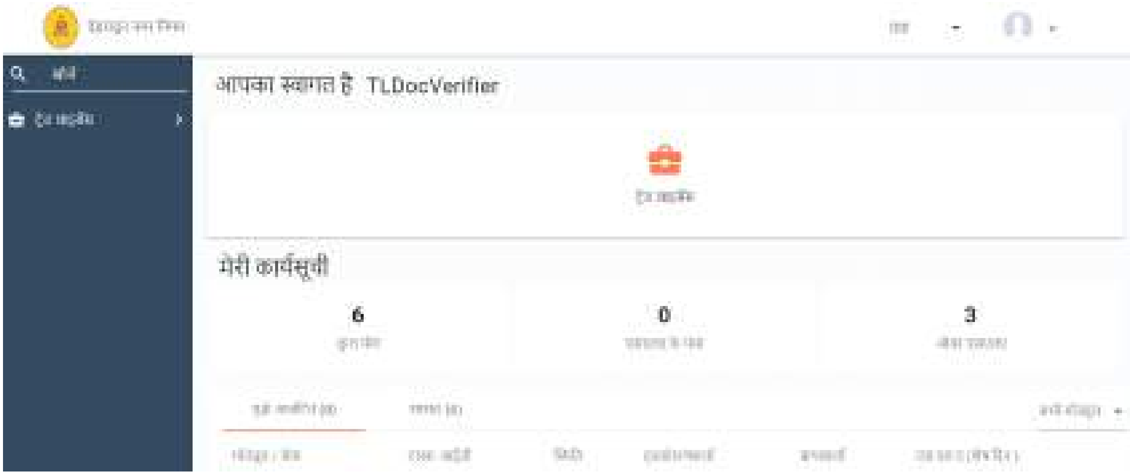

1.2. प्रोफ़ाइल का संपादन

अपनी प्रोफ़ाइल को संपादित करने के लिए नीचे दिखाए गए चरणों का पालन करें। आप ऐसा कर सकते हैं:

- प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपलोड करें
- मोबाइल नंबर को कैप्चर / अपडेट करें
- ईमेल आईडी कैप्चर / अपडेट करें

1.3.उपयोगी नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

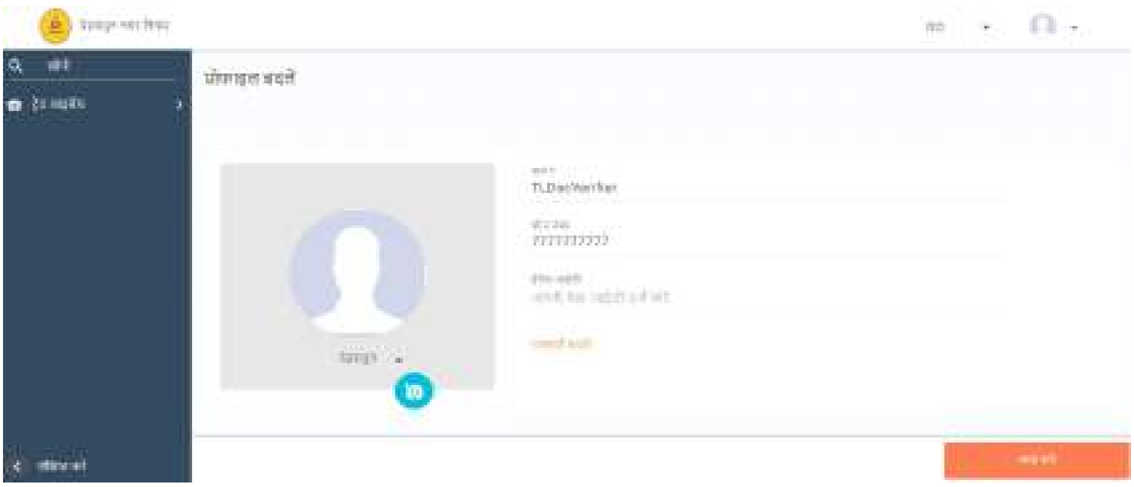

1.4.उपयोग प्रोफ़ाइल फोटो

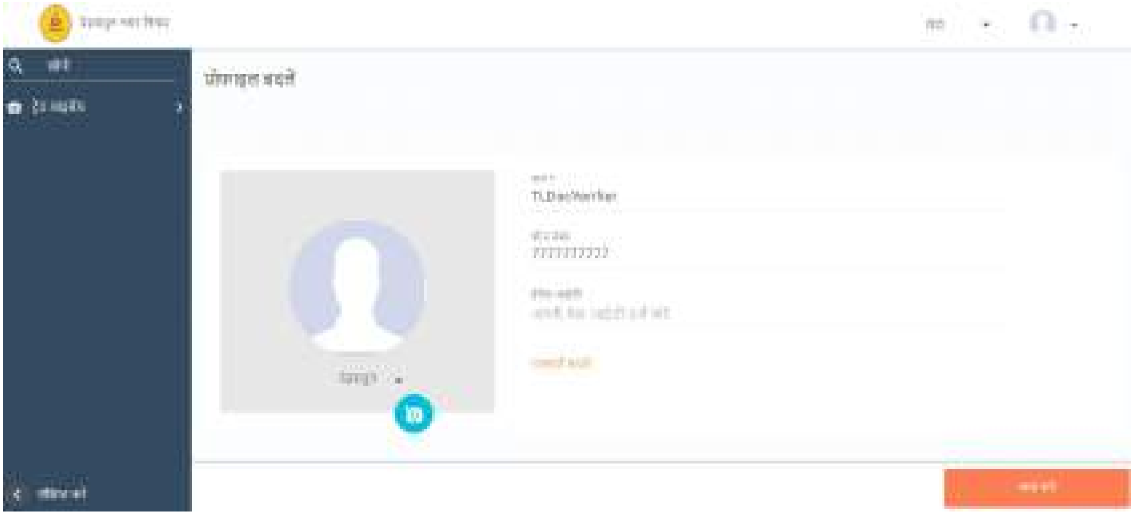

2.स्टेज- I: नए/ नवीकरण व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, काउंटर कर्मचारी नागरिक की ओर से व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन फाइल कर सकता है।

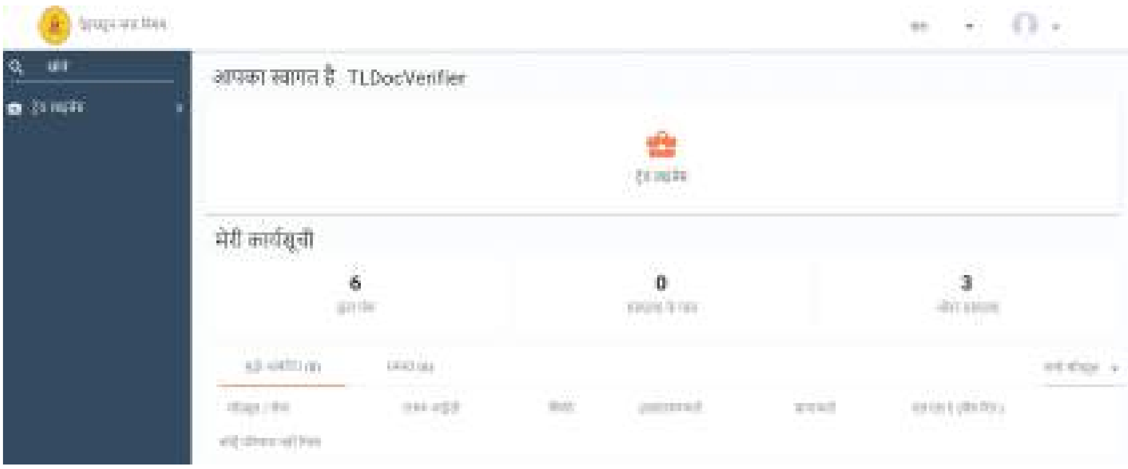

व्यापार लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy

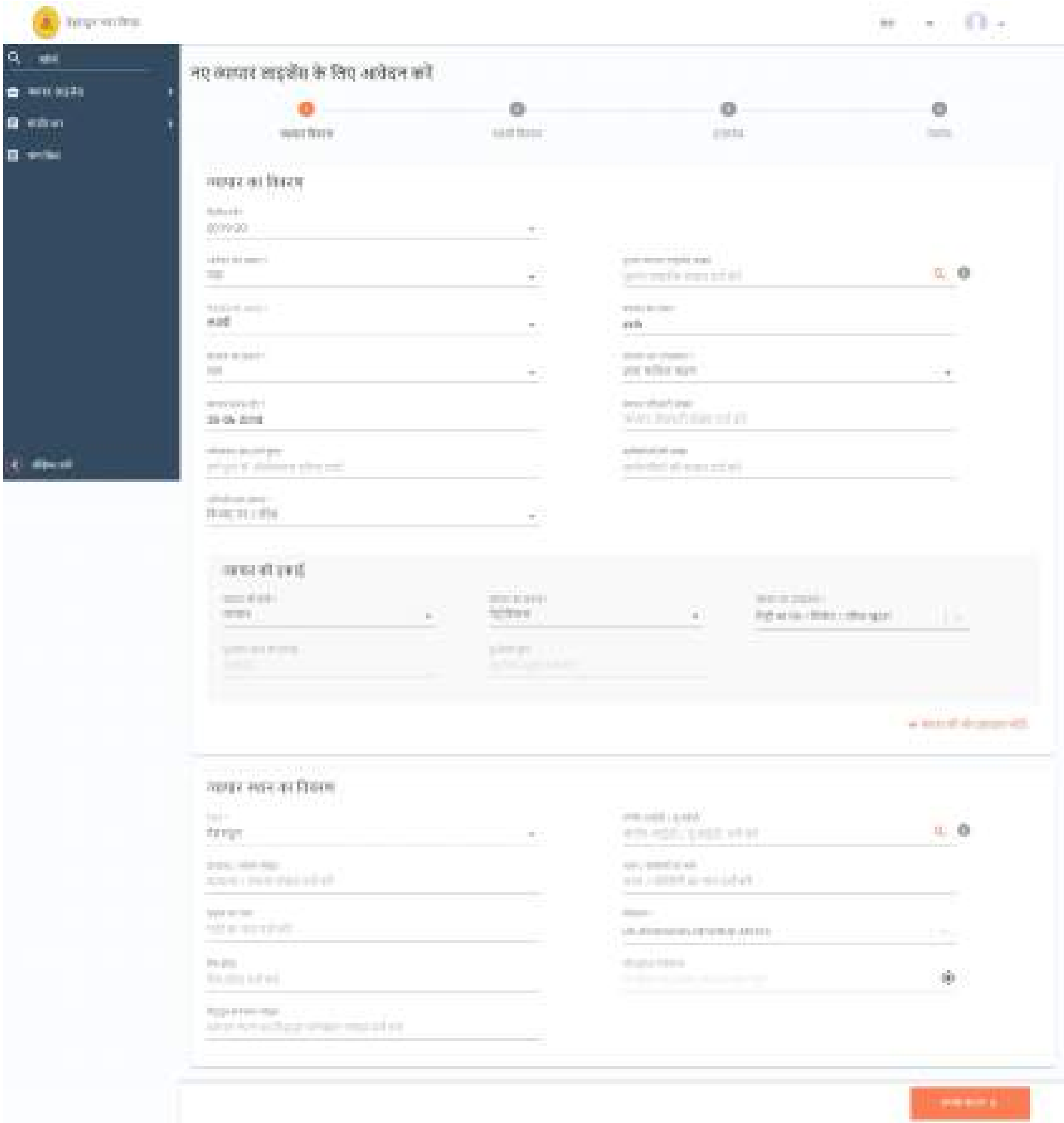
नए व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करें
व्यापार का विवरण
व्यापार स्थान का विवरण

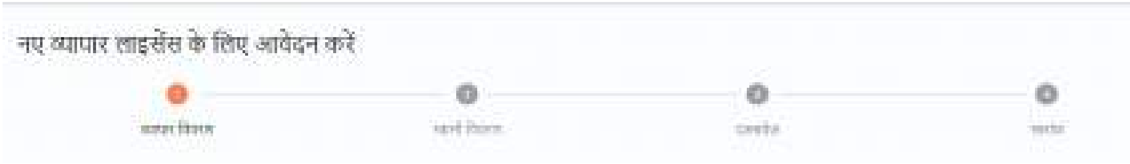

2.1.व्यापार विवरण

व्यापार विस्तार उप-भाग के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार सब-सेक्शन में निम्नलिखित क्षेत्र हैं:

वित्तीय वर्ष	उस वित्तीय वर्ष का चयन करें जिसके लिए लाइसेंस लागू है।
आवेदन का प्रकार	आवेदन प्रकार का चयन करें: ● नया ● नवीनीकरण ((यदि यह नवीनीकरण का आवेदन है तो आवेदन का प्रकार में नवीनीकरण का चयन करें ।)
पुराना एप्लीकेशन नंबर	पुराना एप्लिकेशन नंबर
व्यापार का नाम *	व्यापार का नाम दर्ज करें
संरचना प्रकार *	ड्रॉप-डाउन से संरचना प्रकार का चयन करें। यह हो सकता है: ● अचल ● चल
संरचना उप प्रकार *	ड्रॉप-डाउन से संरचना उप प्रकार का चयन करें। यह हो सकता है: ● शेड ● खुली हुई भूमि आदि

व्यापार कमिशन डेट *	वह तिथि निर्दिष्ट करता है जिससे व्यापार होता है संचालन। यहां नागरिक भविष्य के लिए इनपुट भी कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष के भीतर तारीख।
व्यापार जीएसटी नंबर *	व्यापार से संबंधित जीएसटी नहीं इनपुट की आवश्यकता है।
ऑपरेशन क्षेत्र (वर्ग फीट)	को परिचालन क्षेत्र के इनपुट की आवश्यकता है परिसर / संपत्ति जहां व्यापार संचालित होता है।
कर्मचारियों की संख्या	व्यापार में कार्यरत कर्मचारियों में से कोई नहीं लाइसेंस लागू है।
व्यवसाय प्रकार *	उपयुक्त व्यवसाय प्रकार से चुनें ड्रॉप डाउन

अनुलेख: जब उपयोगकर्ता व्यापार के लेबल पर क्लिक करता है, तो लेबल का रंग लाल में बदल जाता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि उस लेबल पर कार्रवाई की गई है। उदाहरण नीचे दिखाया गया है।

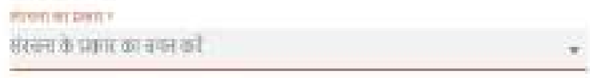

2.2.व्यापार यूनिट

व्यापार इकाई उप-खंड के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार यूनिट-भाग में निम्नलिखित क्षेत्र हैं

व्यापार श्रेणी *	ड्रॉप डाउन से व्यापार से संबंधित उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
व्यापार प्रकार *	संबंधित व्यापार प्रकार का चयन करें नीचे से व्यापार के साथ। यह क्षेत्र व्यापार श्रेणी पर निर्भर है।
व्यापार उप प्रकार *	व्यापार उप प्रकार इस पर निर्भर है चयनित व्यापार श्रेणी और व्यापार प्रकार। सूची उपर्युक्त चयनित के अनुसार है खेत।

*अनिवार्य क्षेत्र

2.3 व्यापार स्थान का विवरण

व्यापार स्थान विवरण अनुभाग के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार स्थान विवरण अनुभाग में निम्नलिखित क्षेत्र हैं:

शहर *	शहर का नाम दर्ज करें
संपत्ति आईडी / यूआईडी	उचित प्रॉपर्टी आईडी / यूआईडी डालें
दरवाजा / मकान नं	उपयुक्त प्रॉपर्टी आईडी / यूआईडी दर्ज करने पर ऑटो पॉपुलेट होता है
भवन / कॉलोनी का नाम	उपयुक्त संपत्ति दर्ज करने पर ऑटो पॉपुलेट करता है आईडी / यूआईडी
सड़क का नाम	उपयुक्त संपत्ति दर्ज करने पर ऑटो पॉपुलेट करता है आईडी / यूआईडी
मोहल्ला *	उपयुक्त वार्ड और इलाके का नाम चुनें
पिन कोड	उपयुक्त पिनकोड दर्ज करें
जीआईएस निर्देशांक	मानचित्र से स्थान का चयन करें
बिजली कनेक्शन	संपत्ति के लिए उचित बिजली कनेक्शन नंबर दर्ज करे

3. व्यापार स्वामी विवरण

कर्मचारी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से पूछा जाएगा कि कर्मचारी को लाइसेंस आवेदन दाखिल करने के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रदर्शित स्क्रीन नीचे दी गई है:

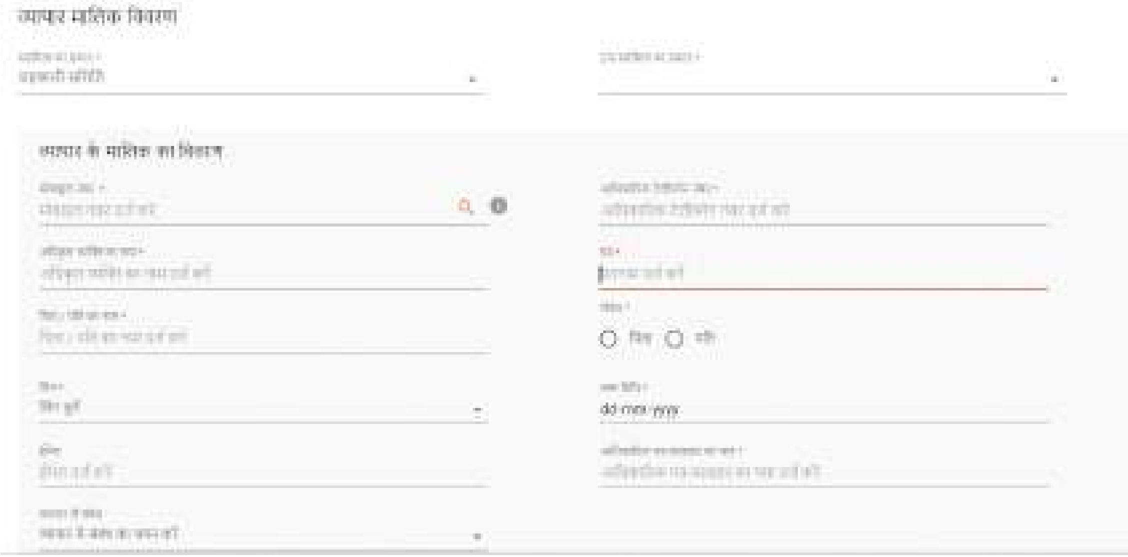

व्यापार के स्वामी के विवरण निम्नलिखित हैं:

3.1.व्यापार स्वामी विवरण

व्यापार स्वामी विवरण उप-भाग के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार स्वामी डिटेल्स सब्सक्रिप्शन में फ़ील्ड निम्नलिखित हैं:

स्वामित्व के प्रकार*	संबंधित स्वामित्व के उपयुक्त प्रकार का चयन करें व्यापार जिसके लिए लाइसेंस लागू किया जा रहा है।
उप-स्वामित्व का प्रकार *	उप-स्वामित्व के उपयुक्त प्रकार का चयन करें उस व्यापार से संबंधित है जिसके लिए लाइसेंस दिया जा रहा है आवेदन किया है।

*अनिवार्य क्षेत्र

3.2. स्वामी सूचना

स्वामी सूचना उप-भाग के लिए स्क्रीन निम्नलिखित है:

व्यापार स्वामी डिटेल्स सब्सक्रिप्शन में फ़ील्ड निम्नलिखित हैं:

मोबाइल नंबर*	प्राथमिक स्वामी का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
नाम *	स्वामी का नाम दर्ज करें
पिता / पति का नाम *	पिता / पति का नाम या तो दर्ज करें मालिक के लिए लागू है।
संबंध	विकल्प से संबंध चुनें: पिता या पति
लिंग	ड्रॉप-डाउन बॉक्स से लिंग का चयन करें।
जन्म की तारीख*	स्वामी की जन्म तिथि दर्ज करें।
ईमेल	व्यापार स्वामी ईमेल आईडी दर्ज करें
पैन नं	मालिक का पैन नंबर दर्ज करें।
पत्राचार का पता*	उस पते को दर्ज करें जिस पर स्वामी पहुँचा जा सकता है।
संबंध प्रकार	ड्रॉप डाउन से रिलेशन टाइप चुनें

*अनिवार्य क्षेत्र

- यदि कर्मचारी ने कई मालिकों का चयन किया है, तो वह कई मालिकों पर क्लिक करके कई मालिक जोड़ सकता है।

- सभी विवरण भर जाने के बाद, अगला चरण पर क्लिक करें।

4.दस्तावेज अपलोड करना

- आवश्यक दस्तावेज़ प्रत्येक व्यापार उप-प्रकार के लिए अलग-अलग होंगे, यह निर्भर करता है व्यापार सब-टाइप आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
- सभी विवरण भर जाने के बाद, अगला चरण पर क्लिक करें

* **अनुलेख:** केवल JPEG और PDF फ़ाइलों को अपलोड करने की अनुमति है, जिनका अधिकतम आकार होना चाहिए 6MB से कम हो।

5. भरे हुए आवेदन पत्र का सारांश

एक बार काउंटर कर्मचारी ने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए हैं, अगला चरण भरे हुए आवेदन पत्र का सारांश है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

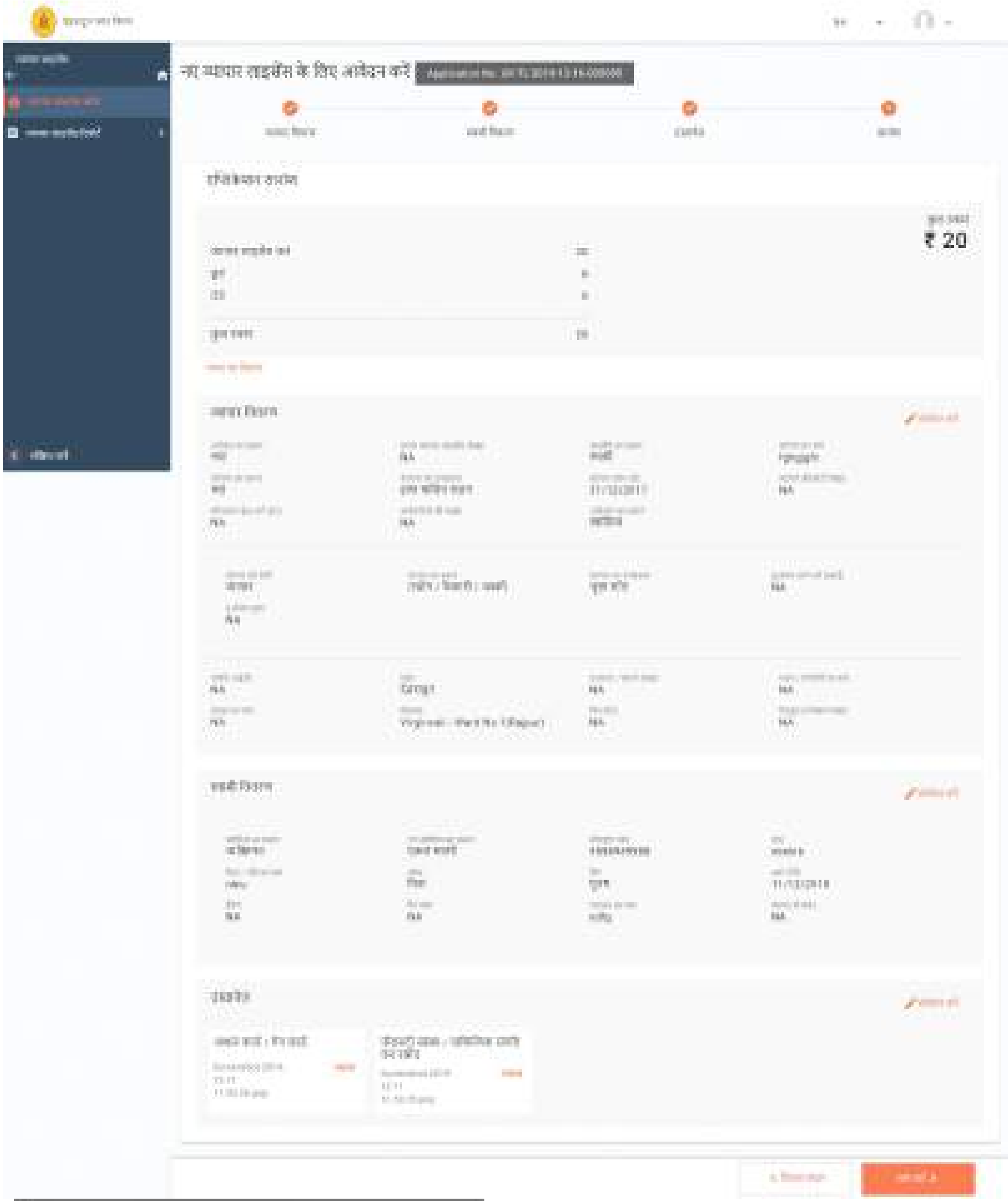

6. आवेदन प्रस्तुत करना

कर्मचारी द्वारा सबमिट पर क्लिक करने के बाद, निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होती है:

7. स्टेज- II: अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करना

- एक बार आवेदन दायर करने के बाद, आवेदन का अगला चरण भरे हुए आवेदन से जुड़े दस्तावेज को सत्यापित करना है।

- अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए लाइसेंसिंग क्लर्क जिम्मेदार है। जब लाइसेंसिंग क्लर्क लॉग इन करता है तो निम्न स्क्रीन दिखाई देती है:

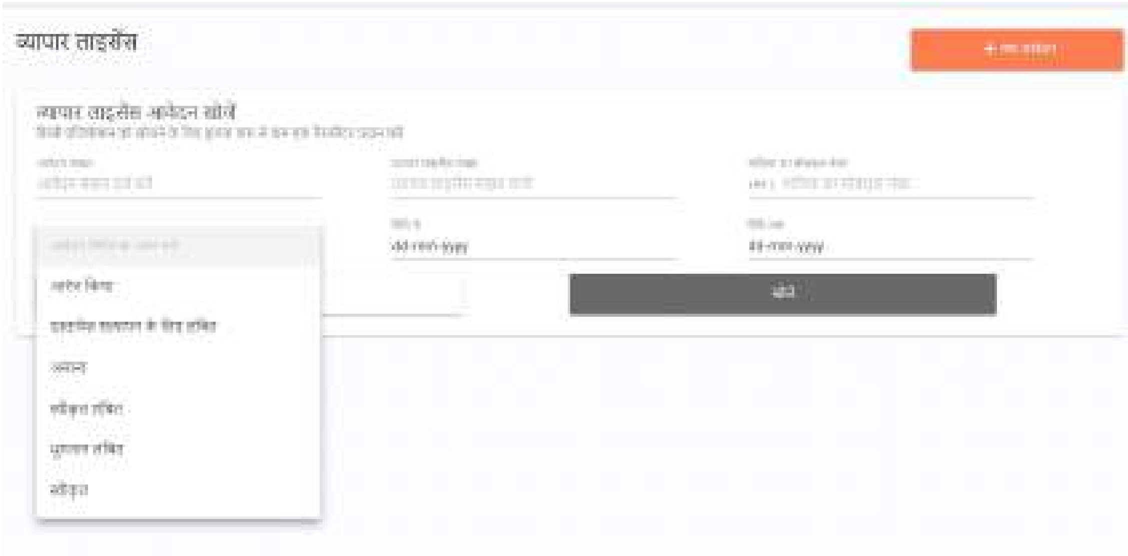
व्यापार लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy

ट्रेड लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
11-12-2019
11-12-2019

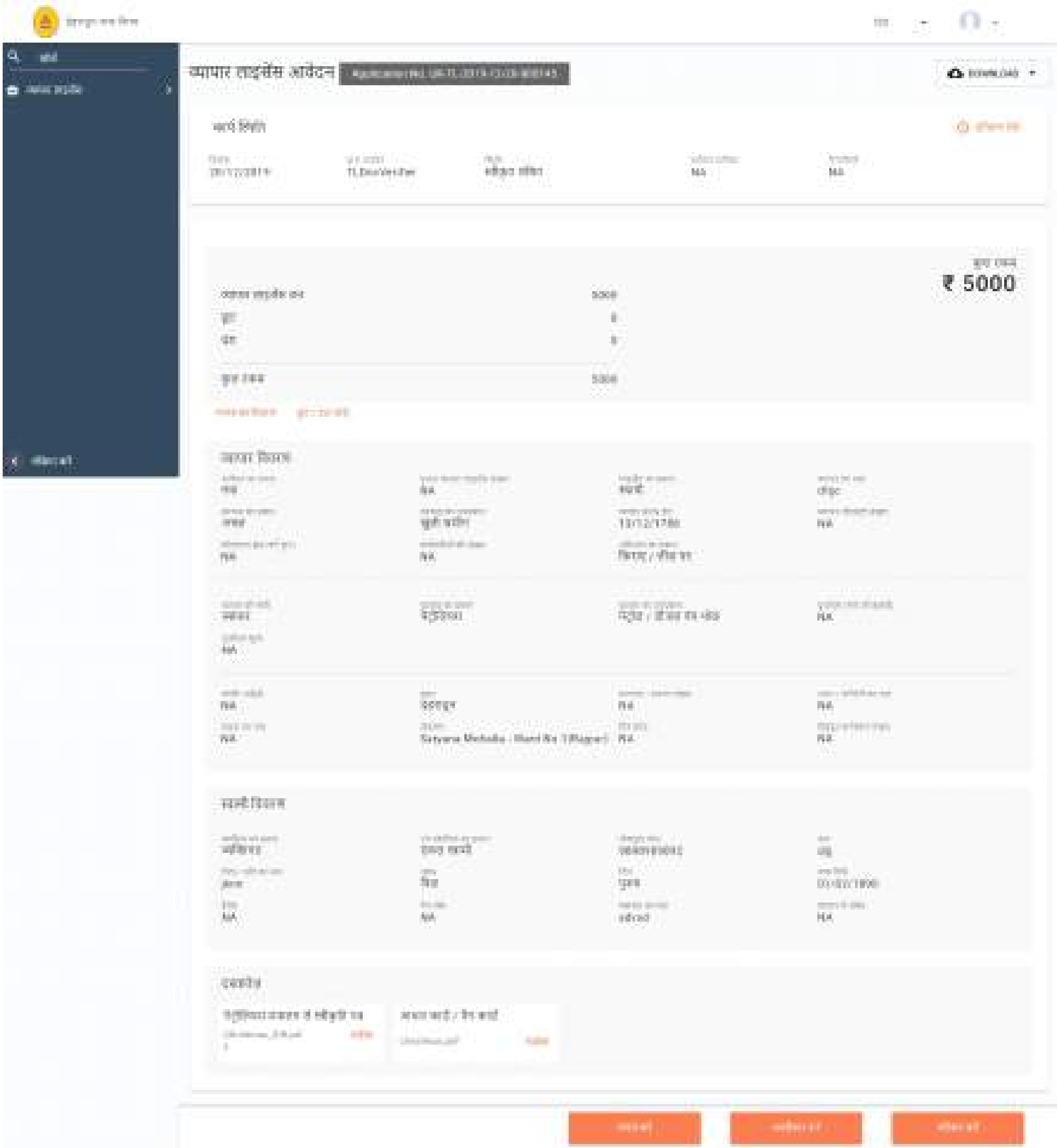
व्यापार लाइसेंस आवेदन
₹ 5000

इतिहास बटन देखें

छूट/दंड छोड़ें

दस्तावेज़ सत्यापनकर्ता को किसी भी विसंगतियों के मामले में जुर्माना जोड़ने या राशि पर छूट देने का विकल्प मिलता है।

₹ 5000
छूट 0
दंड 0
कुल रकम 5000

तदर्थ दंड / छूट जोड़ें
तदर्थ दंड
तदर्थ दंड राशि
प्रवेश शुल्क राशि दर्ज करें
दंड का कारण
दंड का चयन करें
टिप्पणियाँ दर्ज करें
टिप्पणियाँ दर्ज करें
रद्द करना
जोड़ें

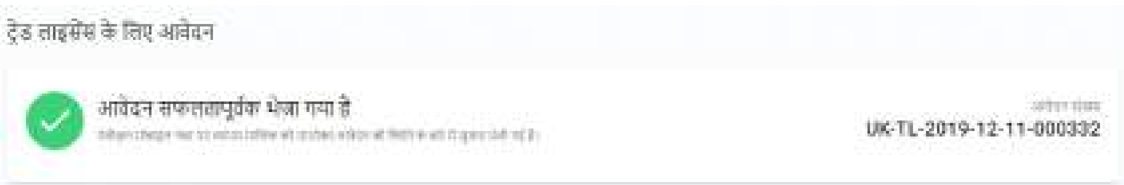

8. स्टेज- III: व्यापार लाइसेंस को मंजूरी

- आवेदन के सत्यापित होने के बाद, आवेदन का अगला चरण है लागू व्यापार लाइसेंस को स्वीकार / अस्वीकार करें।
- लाइसेंसिंग अधिकारी दायर को मंजूरी देने / खारिज करने के लिए जिम्मेदार है व्यापार लाइसेंस आवेदन। लाइसेंस के बाद निम्न स्क्रीन दिखाई देती है इंस्पेक्टर लॉग इन:

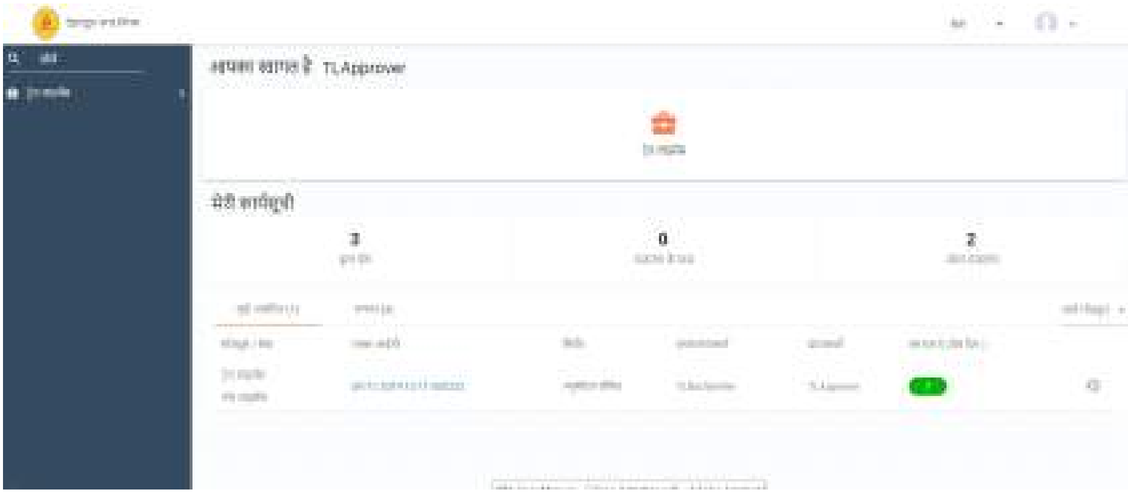

ट्रेड लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy
खोजें

ट्रेड लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy
खोजें

ट्रेड लाइसेंस
व्यापार लाइसेंस आवेदन खोजें
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy
खोजें

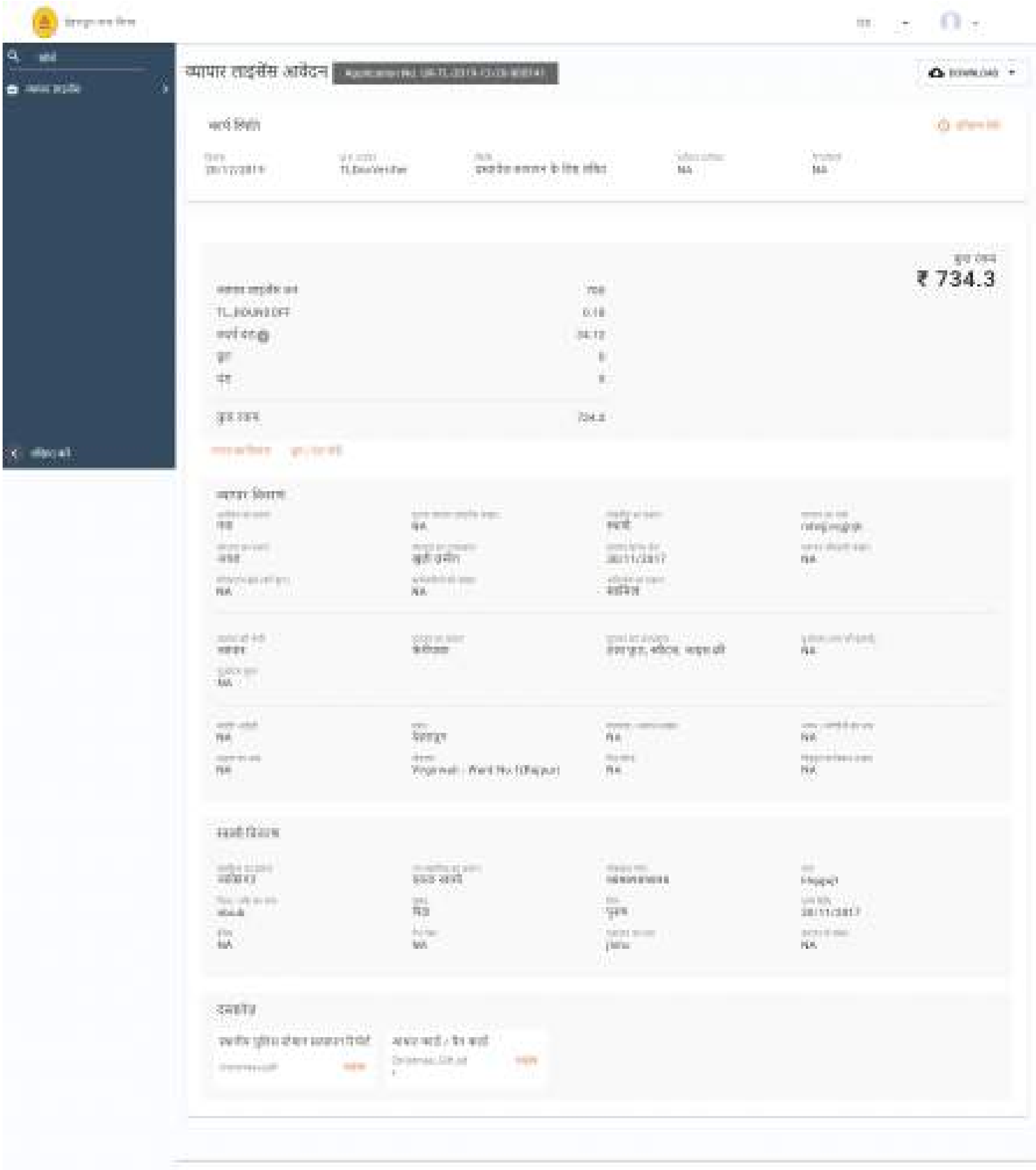

7.1 इतिहास देखें

दृश्य इतिहास सभी कॉन्फ़िगर की गई भूमिकाओं में एप्लिकेशन की समयरेखा का वर्णन करता है।

7.2 छूट/दंड जोड़े

दस्तावेज़ सत्यापनकर्ता को किसी भी विसंगतियों के मामले में जुर्माना जोड़ने या राशि पर छूट देने का विकल्प मिलता है।

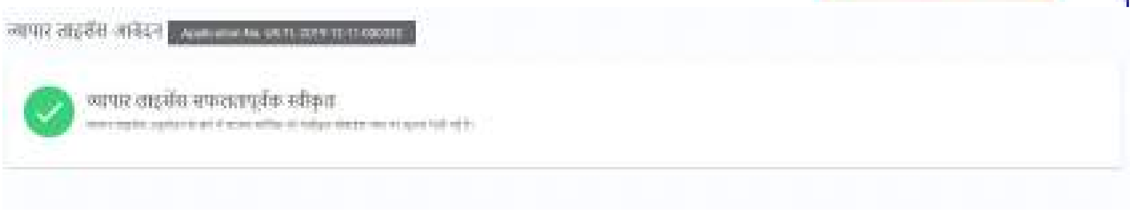

9. स्टेज- IV: भुगतान और व्यापार लाइसेंस

- आवेदन के स्वीकृत होने के बाद, आवेदन का अगला चरण है लागू व्यापार लाइसेंस का भुगतान एकत्र करें और नागरिक को व्यापार लाइसेंस जारी करें,
- काउंटर एम्प्लॉई व्यापार लाइसेंस शुल्क जमा करने के लिए जिम्मेदार है।

निम्न स्क्रीन प्रकट होती है, जब काउंटर कर्मचारी लॉग इन करता है:

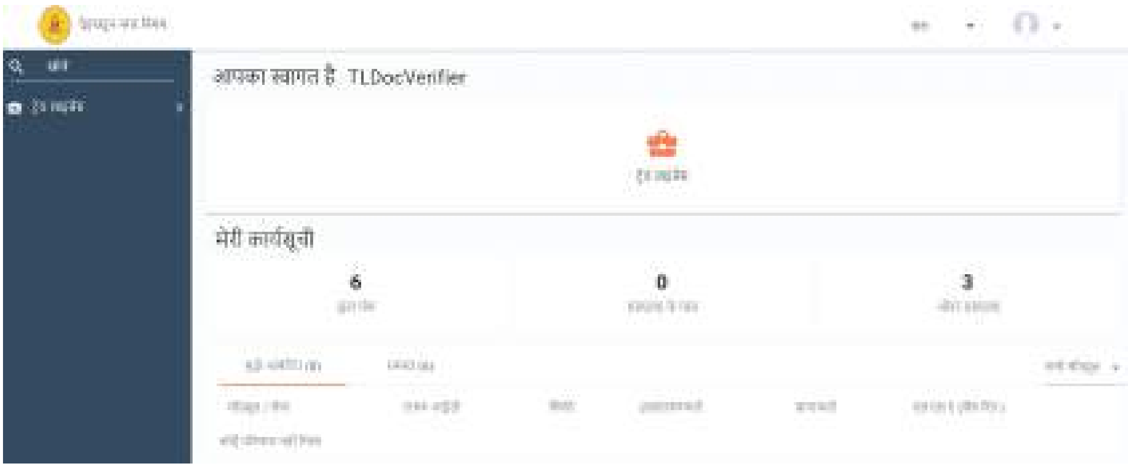
आपका स्वागत है TLDocVerifier
मेरी कार्यसूची
6
0
3

व्यापार लाइसेंस

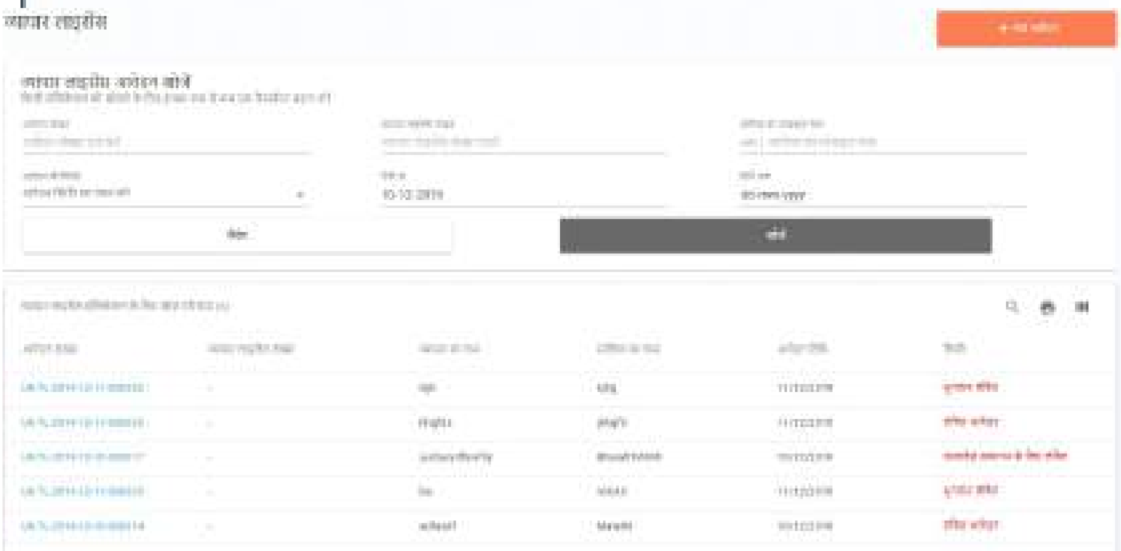
व्यापार लाइसेंस
10-12-2019

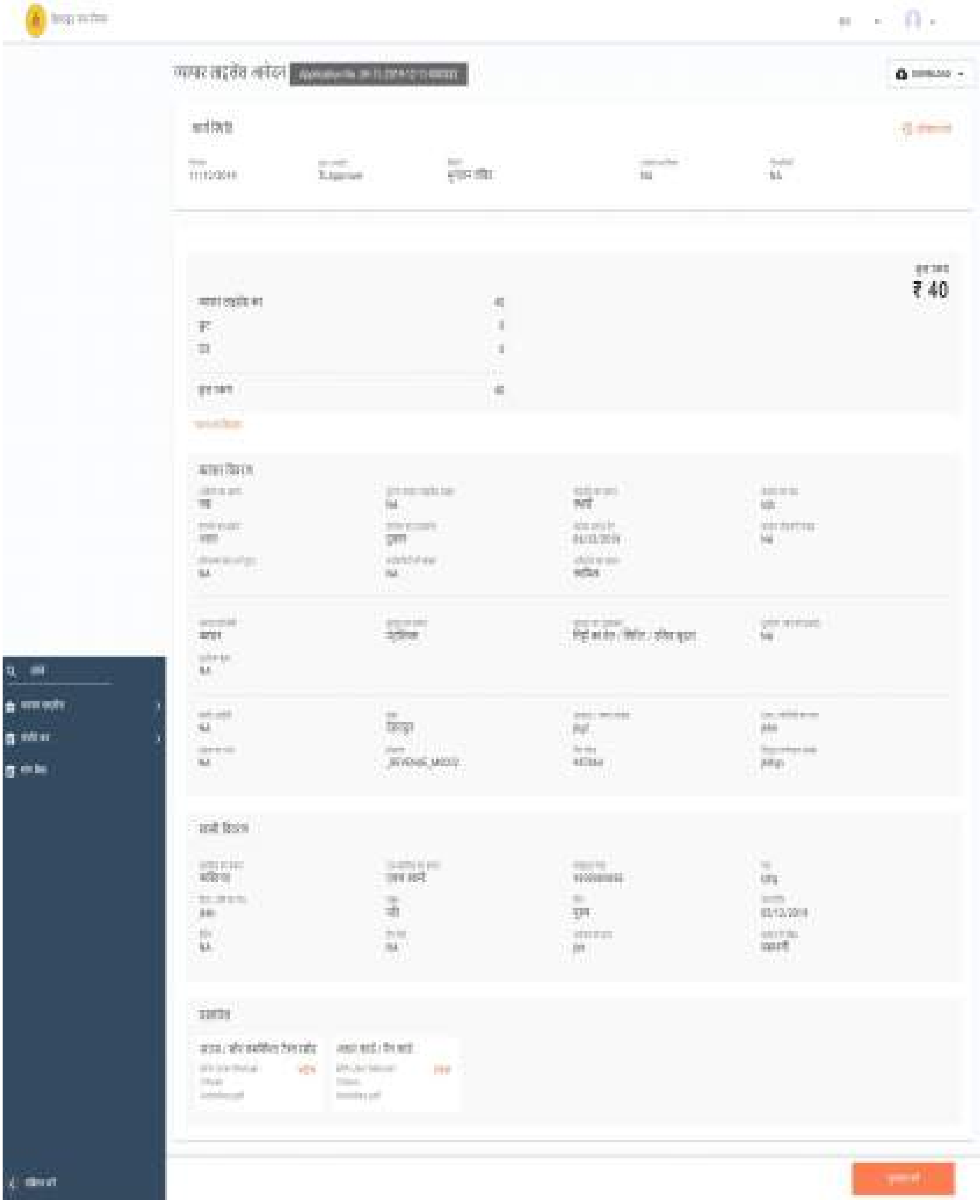
₹ 40

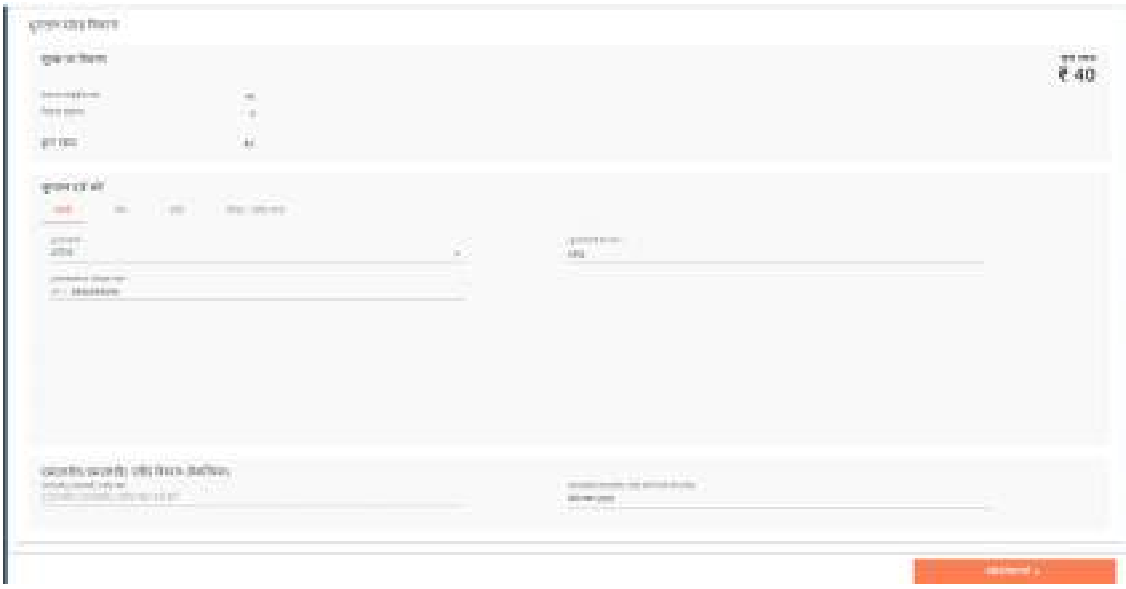

10. स्टेज- IV: रसीद डाउनलोड करना

कर संग्रह विवरण
भुगतान सफलतापूर्वक एकत्र किया गया है।
12/2019-20/000054

	हल्द्वानी नगर निगम व्यापार लाइसेंस भुगतान रसीद	रसीद संख्या 01/2019-20/000143

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण
पुराना व्यापार लाइसेंस संख्या : UK-TL-2018-05-30-000154

आवेदन संख्या : UK-TL-2020-01-04-000257
रसीद संख्या : 01/2019-20/000143

वित्तीय वर्ष : 2019-20
भुगतान तिथि : 4/1/2020

व्यापार विवरण

व्यापार का नाम :	Q B&S	व्यापार की श्रेणी :	व्यापार
व्यापार का प्रकार :	देशी शराब की दुकान	अधिभोग प्रकार :	स्थापित

व्यापार स्थान का विवरण

घर / दरवाजा नं :	NA	भवन / कॉलोनी का नाम :	NA
सड़क का नाम :	NA	इलाका / मोहल्ला :	Hydel Gate Damuwadhunga N02 - Ward No. 1

स्वामित्व विवरण

मालिक का नाम :	Akhila	अभिभावक का नाम :	Vasanth

भुगतान योग्य राशि

व्यापार लाइसेंस शुल्क	दंड	छूट	तदर्थ दंड	तदर्थ छूट	कुल रकम
4000	NA	NA	1000	400	4600

भुगतान विवरण

भुगतान की गई कुल राशि :	4600	बकाया राशि :	0
भुगतान का प्रकार :	कैश	बैंक का नाम :	NA
ट्रांजेक्शन आईडी / चेक / डीडी नंबर :	haldwani8129141389	लेन - देन की तारीख :	4/1/2020
एम एस बी 5/ एम एस बी 2 रसीद संख्या :	NA	एम एस बी 5/ एम एस बी 2 रसीद तारीख :	NA

आयुक्त / ईओ

नोट
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

कृपया ध्यान दें: यदि यह नए प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन है, तो आवेदन का प्रकार नया दिखाई देगा अन्यथा यह नवीकरण के रूप में दिखाएगा |

11. स्टेज- V: प्रमाणपत्र डाउनलोड करना

प्रमाण पत्र की खोज करने के लिए स्क्रीन पर आवेदन संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।

लाइसेंस नीचे सूचीबद्ध किया जाएगा और आवेदन संख्या पर क्लिक करें।

अगली स्क्रीन पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और टीएल प्रमाण पत्र चुनें

नगर निगम देहरादून

पता : Near Doon Hospital, New road, District-Dehradun, Uttarakhand-248001

संपर्क करें : +91 (135) 2653572

वेबसाइट : http://nagarnigamdehradun.com/

ईमेल : nagar_nigam2008@yahoo.com

व्यापार लाइसेंस प्रमाणपत्र

व्यापार लाइसेंस संख्या:	UK-TL-2020-01-08-000136
पुराना लाइसेंस संख्या:	NA
आवेदन संख्या:	UK-TL-2020-01-06-000287
आवेदन का प्रकार:	नवीनीकरण
रसीद संख्या:	01/2019-20/000155
वित्तीय वर्ष:	2019-20
व्यापार का नाम:	asdfvgbvfds
व्यापार के मालिक का नाम:	Akhila
वयापार के मालिक की मोबाइल संख्या:	9999999994
अधिभोग प्रकार:	स्वामित्व
व्यापार का पता:	वीरगिरवाली - वार्ड नं १ (राजपुर), देहरादून
व्यापार का प्रकार:	फेरीवाला
व्यापार लाइसेंस शुल्क:	₹ 770
लाइसेंस जारी करने की तारीख:	08/01/2020
लाइसेंस की वैधता:	01/04/2019 से 31/03/2020

द्वारा स्वीकृत:TLApprover, नगर आयुक्त आयुक्त

यह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है, इसलिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

ह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज है, इसलिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।यह लाइसेंस स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।यह ट्रेड लाइसेंस नगर निगम अधिनियम 1959 / नगर परिषद अधिनियम 1916 के तहत इस शर्त साथ जारी किया जाता है कि आवेदक संबंधित विभागों से प्रासंगिक एनओसी प्राप्त करेगा जैसे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / अग्निशमन कार्यालय / पुलिस विभाग / स्वास्थ्य विभाग / आबकारी विभाग / जीएसटी भाग / उपायुक्त (विस्फोटक अधिनियम के तहत) आदि जो भी लागू हो।नगर परिषद / निगम किसी भी शर्त के उल्लंघन की परिस्थिति में कानून के अनुसार इस ट्रेड लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है।

कृपया ध्यान दें: यदि यह नए प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन है, तो आवेदन का प्रकार नया दिखाई देगा अन्यथा यह नवीकरण के रूप में दिखाएगा |

12. ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण

ट्रेड लाइसेंस जो पिछले वर्षों में प्राप्त किए गए हैं, उन्हें नए सिरे से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और साथ ही आगे की समय अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। यह नीचे दिए गए तरीकों से किया जा सकता है:

12.1 एप्लिकेशन / लाइसेंस नंबर खोजकर

- नागरिक पिछले लाइसेंस नंबर के साथ काउंटर कर्मचारी के पास आता है।
- काउंटर कर्मचारी तब नीचे स्क्रीन पर लाइसेंस खोजता है और खोज हिट करता है:

खोज विकल्प को हिट करने के बाद काउंटर कर्मचारी लाइसेंस का चयन करता है और नीचे की स्क्रीन खुलती है:

1. संपादित करें: यह उपयोगकर्ता को नवीनीकरण के लिए एप्लिकेशन को संपादित करने के लिए प्रेरित करेगा उसी तरह से उपयोगकर्ता ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किया था या 2 डी चरण (चरण 1) से चरणों का पालन कर सकता है।

2. नवीनीकरण के लिए जमा करें: इस विकल्प से सबमिशन हो जाएगा जो किसी भी स्थिति में होगा:

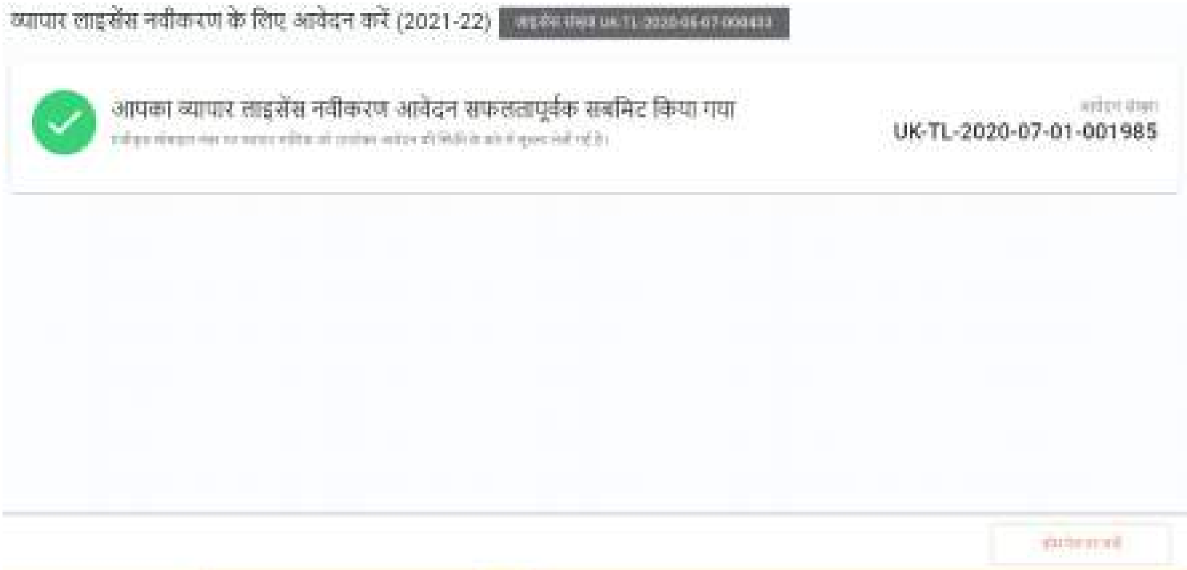

यह स्क्रीन यह सुनिश्चित करती है कि आवेदन नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है और फिर नए आवेदन (यानी 7 वें या दूसरे चरण से) के समान शेष चरणों का पालन किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापनकर्ता से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भुगतान एकत्र किया जाएगा। अनुमोदन के रूप में।

12.2 नए / नवीकरण आवेदन पर क्लिक करके

यदि डीआईजीआईटी प्रणाली के माध्यम से पिछले आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए, ऐसे में उपयोगकर्ता को फिर से पूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए कहा जाएगा।

कदम इस प्रकार हैं:

- काउंटर कर्मचारी नीचे स्क्रीन पर ले जाता है और न्यू / रिन्यूअल एप्लिकेशन पर क्लिक करता है:

2.जो निम्नानुसार आवेदन फॉर्म को खोलेगा

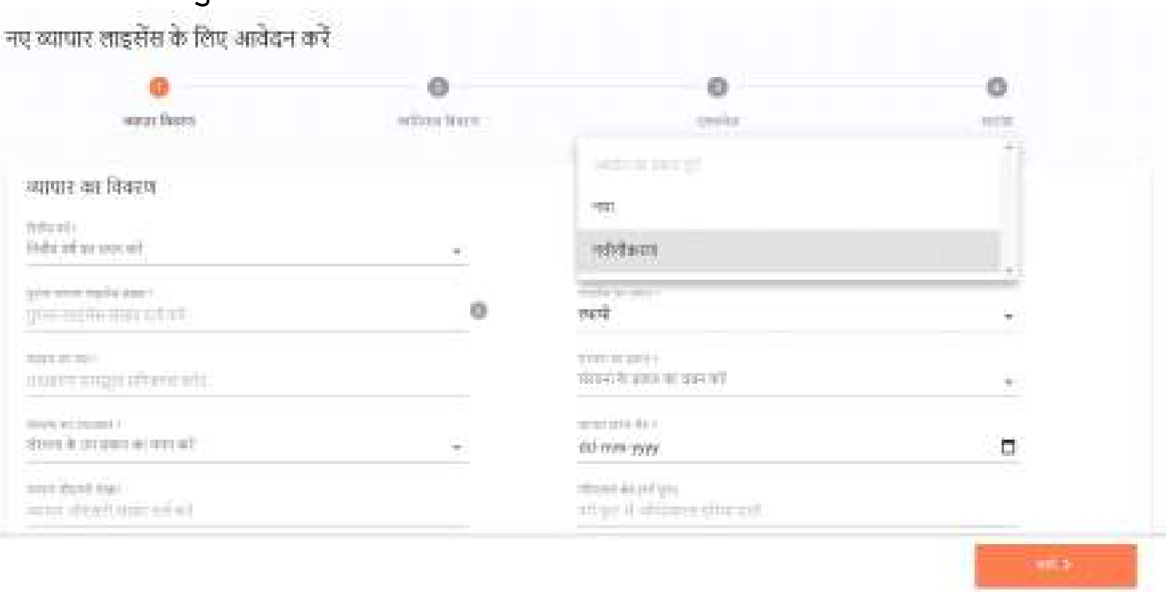

इस मामले में रिवाल विकल्प का चयन किया जाना है और बाकी कदमों का पालन नए आवेदन के लिए किया जाना है और इसी तरह की प्रक्रिया चरण 2 से विस्तृत होगी जो कि आवेदन के चरण 1 से है।

*****

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
मैनुअल–पंद्रह
{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xv) में निर्देशित}

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हों तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित है।

शहरी विकास निदेशालय में पुस्तकालय की सुविधा

शहरी विकास निदेशालय किराये के भवन में अवस्थित है जिसमें पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की सुविधा नहीं है, किन्तु शहरी विकास निदेशालय में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन हेतु आवश्यकता अनुसार आगन्तुकों को बैठने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है।

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतो में वाचन कक्ष व पुस्तकालय की सुविधा

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 7 में नगर पालिका के आवश्यक कर्तव्य और धारा 8 में नगर पालिका के वैवेकिक कृत्य उल्लिखित हैं। पुस्तकालय की व्यवस्था नगर पालिका का वैवेकिक कृत्य (धारा 8 (1)(ख)) है। अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार नगर पालिका की सीमाओं के भीतर और विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसी सीमाओं के बाहर निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है। धारा 8 (1) (ख) के अनुसार **पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राहों केन्द्र कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु–सदन और महिला उद्धार–गृह, पागलखाना हाल, कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम–गृह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान घाट, धोबियों के धुलाई–स्थल, पीने के पानी का स्रोत (ड्रिंकिंग फाउन्टेन), तालाब, कुऑ, बॉध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण में अंशदान देना** नगर पालिका का वैवेकिक कृत्य है।

नगर निगम द्वारा वाचन कक्ष व पुस्तकालय की सुविधा

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 में निगम के अनिवार्य कर्तव्य व धारा 115 में स्वविवेकानुसार कर्तव्य उल्लिखित हैं। पुस्तकालय एवं संग्रहालय की व्यवस्था करना नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य न हो कर स्वविवेकानुसार कर्तव्य है। अधिनियम की धारा 115 (19) के अनुसार **पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों (art galleries), वनस्पति–विज्ञान विषयक (botanical) या जीव विज्ञान विषयक (zoological) संग्रहालयों (collections) की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना** नगर निगम का स्वविवेकानुसार (discretionary) कर्तव्य है।

क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था करना नगर निकायों का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है सम्भवतः इसी और स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों की उपलब्धता के कारण कोटद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, नैनीताल व हल्द्वानी को छोड़कर अधिकांश नगर निकायों द्वारा पुस्तकालय की स्थापना नहीं की गई है। हल्द्वानी में नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित तीन पुस्तकालय व एक वाचनालय हैं।

कोटद्वार, ऋशिकेश, पिथौरागढ़, नैनीताल व हल्द्वानी में स्थापित वाचनालय/पुस्तकालय के खुलने व बन्द होने का समय निम्नवत् हैः –

वाचनालय/पुस्तकालय	खुलने/बन्द होने का समय	
	पूर्वाहह्न	अपराह्न
कोटद्वार	8 बजे से 11 बजे	4 बजे से 7 बजे
ऋषिकेश	8 बजे से 10 बजे	4 बजे से 6 बजे

पिथौरागढ	7 बजे से 10 बजे	3 बजे से 7 बजे
नैनीताल	7:30 बजे से 10:30 बजे	5:30 बजे से 8:30 बजे
हल्द्वानी	8 बजे से 10 बजे	4 बजे से 8 बजे

*****

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–सोलह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xvi) में निर्देशित}

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

शासन द्वारा शहरी विकास विभाग के लिए नियुक्त लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी विकास निदेशालय व अधीनस्थ चिन्हित लोक प्राधिकारियों हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपील अधिकारी निम्नानुसार तैनात किये गये हैं: –

लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
निदेशालय, शहरी विकास	सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय,	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शहरी विकास निदेशालय,	अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, सहायक निदेशक को अपील की सूनवायी हेतु अधिकृत
समस्त नगर निगम,	1–उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त 2–कर अधीक्षक, 3–स्वास्थ्य अधिकारी,	1–उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त 2–कर अधीक्षक, 3–स्वास्थ्य अधिकारी,	नगर आयुक्त
समस्त नगरपालिका परिषद, उत्तराखण्ड	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	नगरपालिका द्वारा नामित अधिकारी	सम्बन्धित जिलो के जिलाधिकारियों द्वारा नामित अधिकारीं
समस्त नगर पंचायत, उत्तराखण्ड	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	नगरपालिका द्वारा नामित अधिकारी	सम्बन्धित जिलो के जिलाधिकारियों द्वारा नामित अधिकारीं

नगर निकायों में तैनात लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड में नगर निकायों की संख्या 105 है जिनमें 09 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायतें हैं। निकाय में तैनात प्रभारी उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों की सेवायें स्थानान्तरणीय है

तथा स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित नगर निकाय के लोक सूचना अधिकारी नामित होते है। वर्तमान में निकायों में तैनात अधिकारियों की स्थिति एवं दूरभाष संख्या निम्नवत् है: –

स्थानीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों की सूची।				
क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थानीय निकाय का नाम/पता	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का नाम	मोबाईल न0
1		नगर निगम, देहरादून	श्री शान्ती प्रसाद जोशी, अधि0अधि0 न0प0/प्र0स0न0आ0	9627118066 8057065085
			श्री यशवीर सिंह राठी व0सहा0/प्र0अधि0अधिकारी	9837096185
			श्री विजय प्रताप सिंह चौहान, कर नि0 एवं रा0 अधि0/प्रभारी सहायक नगर आयुक्त	8126369879
2		नगर पालिका परिषद, विकासनगर	श्री बद्री प्रसाद भट्ट, अधि0अधि0 (न0 पंचायत)	9412921134
3		नगर पालिका परिषद, मसूरी	श्री राजेश नैथानी, कर नि0 एवं रा0 अधि0/प्र0अधि0अधि0	9412055574
			श्री राजबीर सिंह चौहान, सफाई निरीक्षक/प्र0अधि0अधि0	7088738736
4		नगर निगम, ऋषिकेश	श्री रमेश सिंह रावत, कर एवं राजस्व अधीक्षक/सहायक नगर आयुक्त	7017679591
			श्री चन्द्रकांत भट्ट, प्र0स0न0	7017957854
5		नगर पालिका परिषद, हरर्बटपुर	श्री भजनलाल आर्य, अधि0अधि0 (नगर पंचायत)	9917169569 9412057368
6		नगर पालिका परिषद, डोईवाला	श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एवं रा0 अधी0/प्र0अधि0अधि0	8445687487
7		नगर पंचायत, सेलाकुई	श्री मिठ्ठन लाल शाह, अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत)	9756003658
8		नगर निगम, हरिद्वार	श्याम सुन्दर प्रसाद प्रसाद,कर एवं रा0 अधि0/प्र0सहा0 न0 आ0	8755633275
			सुश्री अंकिता जोशी, सहायक नगर आयुक्त	9958523095
			श्री रविन्द्र दयाल, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त	9456103736
9		नगर निगम, रूड़की	श्री एस0पी0 गुप्ता, कर नि0 एवं रा0 अधि0/प्र0अधि0अधि0	9897092681
			श्री संजय कुमार, अधि0अधि0 नगर पं0/प्र0स0न0आ0	9634903929
10		नगर पालिका परिषद, मंगलौर	सुश्री अमरजीत कौर, अधि0अधि0 नगर पं0/प्र0स0न0आ0	8755002449
11		नगर पंचायत, झबरेडा	श्री रमेश पाठक, कर एवं राजस्व	7906653995

			निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	
12		नगर पालिका परिषद, लक्सर	श्री कुलदीप चौहान, प्रधान लिपिक प्रभारी अधि0अधि0	8057875754
13		नगर पंचायत, लण्ढौरा	श्री राजकुमार भारती, सफाई निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9897108634
14		नगर पंचायत, भगवानपुर	श्री मोहन सिंह बनोला, वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9997168177 8859779326
15		नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	श्री सुभाष कुमार, कनिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	8937871194
16		नगर पंचायत, पिरान कलियर	श्री भगवंत सिंह बिष्ट, प्रभारी अधि0अधि0 (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)	9027385425
17		नगर पंचायत, ढंढेरा	श्री संजय रावत, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	8755977578
18		नगर पंचायत, इमलीखेडा	सुश्री मंजू चौहान, वरिष्ठ सहायक / प्र0अ0अधि0	9897712608
19		नगर पंचायत, पाण्डली	श्रीमती सीमा रावत, अधिशासी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)	8127660918
20		नगर पंचायत, रामपुर	श्री अंकित राणा लिपिक, कनिष्ठ सहायक / प्र0 अधिशासी अधिकारी	9917261216 7895974858
21		नगर पंचायत, सुल्तानपुर–अदमपुर	श्री कुलदीप नैथानी, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	8192889363
22	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	श्री शिव कुमार सिंह चौहान,वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9760316350
23		नगर पालिका परिषद, बडकोट	श्री मामचन्द्र वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0 अधि0	
24		नगर पंचायत, गंगोत्री	श्रीमती कुसुम मठूडा, सफाई निरीक्षक / प्रभारी अधि0अधि0	7017443669 9411138470
25		नगर पंचायत, पुरोला	श्री हर्षवर्धन रावत, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	8859779326
26		नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड	श्री विरेन्द्र पंवार, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9411145838 7310583828 7533907987
27		नगर पंचायत, नौगांव	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9412934100
28	चमोली	नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर	श्री प्रीतम सिंह नेगी, वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9412987542
29		नगर पालिका परिषद जोशीमठ	श्री हयात सिह रौतेला वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि	
30		नगर पंचायत, बद्रीनाथ	श्री सुनील पुरोहित प्रभारी अधि0अधि0 (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)	9557124175

31		नगर पंचायत नन्दप्रयाग	श्री गौहर हयात, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9897218552
32		नगर पालिका परिषद, गौचर	श्री ज्योति प्रसाद उनियाल, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9837327988
33		नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	श्री सुरेन्द्र कुमार, सफाई निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9690141480
34		नगर पंचायत, पोखरी	श्री रोशन सिंह पुण्डीर, कर एवं राजस्व निरी0 / प्रभारी अधि0अधि0	9568250628
35		नगर पंचायत, गैरसैण	श्री हेमन्त कुमार, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्रभारी अधि0 अधि0	9410356188
36		नगर पंचायत, थराली	श्री टंकार कौशल, वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9319819363
37		नगर पंचायत, पीपलकोटी	श्री उपेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9719636073
38	टिहरी	नगर पालिका परिषद टिहरी	मौ0 कामिल अधिशासी अधिकारी, (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)	9760018644
39		नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	श्रीमती बीना नेगी,वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9458944693
40		नगर पालिका परिषद, चम्बा	श्री गुरूदीप लाल आर्य सहा0लेखा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9756834076
41		नगर पंचायत कीर्तिनगर	श्री सुधीर कुमार, सहा0लेखा0 / प्रभारी अधि0अधि0	
42		नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग	श्री रघुवीर राय, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9897764792
43		नगर पालिका परिषद, मुनीकीरेती–ढालनवाला	श्री तनवीर मारवाह, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1	7869220871
44		नगर पंचायत, घनसाली	श्री सुशील बहुगुणा, लिपिक	9458201617
45		नगर पंचायत, गजा	श्री हरेन्द्र सिंह चौहान, लिपिक / प्रभारी अधि0अधि0	9756629082 7533907987
46		नगर पंचायत, लम्बगांव	श्री कैलाश सेमवाल, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	
47		नगर पंचायत, चमियाला	श्री अजय कुमार अस्तवाल, कर एवं राजस्व अधीक्षक / प्र0अधि0अधि	9568453839
48		नगर पंचायत, तपोवन	श्री अनिल कुमार पन्त कर एवं रा0 निरीक्षक / प्रभारी अधि0अधि0	9456776559 8006101188
49	रूद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	श्री सुशील कुमार कुरील, कर एवं राजस्व अधीक्षक / प्र0अ0अधि0	9412409827
50		नगर पंचायत केदारनाथ	श्री चन्द्र शेखर चौधरी, कर एवं राजस्व मोहर्रिर / प्रभारी अधि0अधि0	7830034905
51		नगर पंचायत, अगस्तमुनि	श्री कैलाश पेटवाल वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9897020183

52		नगर पंचायत, ऊखीमठ	श्री भरत भूषण पंवार, प्रभारी अधि0 अधि0	8954241234
53		नगर पंचायत, तिलवाड़ा	श्री वासुदेव डंगवाल,वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9411363579
54	पौडी	नगर पालिका परिषद पौडी	श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1	7617548173
55		नगर निगम, श्रीनगर	श्री रविराज बंगारी प्रभारी सहायक नगर आयुक्त	9411138470 9012438470
			श्री अजहर अली, कर एवं रा0अधी0 / प्रभारी सहायक नगर आयुक्त	9557444319
56		नगर पंचायत, स्वर्णाश्रम जौंक	श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	7302346333
57		नगर पालिका परिषद दुगड्डा	श्री गोवर्धन प्रसाद जोशी,वरिष्ठ सहायक / प्र0अधिशासी अधिकारी	7248088090
58		नगर निगम, कोटद्वार	श्री चन्द्र शेखर शर्मा, सहा0लेखाधिकारी / प्र0अधि0अधि0	9760666114
59		नगर पंचायत, सतपुली	श्री जयदीप खत्री, वरि0सहा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9412179116
60		नगर पंचायत, थलीसैण	श्री राजेन्द्र सिंह सजवाण वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9411185348
61	पिथौरागढ	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ	श्री राजदेव जायसी, कर नि0 एवं रा0 अधि0 / प्र0अधि0अधि0	7409739149
62		नगर पालिका परिषद, धारचूला	श्री संजय गडिया वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0 अधि0	
63		नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	मौ0 इस्लाम, लिपिक, कनिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9917158024
64		नगर पंचायत, गंगोलीहाट	श्री राजेन्द्र प्रसाद बेंजवाल, वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधि0अधि0	9456529096
65		नगर पंचायत, बेरीनाग	श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय, लिपिक / प्र0अधि0अधि0	
66	चम्पावत	नगर पालिका परिषद टनकपुर	श्री भूपेन्द्र प्रकाश जोशी प्रभारी अधि0अधि0 (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)	9412100459
67		नगर पालिका परिषद, चम्पावत	श्री अशोक कुमार वर्मा, प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9411115641
68		नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	श्री पूरन सिंह बोरा,वरिष्ठ सहायक / प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9760147315
69		नगर पंचायत, बनबसा	श्री दीपक बुढ़लाकोटी, सहा0लेखा0 / प्रभारी अधि0अधि0	9639121727
70	अल्मोडा	नगर पालिका परिषद अल्मोडा	श्री भरत त्रिपाठी कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9634072354
71		नगर पंचायत द्वाराहाट	श्री धीरज कुमार कण्डपाल, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	9720250569

72		नगर पालिका परिषद रानीखेत–चिनियानौला	श्री प्रवीन कुमार सक्सेना, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	8392842494
73		नगर पंचायत, भिकियासैंण	श्री अनिरूद्ध गौड़, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	8755709435
74		नगर पंचायत, चौखुटिया	श्री विजय सिंह कनवासी, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधिशासी अधिकारी	9410527614
75	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर	श्री हयात सिंह परिहार, कर निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	
76		नगर पंचायत, कपकोट	श्री नवीन कुमार, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	8909841325
77		नगर पंचायत, गरूड़	श्री राजेश कुमार जोशी, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	9412924570
78		नगर पालिका परिषद, नैनीताल	सुश्री पूजा, कर एवं रा0 निरीक्षक / प्रभारी अधि0अधि0	9997638831
79		नगर पालिका परिषद रामनगर	महेन्द्र कुमार यादव,कर नि0 एवं रा0 अधि0 / प्र0अधि0अधि0	9837388351
80		नगर पालिका परिषद भवाली	श्री संजय कुमार, कर नि0 एवं रा0 अधि0 / प्र0अधि0अधि0	9410336253
81		नगर निगम, काशीपुर	सुश्री प्रियंका आर्य, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	7457035159
			सुश्री विमला जोशी, वरिष्ठ सहायक / प्र0 अधि0 अधिकारी	7088652222
82		नगर पंचायत कालाढुगी	श्री ईश्वर सिंह रावत, कर एवं रा0 अधि0 / प्र0अधि0अधि0	9411544917
83		नगर पंचायत लालकुंआ	श्री राहुल कुमार, सहायक लेखाधिकारी / प्रभारी अधि0 अधिकारी	8791336681
84		नगर पंचायत भीमताल	श्री उदयवीर सिंह सफाई निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	
85		नगर पालिका परिषद गदरपुर	श्री संजीव मेहरोत्रा, अधिशासी अधिकारी	8077482361
86		नगर पालिका परिषद जसपुर	श्री शाहिद अली, वरिष्ठ सहा0 / प्र0अधि0अधिकारी	9897025964
87	उद्यमसिंह नगर	नगर निगम, काशीपुर	श्री रोहिताश शर्मा, प्रभारी उप नगर आयुक्त	9412050815
			श्री विनोद लाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–4	7060278435
			श्रीमती सरीता राणा, अधिशासी अधिकारी, न0पं0 / प्र0स0न0	9837022731
88		नगर पालिका परिषद बाजपुर	श्री मनोज कुमार दास, कर एवं राजस्व अधीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9412987361
89			श्रीमती राजू नबियाल, अधि0अधि0 न0पं0 / प्र0सहा0न0आयु0	7533907967

			श्री दीपक गोस्वामी, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1	7819961241
90		नगर पालिका परिषद किच्छा	श्री गुरमीत सिंह, सफाई निरीक्षक / प्र0अधि0अधिकारी	9368533723 9568021005 7456861665
91		नगर पा0 परिषद सितारगंज	श्री नौशाद हसीन, प्रभारी अधिशासी अधिकारी	9045482640
92		नगर पालिका परिषद खटीमा	श्री दीपक शुक्ला, कनिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	7017975410
93		नगर पंचायत महुवाडावरा	सुश्री शिखा आर्य, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9536265606
94		नगर पालिका परिषद, महुआखेडागंज	श्री सतीश कुमार सहायक लेखाकार / प्र0अधि0अधि0	7055660727
95		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी	श्रीमति गीता चौधरी, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	9105586515
96		नगर पंचायत केलाखेडा	श्री आदेश कुमार, सफाई निरीक्षक / प्र0अधि0अधि0	9720480010
97		नगर पंचायत दिनेशपुर	सुश्री सरोज गौतम, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्र0 अधि0 अधिकारी	7088652222
98		नगर पंचायत शक्तिगढ	श्रीमती प्रतिभा कोहली,अधि0अधि0 (नगर पंचायत)	7017030486
99		नगर पंचायत, नानकमत्ता	सुश्री प्रियंका रैक्वाल, कर एवं राजस्व निरीक्षक / प्रभारी अधि0अधि0	7088002222
100		नगर पंचायत, गुलरभोज	श्री आशीष नेगी (प्रतिनियुक्ति)	9410361536 9758790291
101		नगर पालिका परिषद, नगला	श्री विजय बिष्ट, वरिष्ठ सहायक / प्र0अधि0अधि0	9837860090
102		नगर पंचायत, लालपुर	श्री विनोद श्रेय, लिपिक / प्र0अधि0अधि0	7417017000

*****

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग

संख्या 2334 / V–श्–05–145(सा0) / 05
देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2 (एच) के अन्तर्गत शहरी विकास विभाग के लिए विहित लोक प्राधिकारियों हेतु धारा –5 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं साहयक लोक सूचना अधिकारी (APIO) तथा धारा–15 के अन्तर्गत विभागीय अपील अधिकारी (DAA) की निम्नानुसार नियुक्ति किये जाने की श्री राज्पाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
निदेशालय शहरी विकास	निदेशक शहरी विकास	उप निदेषक, शहरी विकास	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
राज्य नगरीय विकास अभिकरण	निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण	परियोजना अधिकारी राज्य नगरीय विकास अभिकरण	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
नगर निगम, देहरादून	मुख्य नगर अधिकारी	उप नगर अधिकारी	निदेशक, शहरी विकास
नगर पालिका परिशद, उत्तराखण्ड	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	नगर पालिका द्वारा नामित अधिकारी	निदेशक, शहरी विकास
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	नगर पंचायत द्वारा नामित अधिकारी	निदेशक, शहरी विकास

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। नगर पालिका परिशदों / नगर पंचायतों के समस्त अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नगर पालिका परिषद / पंचायत के लिए सहायक लोक सूचनाधिकारी को नामित करते हुए शासन एवं निदेशक, शहरी विकास को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

ह0
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्याः 2334 / V–श0वि0–05–145(सा0) / 05, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड। द्वारा निदेशक, शहरी विकास।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0
(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।

<u>नोट</u> :– वर्तमान में नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा नगर निगमों में नगर आयुक्त है।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
मैनुअल–सत्रह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xvii) में निर्देशित}

लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना जो विहित की जाये।
लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में अन्य सूचना

शहरी विकास निदेशालय द्वारा वर्ष 2023–24 की प्रगति पुस्तिका प्रकाशित की गई है जो इस मैनुअल के साथ संलग्न की जा रही है।

*****

उत्तराखण्ड शासन

दिग्दर्शिका एवं ऑउटकम बजट

वित्तीय वर्ष 2024–25

शहरी विकास विभाग

दिग्दर्शिका एवं ऑउटकम बजट

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2024–25

अनुक्रमणिका

1	प्रस्तावना	01
2	उत्तराखण्ड परिदृश्य	03
3	स्थानीय निकायों का विवरण	04
4	निदेशालय स्तर (विभागीय ढ़ाँचा)	07
4.1	निकाय स्तर	09
5	विभागीय कार्यक्रम, योजनायें एवं पहल	12
5.1	स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)	13
5.2	अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)	23
5.3	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	37
5.4	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	44
5.5	देहरादून स्मार्ट सिटी	56
5.6	उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी	69
6	विकसित भारत संकल्प यात्रा (शहरी)	73
7	ई–गवर्नेंस	76
8	शहरी विकास विभाग की उपलब्धियां	80
9	वित्तीय विवरण	82
9.1	बजट उपयोग (2023–24)	83

सविंधान के 74 वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित 18 विषयों पर नगर निकायों का उत्तरदायित्व होगा

1. नगर के नियोजन सहित शहरी नियोजन।

2. भू–उपयोग का विनियम और भवन–निर्माण

3. आर्थिक व सामाजिक उन्नतयन को ध्येय से नियोजन।

4. सड़क एवं पुल।

5. घरेलू उपयोग व औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जलापूर्ति।

6. जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल–प्रबन्धन एवं कूड़ा–कचरा निस्तारण।

7. अग्निशमन सेवाएं।

8. परिस्थितिकीय एवं पर्यावरण संरक्षण के ध्येय से शहरी वनीकरण।

9. शाररिक व मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों का हित संरक्षण।

10. मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन।

11. शहरी गरीबी निवारण।

12. नागरिक जन–सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, और मैदानों की व्यवस्था करना।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यपूर्ण विकास।

14. शव–गृह, कब्रिस्तान और विद्युत शव–दाह–गृह।

15. पशुओं के लिए पीने के पानी और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।

16. जन्म–मृत्यु के आंकडों सहित महत्वपूर्ण सांख्यि की सूचना।

17. गलियों, पार्किंग और स्टापों के पथ–प्रकाश (लाईट) की सुविधाओं की व्यवस्था और प्रबन्धन।

18. पशु वधशालाओं और चर्मशोधनालाओं का विनियमन

प्रस्तावना

विजन शहरों को जीवंत, स्वच्छ एवं आधार भूत ढांचे को मजबूत बनाकर, नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए शहरों का एकीकृत विकास करना।

उद्देश्य विरासत का संरक्षण करते हुए शहरी क्षेत्रो में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना एवं नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुनिश्चित करना।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 103 निकायों की कुल जनसंख्या 36.49 लाख है, राष्ट्रीय दशकीय जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 31.2 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य की औसत वृद्धि दर 30.2 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो की जनसंख्या वृद्धि दर में भिन्नता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के शहरी क्षेत्रो की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत, ग्रामीण औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत के सापेक्ष अत्यधिक है।

राज्य की शहरी जनसंख्या मुख्य रूप से देहरादून (8.03 लाख,) हरिद्वार (2.51 लाख) और राज्य के कृषि से समृद्व और औधोगिक रूप से विकसित भाग जैसे – रूद्रपूर, रूडकी, काशीपुर और हल्द्वानी में स्थित शहरो में केन्द्रित है। उल्लेखनीय है कि देहरादून जो राज्य की राजधानी और नीति निर्माण का केन्द्र है, की दशकीय औसत जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना–2001 और जनगणना–2011 के मध्य 5 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है।

उत्तराखण्ड राज्य के शहरी आबादी के अतिरिक्त कई पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान जैसे–मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुण्ड साहिब, गंगोत्री, यमनोत्री, पिरान कलियर आदि, में पर्यटको और तीर्थ यात्रीयो की एक बडी संख्या वर्ष भर राज्य के विभिन्न शहरों में अस्थायी रूप से निवास करती है।

प्रस्तावना

एक पहाड़ी राज्य होने के कारण अधिकाश शहरी स्थानीय निकाय राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं इसीलिए राज्य में शहरी विकास योजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है। योजनाकारों के लिये राज्य की स्थलकृति और भौगोलिक विषेशताएं अतिरिक्त चुनौतियाँ है।

शहरी विकास विभाग राज्य में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रशासनिक विभाग है, उत्तराखण्ड आवास विभाग शहरी विकास प्राधिकरणों और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लिए समान भूमिका निभाता है। इसके अलावा पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड, पेयजल निगम (यूपीजेएन) और जल संस्थान (यूजेएस) का प्रशासनिक विभाग है जो परियोजना कस्बों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज और जल निकासी सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसे संगठन शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अन्य लाइन एजेंसियां हैं।

उत्तराखण्ड परिदृश्य

क्रम	बिन्दु	विवरण
1	क्षेत्रफल	53483 वर्ग कि0मी0
2	मण्डल / जनपद	2 / 13
3	शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	36,48,834
4	स्थानीय नागर निकाय	103
5	नगर निगम	09
6	नगर पालिका परिषद	45
7	नगर पंचायत	49

स्थानीय निकायों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का निकायवार विवरण

क्र०सं०	जनपद	स्थानीय निकाय	जनगणना वर्ष 2011		सीमा विस्तार के पश्चात्		कुल वार्ड
			क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	जनसंख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	जनसंख्या	
1		नगर निगम, देहरादून	64.48	569578	185.00	803983	100
2		नगर पालिका परिषद, विकासनगर	3.11	13927	9.35	24019	11
3		नगर पालिका परिषद, मसूरी	64.75	30118	64.75	30118	13
4	देहरादून	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	12.41	98899	26.00	106320	40
5		नगर पालिका परिषद, हर्रबटपुर	3.28	9782	7.08	10567	9
6		नगर पालिका परिषद, डोईवाला	2.91	8709	50.37	55791	20
7		नगर पंचायत, सेलाकुई	12.87	16880	12.87	16880	9
8		नगर निगम, हरिद्वार	12.17	228832	18.82	251197	60
9		नगर निगम, रुड़की	28.97	184060	34.00	182515	40
10		नगर पालिका परिषद, मंगलौर	8.23	52971	8.23	52994	20
11		नगर पंचायत, झबरेड़ा	3.00	11186	3.19	11186	9
12		नगर पालिका परिषद, लक्सर	5.00	21760	5.00	25754	11
13		नगर पंचायत, लण्ढौरा	0.82	18370	7.04	18370	9
14	हरिद्वार	नगर पंचायत, भगवानपुर	2.64	17179	2.64	17179	9
15		नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	13.36	32000	15.50	33600	13
16		नगर पंचायत, पिरान कलियर	2.97	19201	2.97	19439	9
17		नगर पंचायत, ढंडेरा	3.65	23257	3.65	23276	11
18		नगर पंचायत, इमलीखेड़ा	15.91	10236	15.91	10240	9
19		नगर पंचायत, पाण्डली गुर्जर	7.47	21468	7.47	21468	11
20		नगर पंचायत, रामपुर	7.06	17821	7.06	27364	11
21		नगर पंचायत, सुल्तानपुर–आदमपुर	2.42	16042	2.42	16047	9
22		नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी	12.02	17475	23.11	27102	11
23		नगर पालिका परिषद, बड़कोट	7.00	6720	13.00	7414	7
24	उत्तरकाशी	नगर पंचायत, गंगोत्री	8.00	110	8.00	110	0
25		नगर पंचायत, पुरोला	5.26	7931	5.26	7931	7
26		नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़	6.19	8844	6.19	8844	7
27		नगर पंचायत, नौगांव	5.77	5174	5.77	5174	7
28		नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	10.00	9307	10.00	9313	7
29		नगर पंचायत केदारनाथ	0.14	612	0.14	612	0
30	रूद्रप्रयाग	नगर पंचायत, अगस्तमुनि	2.47	6557	2.52	6557	7
31		नगर पंचायत, ऊखीमठ	2.74	3115	4.60	3638	4
32		नगर पंचायत, तिलवाड़ा	2.70	2900	2.70	2398	4
33		नगर पालिका परिषद टनकपुर	1.20	17626	10.55	21484	11
34	चम्पावत	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	10.00	11029	10.00	12756	9
35		नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	4.50	7926	4.50	7932	7
36		नगर पंचायत, बनबसा	0.88	6023	0.88	6023	7

स्थानीय निकायों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का निकायवार विवरण							
क्र0सं0	जनपद	स्थानीय निकाय	जनगणना वर्ष 2011		सीमा विस्तार के पश्चात्		कुल वार्ड
			क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या	
37	चमोली	नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर	14.08	21447	14.08	21447	11
38		नगर पालिका परिषद जोशीमठ	20.46	16709	21.79	16709	9
39		नगर पंचायत, बद्रीनाथ	2.01	2438	2.01	2438	0
40		नगर पंचायत नन्दप्रयाग	2.16	1641	4.84	2441	4
41		नगर पालिका परिषद, गौचर	5.39	8864	5.39	8864	7
42		नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	4.40	8297	12.52	9850	7
43		नगर पंचायत, पोखरी	8.75	6119	8.75	5295	7
44		नगर पंचायत, गैरसैण	7.53	8665	7.53	8665	7
45		नगर पंचायत, थराली	4.59	4482	4.59	4649	4
46		नगर पंचायत, पीपलकोटी	6.99	3521	6.99	3521	4
47		नगर पंचायत, नन्दानगर			4.09	2839	4
48	टिहरी	नगर पालिका परिषद टिहरी	37.05	24014	37.05	24014	11
49		नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	10.36	6033	11.65	6049	7
50		नगर पालिका परिषद, चम्बा	8.00	10457	8.00	10457	9
51		नगर पंचायत कीर्तिनगर	2.50	1517	5.64	2991	4
52		नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग	6.00	2868	8.75	3059	4
53		नगर पंचायत, घनसाली	20.35	28636	20.35	28636	11
54		नगर पालिका परिषद, मुनीकीरेती–ढालवाला	0.52	7775	0.52	7750	7
55		नगर पंचायत, गजा	1.08	1800	1.08	2098	4
56		नगर पंचायत, लम्बगांव	1.80	2330	1.80	1061	4
57		नगर पंचायत, छमियाला	2.93	5306	2.93	5017	7
58		नगर पंचायत, तपोवन	0.97	3890	0.97	3890	4
59	पौड़ी	नगर पालिका परिषद पौड़ी	42.00	25440	42.00	25135	11
60		नगर निगम, श्रीनगर	9.00	20115	1257.05	37911	40
61		नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक	8.00	4669	8.00	4617	4
62		नगर पालिका परिषद दुगड्डा	1.50	2422	1.50	2422	4
63		नगर निगम,कोटद्वार	2.59	28859	45.52	135544	40
64		नगर पंचायत, सतपुली	2.29	4345	2.29	4345	4
65		नगर पंचायत, थलीसैण	5.32	2982	5.32	2982	4
66	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	9.00	56044	12.19	65502	20
67		नगर पालिका परिषद, धारचूला	3.50	7039	3.50	7039	7
68		नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	4.54	6522	4.54	7969	7
69		नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट	6.62	7112	6.62	7112	7
70		नगर पंचायत, बेरीनाग	7.03	7641	7.03	7641	7

क्र०सं०	जनपद	स्थानीय निकाय	जनगणना वर्ष 2011		सीमा विस्तार के पश्चात्		कुल वार्ड
			क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	जनसंख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	जनसंख्या	
71	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा	7.35	34125	18.17	38958	13
72		नगर पंचायत द्वाराहाट	2.88	2749	2.88	2749	4
73		नगर पालिका परिषद रानीखेत	0.62	5050	0.62	5050	7
74		नगर पंचायत, भिकियासैण	4.54	3275	4.54	4214	4
75		नगर पंचायत, चौखुटिया	4.51	4464	4.51	4464	4
76	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर	5.50	9079	8.69	25045	11
77		नगर पंचायत, कपकोट	5.49	5365	5.49	5365	7
78		नगर पंचायत, गरूड़	2.46	5002	2.46	5227	7
79	नैनीताल	नगर पालिका परिषद नैनीताल	11.73	41377	11.73	41377	15
80		नगर पालिका परिषद रामनगर	2.43	54787	2.43	54787	20
81		नगर पालिका परिषद भवाली	2.28	6309	27.00	8457	7
82		नगर निगम, हल्द्वानी	14.16	171351	58.96	281215	60
83		नगर पंचायत कालाढुंगी	2.00	7611	5.88	9878	7
84		नगर पंचायत लालकुंआ	4.25	7644	4.25	7644	7
85		नगर पंचायत भीमताल	3.95	7722	18.52	14882	9
86	ऊधमसिंह नगर	नगर पालिका परिषद गदरपुर	3.40	19301	6.40	23289	11
87		नगर पालिका परिषद जसपुर	10.39	50523	10.39	56156	20
88		नगर निगम, काशीपुर	8.58	121623	51.50	175819	40
89		नगर पालिका परिषद बाजपुर	4.50	25524	13.80	31172	13
90		नगर निगम, रूद्रपुर	12.43	140857	59.60	175723	40
91		नगर पालिका परिषद किच्छा	4.02	41965	27.09	74356	20
92		नगर पा० परिषद सितारगंज	2.00	29965	2.50	31185	13
93		नगर पालिका परिषद खटीमा	0.74	15093	16.92	58494	20
94		नगर पंचायत महुवाडावरा	4.00	7326	4.00	7326	7
95		नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज	8.15	12584	8.15	12584	9
96		नगर पालिका परिषद, गगला	44.22	57977	44.22	57977	20
97		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी	4.04	9881	4.37	9881	7
98		नगर पंचायत केलाखेड़ा	4.98	10929	4.98	10929	9
99		नगर पंचायत दिनेशपुर	4.50	10802	5.50	11883	9
100		नगर पंचायत शक्तिगढ	2.03	6309	2.61	7784	7
101		नगर पंचायत, नानकमत्ता	5.88	8478	5.88	8478	7
102		नगर पंचायत, गुलरभोज	0.98	4829	2.12	6957	7
103		नगर पंचायत, लालपुर	2.13	3675	2.13	3975	4
योग			824.64	2823500	2631.70	3648834	1264

निदेशालय स्तर (विभागीय ढाँचा)

शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड में पुर्नगठन शासनादेश संख्या–618/पत्र/(1)/2014–01(28)/2014, दिनांक 08–09–2014, एवं शासनादेश संख्या–758, दिनांक 08–02–2021 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के सृजित पदों एवं उसके सापेक्ष कार्यरत/रिक्तियों का विवरण (28–02–2023 की स्थिति)					
क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	वेतनबैण्ड / ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद
प्रशासनिक शाखा					
1	निदेशक (I.A.S.)	संवर्गानुसार	1	1	0
2	अपर निदेशक (P.C.S.)	संवर्गानुसार	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक (01 पद प्रशासन तथा 01 पद सतर्कता, विधि एवं प्रशिक्षण)	15600–39100 / 7600	2	1	1
4	उपनिदेशक (01 पद प्रशासन तथा 01 पद नियोजन एवं अन्य विविध कार्य)	15600–39100 / 6600	2	1	1
5	सहायक निदेशक (01 पद प्रशासन तथा 01 पद नियोजन एवं अन्य विविध कार्य)	15600–39100 / 5400	2	2	0
लेखा संवर्ग शाखा					
6	वित्त नियन्त्रक	वित्त एवं लेखा संवर्ग	1	1	0
7	सहायक वित्त / लेखाधिकारी	9300–34800 / 4800	1	1	0
8	लेखाकार	9300–34800 / 4200	2	2	0
9	सहायक लेखाकार	5200–20200 / 2800	4	4	0
तकनीकी सेल					
10	अधीक्षण अभियन्ता	37,400–67000 / 8700	1	1	0
11	अधिशासी अभियन्ता	15600–39100 / 6600	1	0	1
12	सहायक अभियन्ता	15600–39100 / 5400	2	2	0
13	अवर अभियन्ता (सिविल)	9300–34800 / 4600	4	0	4
14	अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल)	9300–34800 / 4600	1	0	1
15	अवर अभियन्ता (मैकेनिकल)	9300–34800 / 4600	1	0	1

निदेशालय स्तर (विभागीय ढाँचा)

क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	वेतनबैण्ड / ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद
16	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) अवस्थापना	–	1	1	0
17	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन	–	1	1	0
मिनिस्ट्रियल संवर्ग शाखा					
18	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100 / 5400	2	1	1
19	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 / 4800	2	0	2
20	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 / 4600	2	1	1
21	प्रधान सहायक	5200–20200 / 4200	5	2	3
22	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 / 2800	7	7	0
23	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 / 2000	9	2	7
24	आशुलिपिक / डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200–20200 / 2400	8	6	2
25	वाहन चालक	5200–20200 / 1900	2	2	0
26	चपरासी / अनुसेवक	5200–20200 / 1800	5	9	-4
योगः–			**70**	**49**	**21**

नोट– शहरी विकास निदेशालय में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के 04 पदों पर लोक सेवा आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी हैं, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये 03 कनिष्ठ सहायक के पद का अधियाचन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

निकाय स्तर (पालिका केन्द्रियत सेवा)

स्थानीय निकायों में शासनादेश संख्या–756, 757, 758, 759/प(1)/2015–01(32)/2014, दिनांक 12–06–2015, शासनादेश संख्या–1368, दिनांक 07–10–2015, शासनादेश संख्या–86, दिनांक 22–01–2016, शासनादेश संख्या–15,दिनांक 06–01–2016, शासनादेश संख्या–1202, 1201, 1200 दिनांक 30–09–2019, एवं निदेशालय के शासनादेश संख्या–618, दिनांक 08–09–2014, संख्या 680, दिनांक 25–05–2015 व संख्या 581, दिनांक 03–09–2021 द्वारा पुनर्गठन के फलस्वरूप के अनुसार सृजित पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों का विवरण (102 स्थानीय निकायों में दिनांक 28.02.2023 की स्थिति

क्र0	सृजित पदनाम	वेतन बैण्ड /ग्रेड	सृजित पद	वर्तमान कार्मिक	रिक्त पदों की संख्या			रिक्त पद
					सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनि0 के पद	
पालिका प्रशासी सेवा								
1	नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी	37400–67000/8700	4	0	0	4	0	4
2	अपर नगर आयुक्त/अपर मुख्य नगर अधिकारी/संयुक्त निदेशक	15600–39100/7600	4	0	0	4	0	4
3	उप नगर आयुक्त/उप नगर अधिकारी/उप निदेशक	15600–39100/6600	12	0	0	12	0	12
4	सहायक नगर आयुक्त/ सहायक नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/सहायक निदेशक	15600–39100/5400	26	7	7	12	0	19
5	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2	9300–34800/4800	11	1	0	10	0	10
6	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	9300–34800/4200	28	2	0	26	0	26
7	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	5200–20200/ 2800	50	13	37	0	0	37
पालिका अभियन्त्रण सेवा								
8	अधीक्षण अभियन्ता	15600–39100/7600	1	1	0	0	0	0
9	अधिशासी अभियन्ता	15600–39100/6600	10	1	0	9	0	9
10	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100/5400	20	5	10	5	0	15
11	सहायक अभियन्ता (मैकेनिकल)	15600–39100/5400	1	0	0	0	1	1
12	सहायक अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल)	15600–39100/5400	1	0	0	0	1	1
13	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	9300–34800/4800	12	0	0	12	0	12
14	अवर अभियन्ता (सिविल)	9300–34800/4600	59	20	33	6	0	39
15	अवर अभियन्ता (मैकेनिकल)	9300–34800/4600	3	1	0	0	2	2
16	अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल)	9300–34800/4600	10	1	0	0	9	9

निकाय स्तर (पालिका केन्द्रियत सेवा)

क0	सृजित पदनाम	वेतन बैण्ड /ग्रेड	सृजित पद	वर्तमान कार्मिक	रिक्त पदों की संख्या			रिक्त पद
					सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनि0 के पद	
पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा								
17	सहायक नगर आयुक्त / सहायक नगर अधिकारी(ठोस प्रबन्धन)	15600–39100 / 5400	2	0	0	2	0	2
18	जोनल सफाई अधिकारी	9300–34800 / 4800	11	0	0	11	0	11
19	मुख्य सफाई निरीक्षक	9300–34800 / 4200	28	0	0	28	0	28
20	सफाई निरीक्षक	5200–20200 / 2800	133	45	44	44	0	88
पालिका लेखा सेवा								
21	लेखाधिकारी ग्रेड–1 / लेखाधिकारी	15600–39100 / 5400	2	0	0	2	0	2
22	लेखाधिकारी ग्रेड–2 / सहायक लेखाधिकारी	9300–34800 / 4800	7	6	0	1	0	1
23	लेखाकार	9300–34800 / 4200	18	1	0	17	0	17
24	सहायक लेखाकार	5200–20200 / 2800	64	26	32	6	0	38
पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा								
25	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 / 4800	9	0	0	9	0	9
26	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 / 4600	26	0	0	26	0	26
27	प्रधान सहायक	9300–34800 / 4200	59	0	0	59	0	59
28	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 / 2800	180	126	0	54	0	54
29	प्रधान लिपिक	5200–20200 / 2400	4	2	2	0	0	2

निकाय स्तर (पालिका केन्द्रियत सेवा)

क्र0	सृजित पदनाम	वेतन बैण्ड/ग्रेड	सृजित पद	वर्तमान कार्मिक	रिक्त पदों की संख्या			रिक्त पद
					सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनि0 के पद	
पालिका राजस्व सेवा								
30	सहायक नगर आयुक्त /अधिकारी (कर एवं राजस्व)	15600–39100/5400	2	0	0	2	0	2
31	कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी	9300–34800/4800	11	11	0	0	0	0
32	कर एवं राजस्व अधीक्षक	9300–34800/4200	29	22	0	7	0	7
33	कर एवं राजस्व निरीक्षक	5200–20200/2800	103	39	35	29	0	64
योग			**940**	**330**	**200**	**397**	**13**	**610**

नोट– सहायक नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 के 05, अधिशासी अधिकारी के 63, सहायक अभियन्ता 09, अवर अभियन्ता 32, सफाई निरीक्षक 66, कर एवं राजस्व निरीक्षक 22, सहायक लेखाकार 30, कुल 227 पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं।

विभागीय कार्यक्रम, योजनायें एवं पहल

स्वच्छ भारत मिशन

स्मार्ट शौचालयों का निर्माण, जो आटोमैटिक हैण्ड वाश, शूज पॉलिस, वेटिंग रूम सोफा टी0वी0 व जलपान आदि सुविधाओ से युक्त है।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन–शहरी कार्यक्रम का शुभारम्भ देश के यशस्वी मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को किया गया। कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष अर्थात् 02 अक्टूबर, 2014 से 02 अक्टूबर, 2019 तक थी, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया गया। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष–2026 तक देश के प्रत्येक शहर को कचरा मुक्त शहर बनाने की परिकल्पना के साथ स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का संचालन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 37.70 करोड़ है जो कुल जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत है जो वर्ष 2031 तक लगभग 60 करोड़ होने की प्रबल संभावना है। शहरों में कमजोर साफ–सफाई एवं अनुपचारित मल भारत में जल प्रदूषण का एक मुख्य स्त्रोत है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय अभियान है, जो भारत के 4400 से अधिक शहरों को आच्छादित करता है, जो देश की गलियों, सड़कों को साफ रखने एवं स्वच्छता से सम्बन्धित बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावी जन आन्दोलन है। इस जन आन्दोलन में उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक नागरिक द्वारा पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर किया जाना होगा। ताकि स्वच्छता के इस महाअभियान को सही मायनों में सफल बनाया जा सके व योजना को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू की जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 का कार्यान्वयन वर्ष 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाने के विजन के साथ किया गया है, जिस हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है:–

- स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्थायी स्वच्छता और जल अपशिष्ट का उचित उपचार।
- बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुंच बनाने हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना।
- मिशन के उद्देश्यों की ससमय पूर्ती हेतु क्षमता सम्वर्द्धन के कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करना।

मिशन के घटक :–

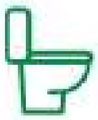

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।

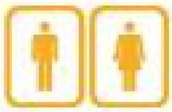

2. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण।

3. वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।

4. वैज्ञानिक जल अपशिष्ट प्रबन्धन।

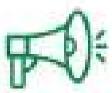

5. सूचना शिक्षा एवं संचार।

6. क्षमता अभिवृद्धि।

14

व्यक्तिगत् घरेलू शौचालय

निकाय अंतर्गत ऐसे व्यक्तिगत् घरेलू शौचालयों का सर्वे वार्ड सभासद के साथ सामंजस्य स्थापित कर किया जाना है, ऐसे घर जिनमें शौचालय नहीं हैं, ऐसे घर जिनमें शौचालय हैं परन्तु अस्वस्थकारी दशा में है अर्थात् ऐसे शौचालय जो टू पिट सिस्टम/सैप्टिक टैंक–सोक पिट/सीवर लाईन में संयोजित नहीं हैं। जिन घरों में व्यक्तिगत् घरेलू शौचालय उपलब्ध नहीं है अथवा अस्वस्थकारी दशा में हैं उन्हें तैयार किये जाने हेतु नियमानुसार प्रोत्साहन धनराशि लाभार्थी को प्रदान की जाऐगी।

सामुदायिक शौचालय

नगर निकाय के अंर्तगत ऐसे सामुदायिक शौचालय का भी सर्वे किया जाना है जो खराब स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान का भी सर्वे प्रस्तावित है, जहाँ 06 से 20 परिवार निवासरत् हों व घरों में व्यक्तिगत् घरेलू शौचालय नहीं हो तथा तैयार किये जाने हेतु उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध न हो, हेतु स्थान चयन कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।

सार्वजनिक शौचालय

नगर निकाय के अंर्तगत सार्वजनिक शौचालय का सर्वे किया जाना है जो खराब स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ शौचालय उपलब्ध नहीं है का भी सर्वे कर शौचालय निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है। जिन निकायों में मेले का आयोजन किया जाता है तथा पर्यटन सीजन में यात्रियों का आवागमन अधिक होता है वहाँ उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर मोबाईल शौचालय भी प्रस्तावित किया जा सकता है।

वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु निर्मित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा नियमानुसार 90 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य है। इस मद में निकाय अन्तर्गत नये कूडे के साथ–साथ निकाय में अवस्थित पुराने कूड़े के ढेरों का भी उचित निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

जल अपशिष्ट प्रबन्धन

प्रदेश के एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है। शहरी विकास विभाग में इस कार्य हेतु तकनीकि विषेशज्ञों के अभाव में जल निगम/जल संस्थान के विषय विषेशज्ञों/अभियन्ताओं का सहयोग लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। निकाय अन्तर्गत सीवर नेटवर्क का निर्माण/एस0टी0पी0 का निर्माण/फीकल स्लज प्रबन्धन/सीवर साफ करने हेतु उपकरण क्रय किये जाने आदि कार्य अनुमन्य हैं।

सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधिया

मिशन उद्देश्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार तथा स्वच्छता के प्रति नागरिकों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रचार–प्रसार की गतिविधियां संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की जानी है। इस हेतु विस्तृत कार्य–योजना 2021–26 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

- प्रत्येक पखवाड़े को किसी विषय से जोड़ते हुये समस्त निकायों में विषेष स्वच्छता पखवाड़ों का नियमित आयोजन।
- आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक निकाय से स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर चिन्हित किए गए हैं।
- निकायन्तर्गत अन्तर–विद्यालयी निबन्ध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार–प्रसार, नुक्कड़ नाटक, कठपुतलियों इत्यादि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

15

02 अक्टूबर 2014 से 07 फरवरी, 2024 तक आवंटित बजट की स्थिति (धनराशि रू0 करोड़ में)

कार्य का नाम	कुल प्राप्त धनराशि	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	व्यय धनराशि
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	155.53	71.63	83.90	125.46
क्षमता अभिवृद्धि	4.73	4.26	0.47	2.66
आई0ई0सी0 एवं जन–जागरूकता	9.26	8.34	0.92	7.56
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय	33.17	29.85	3.32	29.85
सार्वजनिक मूत्रालय	3.20	1.28	1.92	3.20
यूज्ड वाटर मैनेजमेंट	2.24	2.02	0.22	0.00
योग	**208.13**	**117.38**	**90.75**	**168.73**

स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अंर्तगत नगर निकाय कीर्तिनगर एवं नौगॉव में निर्मित एम.आर.एफ. केन्द्र

"स्वच्छ सर्वेक्षण–2023"

देश के नगरीय क्षेत्रों के मध्य स्वच्छता का सबसे बड़ा मुकाबला है "स्वच्छ सर्वेक्षण"। यह अखिल भारतीय स्वच्छता प्रतियोगिता भारत देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सराही जा रही है।

राज्य के 97 निकायों (88 शहरी निकायों तथा 09 छावनी परिषदों) को अखिल भारतीय नगरीय स्वच्छता रैंकिंग के पैमाने पर परखा जा चुका है। स्वच्छता की यह प्रतियोगिता पूरे देश में 01 अप्रैल, 2023 से क्षेत्रीय स्तर पर स्वच्छता का मूल्यांकन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुल 02 पुरस्कार प्राप्त हुए।

एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में देहरादून को उत्तराखण्ड में स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक लाख से कम जनसंख्या वाली निकायों में मुनि की रेती का उत्तराखण्ड में स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 100 निकायों से कम वाले राज्यों की श्रेणी में राज्य को 19 वां स्थान प्राप्त हुआ। राज्य में अब तक 52 निकाय ओ0डी0एफ0, 30 निकाय ओ0डी0एफ0, 04 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस 02 निकाय वाटर प्लस तथा 01 निकाय जी0एफ0सी घोषित हुई हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त करते हुए निवर्तमान मा0 मेयर नगर निगम देहरादून व अन्य

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त करते हुए निवर्तमान मा0 अध्यक्ष नगर पालिका मुनिकीरेती व अन्य

17

"अर्बन लार्नाथोन"

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान की ओर से प्लास्टिक और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अर्बन लार्नाथोन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राज्यों से शहरी निकायों ने भाग किया। जिसमें उत्तराखण्ड को अर्बन लार्नाथोन 2023 के विजेता और उपविजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अर्बन लार्नाथोन–2023 विजेता और उपविजेता का पुरस्कार प्राप्त करते हुए नगर निगम हल्द्वानी के मेयर, श्री जोगेंद्र रोतेला एंव शहरी विकास निदेशालय के सहायक निदेशक, श्री विनोद कुमार

Behavioral Change

for Plastic Waste Management in Uttarakhand

Initiative by

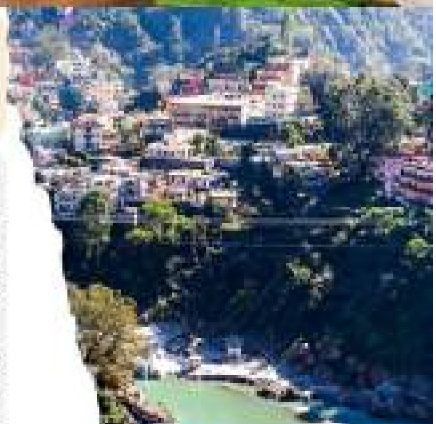

कूड़ा व्यवस्थापना के लिए शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन रूद्रप्रयाग द्वारा रिसाइकल संस्था के माध्यम से अभिनव पहल

चार–धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्री हर साल यहां बड़ी संख्या में इस यात्रा में आते हैं और परिणामस्वरूप प्लास्टिक कूड़ा अत्यधिक बढ़ जाता है। शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन रूद्रप्रयाग द्वारा रिसाइकल संस्था के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी के लिए तकनीकी समाधानों की आपूर्ति हेतु एक अभिनव पहल की गयी।

'डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम' (डिजिटल डी0आर0एस0) नामक पहल, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में भी परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य बेची गई प्रत्येक प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की वस्तु को इकट्ठा करके संग्रह प्रणाली में वापस लाना है जिससे की प्लास्टिक कूड़ा पर्यावरण को हानि न पहुंचा पाये।

डिजिटल डीआरएस पहल सबसे पहले जनपद रूद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में लागू की गई थी। इस पहल ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर तीर्थयात्रियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे स्थानीय नागरिकों, खुदरा विक्रेताओं और मीडिया से भी भरपूर सराहना मिली, साथ ही इस अभिनव प्रयोग को तकनीकी समाधान के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ। इस प्रणाली के उपयोग करने के लिए यूनिक सीरियलाइज्ड कोड (यू0एस0आई0) वितरित किए जाते हैं। इन यू0एस0आई0 कोड को इन बोतलों की पैकेजिंग पर चिपका दिया जाता है। डी0आर0एस0 प्रणाली में उपभोक्ता प्लास्टिक की बोतलें खरीदते हैं और डिपॉजिट के तौर पर 10 रूपये जमा करते हैं जो की पूरी तरह से वापसी योग्य है। जब उपभोक्ता यात्रा मार्ग पर स्थापित संग्रह बिंदुओं पर खाली बोतलें लौटाते हैं तब इस राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

इस वर्ष डिजिटल डी0आर0एस0 का विस्तार अन्य धामों– गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इन तीन धामों से डिजिटल डीआरएस के जरिए रु0 16.00 लाख बोतलें 70 प्रतिशत की पुनर्प्राप्ति दर के साथ इकट्ठा करके रीसाइक्लिंग के लिए भेजी गयी है।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी की प्रमुख उपलब्धियां व सफलतम प्रयास

- 89 निकायों की 62 परियोजनाओं की स्वीकृति व धनराशि प्राप्त।
- कुल उत्पादित अपशिष्ट के 90 प्रतिशत् का प्रसंस्करण प्रारम्भ।
- 102 निकायों में डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण प्रारम्भ।
- 85 प्रतिशत् वार्डों में कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन प्रारम्भ।
- 08 स्वच्छ सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 19 अवार्ड प्राप्त।
- स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य को 02 बार तृतीय स्थान प्राप्त।
- स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुल 02 पुरस्कार प्राप्त हुए।
- एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में देहरादून व एक लाख से कम जनसंख्या वाली निकायों में मुनि की रेती का उत्तराखण्ड में स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- 100 निकायों से कम वाले राज्यों की श्रेणी में राज्य को 19 वां स्थान प्राप्त हुआ।
- राज्य में अब तक 52 निकाय ओ0डी0एफ0, 30 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस, 04 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस तथा 02 निकाय वाटर प्लस घोषित हुई हैं। 01 निकाय जी0एफ0सी घोषित हुई हैं।

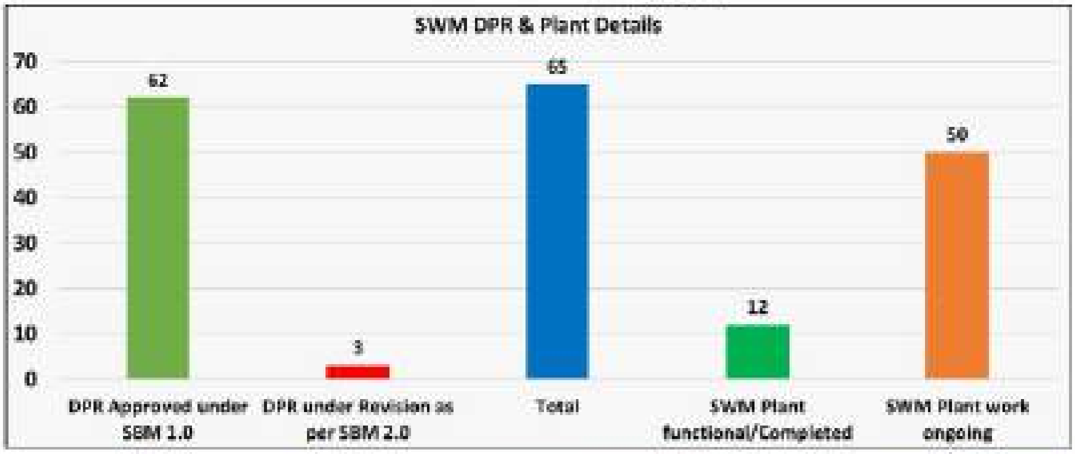

20

सफलतम् प्रयास : उत्तराखण्ड

- आत्मनिर्भर वार्ड : नथुआवाला
- एम0आर0एफ0 मॉडल : हर्रावाला
- एम0आर0एफ0 मॉडल : डोईवाला
- एम0आर0एफ0 मॉडल : रामनगर
- एम0आर0एफ0 मॉडल : हरिद्वार
- डिजिटल डी0आर0एस0 : केदारनाथ
- कचरे से सम्पत्ति : जोशीमठ
- पैणी सेना : हल्द्वानी व बागेश्वर

नगर निगम, देहरादून के स्वच्छता तथा पर्यावरण संतुलन की दिशा में किए गए अनूठी पहल के कार्य।

- कोकोनट से रस्सी, बेड के स्पंज, कंपोस्ट तैयार एंव अन्य और कार्य किये जा रहे हैं। जिसका नगर निगम देहरादून के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण ससमय किया जाता है।
- धार्मिक संस्थाओं मंदिरों गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि में जो श्रद्धालुओं द्वारा फूल मलाये चढ़ाई जाती हैं, उनका नगर निगम, देहरादून के द्वारा प्रोसेसिंग कर अगरबत्तियां, धूपबत्तियां और अन्य सामान बनाए जा रहे हैं।

बैणी सेना : महिला स्वयं सहायता समूह

बैणी सेना महिला स्वयं सहायता समूह नगर निगम, हल्द्वानी में यह योजना 2022 में प्रारम्भ की गयी, जिसमें 58 समूहों के माध्यम से नगर निगम के समस्त 60 वार्डों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यों की निगरानी की जा रही है, साथ ही स्वच्छता को लेकर जनता से निरन्तर संवाद कीये जा रहे हैं। इनके द्वारा रू0 36.00 लाख प्रति माह का यूजर चार्ज एकत्रित किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि का 25 प्रतिशत बैणी सेना को प्रोतसाहन धनराशि के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह कार्य महिला स्वयं सहायता समूह को न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वावलंबन बना रहा है बल्कि महिलाओं को एक नई पहचान भी दिला रहा है।

बैणी सेना : अन्य शहरी निकायों में अनुसरण

- नगर निगम रुद्रपुर (नारी शक्ति सेना):– 16 फरवरी, 2023 से क्रियान्वित। जिसमे 43 समूह की 89 महिलाओं को 41 वार्डों की जिम्मेदारी।
- नगर निगम काशीपुर (शक्ति वाहिनी सेना):– 02 फरवरी, 2023 से क्रियान्वित। जिसमे 16 समूह को 35 वार्डों की जिम्मेदारी।
- नगर पालिका परिषद बागेश्वर (सखी स्वायत सहकारिता संघ):– 49 महिलायें और 2 पर्यवेक्षक नियुक्त।
- 19 मई, 2023 को औपचारिक समझौता हस्ताक्षरित।
- प्रोत्साहन आधारित मॉडल के बजाय निश्चित पारिश्रमिक मॉडल पर आधारित।

अमृत

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (2015–2021)

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप में शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख–सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तरों में सुधार होगा।

उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ हो।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- गैर–मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिये सुविधाओं के निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना।
- बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार करना।

कवरेज

- छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगर पालिका परिषदों सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे।
- (1) में शामिल नही किये गए सभी राजधानी शहर/राज्यों के कस्बों/संघ राज्य क्षेत्र।
- हृदय स्कीम के अर्न्तगत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रुप में वर्गीकृत सभी शहर कस्बे।
- 75000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वले 13 शहरों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारों पर है।
- पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य) से एक से अधिक शहर नही।

अमृत सिटी प्रोफाईल

राज्य में मिशन शहरों का विवरण (7 शहर)

शहर का नाम	जनसंख्या
देहरादून	574840
हरिद्वार	231338
हल्द्वानी–काठगोदाम	201461
रुड़की	184060
रुद्रपुर	154554
काशीपुर	121623
नैनीताल	41377
कुल योग	1509253

- जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या लगभग 1.01 करोड़ है, जिसमें से कुल 30 प्रतिशत जनसंख्या (36,41,029 लाख) शहरी क्षेत्रों में निवासरत् है।
- अमृत शहरों की कुल जनसंख्या 15,09,253 है, जो कि जनगणना, 2011 के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या की 49.49 प्रतिशत है।

कुल/शहरी जनसंख्या	2001	2011	अन्तर	दशकीय विकास 2001.2011
कुल	84,89,349	1,00,86,292	15,96,943	18.8%
शहरी	21,79,074 (25.67%)	36,49,338 (36.23%)	14,70,264	67.5%

आधारभूत परिदृश्य

सभी को सेवाएं प्रदान करने के बेंचमार्क का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर वर्ष 2011 में कराये गये बेसलाईन सर्वे के अनुसार अमृत मिशन शहरों की विभिन्न घटकों की आधारभूत स्थिति निम्नवत् है–

क्र.	शहर का नाम	जलापूर्ति		सीवरेज		स्टार्म वॉटर ड्रेनेज
		परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन	जलापूर्ति की प्रति व्यक्ति मात्रा	शौचालयों की कवरेज	सीवरेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज	जल निकासी नेटवर्क कवरेज
मिशन लक्ष्य		(100%)	(135 lpcd)	(100%)	(100%)	(100%)
1	**देहरादून**	78	135	70	15	11
2	**हरिद्वार**	90	187	87	70	50
3	**हल्द्वानी**	80	133	87	10	41
4	**रूद्रपुर**	11	49	100	0	0
5	**काशीपुर**	15	45	90	22	60
6	**रूड़की**	48.18	109	99.8	23	60
7	**नैनीताल**	80	110	95	80	0
कुल		**57.45**	**109.42**	**89.82**	**31.42**	**31.71**

मिशन के प्राथमिक उद्देश्य के तहत मिषन अवधि के दौरान राज्य अन्तर्गत मिषन शहरों के घटकों में सार्वभौमिक कवरेज (100:) प्राप्त करने के लिए रू0 3200.00 करोड़ की कुल आवश्यकता होगी। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रू0 593.02 करोड़ का धनावंटन किया गया है। शेष रू0 2607.00 करोड़ की पूर्ति युगपतिकरण/अभिसरण कर पूर्ण कर ली जायेगी

वार्षिक कार्य–योजना

अमृत मिशन शहरों द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज, ड्रेनेज, ग्रीनस्पेस/पार्क पर उपलब्ध आंकड़ों, सूचनाओं तथा योजनाओं पर तैयार सेवा स्तरीय सुधार योजना के तदक्रम में वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

मिशन अवधि में वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के सापेक्ष कुल 03 वार्षिक कार्य–योजना तैयार की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

वार्षिक कार्य–योजना (कुल 03 सैप) (रू0 करोड़ में)

SAAP-1 (2015-16)						
क्र0 सं0	शहर का नाम	जलापूर्ति	सीवरेज	ड्रेनेज	ग्रीनस्पेस/पार्क	योग
1	देहरादून	36.50	12.55	6.47	2.00	57.52
2	हरिद्वार	19.00	1.43	0	0.50	20.93
3	हल्द्वानी	10.00	15.88	0	0.30	26.18
4	रूद्रपुर	19.50	0.00	0	0.30	19.80
5	काशीपुर	12.00	9.50	0	0.30	21.80
6	रूड़की	2.00	0.00	0	0.30	2.30
7	नैनीताल	0	0	0	0	0
योग		99.00	39.36	6.47	3.70	148.53

SAAP-2 (2016-17)						
क्र0 सं0	शहर का नाम	जलापूर्ति	सीवरेज	ड्रेनेज	ग्रीनस्पेस/पार्क	योग
1	देहरादून	54.50	21.00	0	2.00	77.50
2	हरिद्वार	2.31	28.69	3.00	0.75	34.75
3	हल्द्वानी	10.00	13.00	0	0.55	23.55
4	रूद्रपुर	14.01	6.90	0	0.50	21.41
5	काशीपुर	10.00	9.99	0	0.41	20.40
6	रूड़की	13.68	0	0	0.42	14.10
7	नैनीताल	0	5.5	0	0.12	5.62
योग		104.5	85.08	3.00	4.75	197.33

SAAP-3 (2017-18)						
क्र0 सं0	शहर का नाम	जलापूर्ति	सीवरेज	ड्रेनेज	ग्रीनस्पेस/पार्क	योग
1	देहरादून	58.00	15.00	7.50	2.26	82.76
2	हरिद्वार	1.66	2.00	7.50	0.84	12.00
3	हल्द्वानी	5.50	26.00	0	0.81	32.31
4	रूद्रपुर	27.56	0	3.50	0.80	31.86
5	काशीपुर	39.97	21.28	0	0.80	62.05
6	रूड़की	18.52	0	0	0.48	19.00
7	नैनीताल	0	0	7.00	0.18	7.18
योग		151.21	64.28	25.50	6.17	247.16
कुल योग (123)		354.71	188.72	34.97	14.62	593.02

अमृत 1.0 परियोजना प्रगति

भौतिक प्रगति					
स्वीकृत परियोजना		पूर्ण परियोजनायें		कार्य प्रगति पर	
संख्या	लागत (करोड़)	संख्या	लागत (करोड़)	संख्या	लागत (करोड़)
151	593.02	128	384.50 cr	23	208.47 cr
100%		84.76%		15.23%	

वित्तीय प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य	स्वीकृत आवंटन (करोड़)	अवमुक्त (करोड़)	प्रतिशत
1	कुल केन्द्रांश अवमुक्त	533.72	531.91	99.66%
2	कुल राज्यांश अवमुक्त	59.30	59.11	99.66%
कुल		593.02	591.02	99.66%

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (रु0 करोड़ में)						
केन्द्रांश अवमुक्त धनराशि	राज्यांश अवमुक्त धनराशि	कुल (केन्द्रांश व राज्यांश)	उपयोगिता प्रमाण–पत्र केन्द्रांश	उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यांश	भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	अभ्युक्ति
531. 91	59.11	591.02	449.17	49.90	499.07	84.44 %

केन्द्रांश–90 प्रतिशत
राज्यांश–10 प्रतिशत

अमृत परियोजनायें – भौतिक प्रगति							
क्र0सं0	निकाय का नाम	स्वीकृत परियोजनायें		पूर्ण परियोजनायें		गतिमान परियोजनायें	
		संख्या	लागत (रु0 करोड़ में)	संख्या	लागत (रु0 करोड़ में)	संख्या	लागत (रु0 करोड़ में)
1	हल्द्वानी	24	82.04	24	82.04	-	-
2	नैनीताल	7	13	6	7.86	1	4.97
3	हरिद्वार	33	68	32	64.94	1	2.34
4	देहरादून	37	218	33	149.16	4	68.59
5	रुड़की	12	35	10	31.05	2	4.40
6	रुद्रपुर	18	73	12	16.86	6	56.62
7	काशीपुर	20	104	11	32.59	9	71.55
कुल योग		**151**	**593**	**128**	**384.50**	**23**	**208.47**

भौतिक प्रगति (प्रतिशत)						
क्र0सं0	विवरण	संख्या	%	धनराशि (करोड़ में)	%	कार्य पूर्ण होने की समय–सीमा
1	पूर्ण परियोजनायें	128	84.76%	384. 50	64.84	-
2	परियोजनाओं की प्रगति (76–99 प्रतिशत)	18	11.92%	197.25	33.26	मार्च, 2024
3	परियोजनाओं की प्रगति (51–75 प्रतिशत)	2	1.32%	3.28	0.55	मार्च, 2024
4	परियोजनाओं की प्रगति (26–50 प्रतिश)	1	0.66	3.15	0.53	मार्च, 2024
5	परियोजनाओं की प्रगति (0–25 प्रतिशत)	2	1.32%	4.79	0.80	मार्च, 2024
कुल योग		**151**	**100**	**593**	**100**	

जी0आई0एस0 आधारित मास्टर प्लान –भौतिक प्रगति				
क्र0 सं0	शहर का नाम	ड्राफ्ट मास्टर प्लान	प्रदर्शिनी / आपत्ति एवं सुझाव	अन्तिम रिपोर्ट (नोटिफाईड मास्टर प्लान)
1	देहरादून	पूर्ण	पूर्ण	गतिमान
2	हरिद्वार	पूर्ण	गतिमान	गतिमान
3	काशीपुर	पूर्ण	पूर्ण	गतिमान
4	रुद्रपुर	पूर्ण	पूर्ण	गतिमान
5	हल्द्वानी	पूर्ण	गतिमान	गतिमान
6	नैनीताल	पूर्ण	गतिमान	गतिमान
7	रुड़की	पूर्ण	गतिमान	गतिमान

जी0आई0एस0 आधारित मास्टर प्लान –भौतिक प्रगति						
क्र0 सं0	किश्त	विवरण	%	मास्टर प्लान (रु0 लाख में)	Capacity Building (CA+SA)	भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण (रु0 लाख में)
1	प्रथम किश्त	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	20	105.0	4.2	Rs. 94.36
2	द्वितीय किश्त	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	40	102.0	8.4	Rs 163.81
3	तृतीय किश्त	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	20	69.09	4.2	Rs 221
4	चतुर्थ किश्त	भारत सरकार से अवमुक्त होने वाली धनराशि	20	69.09	4.2	demand send to GoI
कुल (रु0 लाख में)			100	345.5	21.0	366.5

*Note: In fourth installment to be released after submission of final notified master plan.

अमृत–2.0 (2021–2026)

क्र0सं0	फंडिग पैटर्न	रु0 करोड़ में
1	**केन्द्रांश (90 प्रतिशत)**	585.00
2	**राज्यांश (10 प्रतिशत)**	65.00
कुल योग		**650.00**

चयन प्रक्रिया			
क्र0सं0	**विवरण**	**नगर निकायों की संख्या**	**वित्तीय अनुदान**
1	पेयजल निगम हेतु चयनित शहर	38	JICA (1804 cr)
2	यू0यू0एस0डी0ए0 हेतु चयनित शहर	16	ADB/EAP* (Rs 6820 cr)
3	जलापूर्ति संतृप्त शहर	7	ADB/ JnNURM etc
4	एस0पी0ए0 सहायतित चयनित शहर (मसूरी)	1	SPA
5	ट्रेंच–1 आच्छादित शहर	19 (18+1(24*7 water supply))	AMRUT 2.0 (Rs 233.74 cr)
6	ट्रेंच–2 आच्छादित शहर	22	AMRUT 2.0
7	कुल नगर निकाय ट्रेंच–3 आच्छादित शहर	09	AMRUT 2.0
8	नवीन नगर निकाय (नगला, रामपुर, सुल्तानपुर)	03	-
कुल योग–		**112**	

*ADB/EAP- Proposed to provide Water suppy and sewerage/septage in all 16 ULBS

अमृत 2.0 जी0आई0एस0 आधारित मास्टर प्लान

द्वितीय श्रेणी के शहर–(जनसंख्या 50,000–99,999)

अमृत 2.0 के अन्तर्गत चयनित शहर	
क्र0सं0	शहर
1	**डोईवाला**
2	**मंगलौर**
3	**पिथौरागढ़**
4	**रामनगर**
5	**जसपुर**
6	**किच्छा**
7	**खटीमा**
8	**नगला**
9	**कोटद्वार**
10	**ऋषिकेश**

क्र0सं0	घटक	केन्द्रांश (रु0 लाख)	राज्यांश (रु0 लाख)	योग (रु0 लाख)
1	भू डाटाबेस निर्माण	82.26	0.00	**82.26**
2	मास्टर प्लान तैयार करना	710.00	0.00	**710.00**
3	क्षमता अभिवृद्धि	20.00	-	**20.00**
कुल एस0ए0पी0		**812.3**	**00**	**812.3**

रु0 8.12 करोड़ केन्द्रांश प्राविधानित है।

अमृत 2.0 उपयोजना अंतर्गत श्रेणी-3 के 13 अतिरिक्त नगरों (क्रमशः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टनकपुर, विकासनगर, लक्सर, श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर, उत्तरकाशी) की महायोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

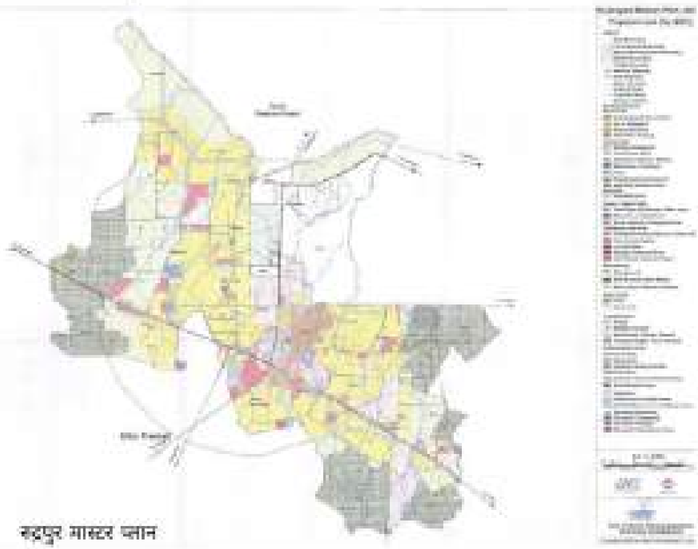

रुद्रपुर मास्टर प्लान

32

अमृत 2.0 कार्य योजना

Key Activities

- केंद्र, राज्य और यू0एल0बी0 के मध्य समझौता ज्ञापन ।

Completed

- राज्य एवं यूएलबी स्तर पर अमृत 2.0 के लिए समिति का गठन ।
- शहरी जल संतुलन योजना सी0डब्ल्यू0बी0पी0 दिनांक 15.02.2024 को पूरी हुई ।
- सी0डब्ल्यू0बी0पी0 शहरी जल संतुलन योजना को अमृत 2.0 पोर्टल पर अपडेट किया गया।
- यू0एल0बी0 का गैप विश्लेषण ।
- गैप विश्लेषण के आधार पर यूएलबी का पृथक्करण।
- शहरी जल कार्य योजना /सी0डब्ल्यू0ए0पी– ट्रेंच–1 को अंतिम रूप देना।
- राज्य जल कार्य योजना – शीर्ष समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
- एपेक्स समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी– ट्रेंच–1 में रु0 233.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी । (18+1) नगरों के लिए स्वीकृत और 20 प्रतिशत पहली किस्त रु0 46.75 करोड़ की प्रथम किश्त उत्तराखण्ड शासन को भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अमृत 2.0 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त रु0 93.49 करोड़ अवमुक्त करने का अनुरोध भारत से किया गया है।

Ongoing

19 परियोजनाओं में से –08 परियोजनायें प्रगति पर तथा 02 परियोजनाओं की निविदा प्रगति पर है। 6 परियोजनायें ईएफसी हेतु शासन को प्रेषित हैं। शेष 2 योजनाओं में से 1 परियोजना टीएसी के लिए प्रेषित की गयी है तथा 1 परियोजना संशोधन प्रक्रिया के तहत है।

Future Plan

निविदा जारी . 02

निष्पादन .08

संचालन एवं रखरखाव . 0

जल निकायों (वॉटर बॉडीज) का कायाकल्प

- 102 निकायों में 93 वॉटर बॉडीज को पुनर्जीवन के लिये चिन्हित किया गया है।
- 20 अमृत सरोवर तैयार किये जा चुके है।
- 13 वॉटर बॉडीज में आयुक्त (गढ़वाल/कुमाऊ), जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही गतिमान है (डोडीताल–उत्तरकाशी, नैनीताल झील, सरियाताल–नैनीताल, मसूरी झील, नौकुचियाताल, भीमताल, खुर्पाताल, सात ताल, संतोपथ सरोवर–गोपेश्वर, रानीझील–रानीखेत, नचिकेताताल–उत्तरकाशी)
- सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे 15वें वित्त आयोग कोष का उपयोग जल निकायों के कायाकल्प के लिये करें।

फोटो गैलेरी

हल्द्वानी

28 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी

अम्बेडकर पार्क हल्द्वानी

<u>Under Urban green Space Component Construction of Children park at Gandhi park and Phase-II Dehradun work</u>

एफ0एस0टी0पी0 रूद्रपुर

नैनीताल

रूद्रपुर

हरिद्वार

प्रधान मंत्री
आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी

प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी (पीएमएवाई–यू), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एम०ओ०एच०यू०ए०) भारत सरकार, द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम 25 जून 2015 को प्रारम्भ किया गया था। मिशन द्वारा ई०डब्ल्यू०एस०/एल०आई०जी० व एम०आई०जी० श्रेणी के अभ्यर्थियों की आवास माँग को पूरा कराना है। मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित समस्त श्रेणियों के लाभार्थियों को लाभांवित करना था, वर्तमान में मिशन को दिसम्बर 2024 तक बढ़ाया गया है। पीएमएवाई (यू) माँग आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है, जिसमें राज्य/यूएलबी आवास मांग के आकलन कर, आवास की आवश्यकता का आंकलन करते है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एस०एल०एन०ए०), शहरी स्थानीय निकाय (यू०एल०बी०)/कार्यान्वयन एजेंसियां (आई०ए०) यथा प्राधिकरण, केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सी०एन०ए०) और प्राथमिक ऋण संस्थान (पी०एल०आई०) मुख्य हितधारक हैं। जो पीएमएवाई (यू) के क्रियान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिशन समस्त शहरी क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है, जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। पीएमएवाई (यू) के तहत घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं होना आवश्यक है। मिशन महिला सदस्य के नाम या संयुक्त नाम पर मकानों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है। पीएमएवाई (यू) आवास का उद्देश्य लाभार्थियों को सुरक्षा की भावना और स्वामित्व के गर्व के साथ–साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित करता है।

क) मिशन अंतर्गत आवास चार घटक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है–

1. स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास

घटक अंतर्गत भूमि को संसाधन के रुप में प्रयोग करते हुए निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ पात्र स्लम परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाता है, घटक अंतर्गत रु0 1.00 लाख की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पुनर्विकास के बाद, राज्य द्वारा मलिन बस्ती की अधिसूचना रद्द करनी होती है। स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास घटक अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाये जाने के लिए राज्य अतिरिक्त एफएसआई/एफएआर या टीडीआर प्रदान कर सकते हैं। निजी स्वामित्व वाली भूमि पर झुग्गियों के लिए, राज्य अपनी नीति के अनुसार भू–स्वामी को अतिरिक्त एफएसआई/एफएआर या टीडीआर प्रदान कर सकते हैं, ऐसे मामले में कोई केंद्रीय सहायता स्वीकार्य नहीं है। घटक अंतर्गत राज्य में कोई परियोजना स्वीकृत नही की गई है।

38

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी

2.क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना–
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्य आय वर्ग (एमआईजी)–1 और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी)–2 के लाभार्थी जो बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और ऐसे अन्य संस्थानों से नए आवास क्रय करने के लिए आवास ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हे आवासों के निर्माण या वृद्धि हेतु ऋण राशि रु. 6 लाख, रु. 9 लाख और रु 12 लाख क्रमशः के ऋण पर 6.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करयी जाती है। भारत सरकार द्वारा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में नामित किया है, ताकि लाभार्थियों को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जा सके और प्रगति की निगरानी की जा सके। वर्तमान में घटक को समाप्त कर दिया गया है। घटक अंतर्गत राज्य में 20134 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया है तथा 17174 लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी के रुप में रु. 350 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायी गई है। घटक अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सी0एल0ए0पी0 पोर्टल विकसित किया है ताकि सी0एल0एस0एस0 घटक के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा लाभार्थियों को मिलने वाली ऋण सब्सिडी की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

3.भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
घटक अंतर्गत रु. 1.5 लाख की केंद्रीय सहायता तथा रु. 1.00 लाख की राजकीय सहायता प्रति ईडब्ल्यूएस आवास उपलब्ध करायी जाती है। किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के आवासों का मिश्रण हो सकती है, लेकिन केंद्रीय सहायता के लिए परियोजना तभी पात्र होगी, यदि परियोजना में कम से कम 35 प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु निर्मित किये जाये। राज्य ईडब्ल्यूएस आवासों के अधिकतम् बिक्री मूल्य तय करेंगें, ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी द्वारा आवास लागत वहन की जा सके और इच्छित लाभार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें। इस घटक में परियोजनाओं को प्राधिकरण/यू0एल0बी0 अथवा पी0पी0पी0 पार्टनर के माध्यम से भारत सकरार को प्रस्तुत किया जाता है, घटक अंतर्गत राज्य परियोजना हेतु अन्य सुविधाएं यथा राज्यांश, सस्ती लागत पर जमीन, स्टाम्प शुल्क में छूट आदि भी उपलब्ध कराता है। घटक अंतर्गत राज्य में 17304 आवासों की 21 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है तथा 15960 आवासों की 20 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 8565 आवास लाभार्थियों को आवंटित भी किये जा चुके है।

4.लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (बीएलसी–एनसी/बीएलसी–ई)
घटक अंतर्गत ऐसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को लाभांवित किया जाता है जिनके पास आवास निर्माण हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है। घटक अंतर्गत आवास निर्माण हेतु रु. 1.50 लाख केन्द्रांश तथा रु. 0.50 लाख राज्यांश के रुप में लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त घटक अंतर्गत आवास वृद्धि हेतु भी पात्र परिवारों को आवास की वृद्धि अधिकत् 30 वर्ग मी0 के लिए केन्द्रांश सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी

शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण यथा भूमि का स्वामित्व, आर्थिक स्थिति और पात्रता का सत्यापन कर परियेाजना प्रस्तुत करते है जिसके आधार पर केन्द्रीय व राज्य की आर्थिक सहायता निर्गत की जाती है। लाभार्थियों को धनराशि लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से बैंक खातों में अन्तरित की जाती है। घटक अन्तर्गत राज्य में 25760 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जा चुकी है। तथा 16797 लाभार्थियों के आवास निर्माण का कार्य गतिमान है जिनमें से 9653 आवासो के निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। घटक अंतर्गत रु. 236.64 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की गई है। जिसमें से रु. 200. 00 करोड़ की धनराशि को लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

ख) प्रवासी श्रमिकों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसर (एआरएचसी)–

कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में शहरी प्रवासियों/गरीबों का इन मॉइग्रेशन हुआ है। आवास पर लागत बचाने के लिए शहरी प्रवासी मलिन बस्तियों/अनौपचारिक बस्तियों/अनधिकृत कॉलोनियों/अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए विवश थे। उन्हें अपने कार्य स्थलों के समीप उचित किराये के आवास की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पी0एम0एवाई0–यू) के तहत एक उप–योजना, किफायती किराये के आवास परिसरों (ए0आर0एच0सी0) की शुरुआत की, यह औद्योगिक क्षेत्र में शहरी प्रवासियों/गरीबों के साथ–साथ गैर–औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में उनके कार्यस्थल के समीप प्रतिष्ठित किफायती किराये के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक है।

उपघटक अन्तर्गत राज्य में पूर्व निर्मित 06 परियोजनओ को चिन्हित 512 आवासों को ए0आर0सी0एच0 अंतर्गत चिन्हित किया गया। वर्तमान तक देहरादून, लालकुआँ तथा मसूरी के 202 आवासों का आवंटन योजना की दिशा–निर्देशों के अनुसार कर लिया गया है।

ए0आर0एच0सी0 योजना दो मॉडलों के माध्यम से लागू की जानी प्रस्तावित थी

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली मकानों का उपयोग करना।
2. सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली जमीन पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रख रखाव करना।

आवास योजना से पूरी हुई घर बनाने की उम्मीद

मेरा नाम रिंकी देवी पत्नी श्री लाला राम है, मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूँ, मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आयी। मेरी शादी को 18 वर्ष हो चुके है, मेरे 02 पुत्र हैं। एक इण्टर क्लास मे व दूसरा 07वीं मे सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है। हम पति/पत्नी दोनों दिहाडी की मजदूरी कर अपना गुजरबसर करते हैं। दिन–रात मजदूरी कर हमारे द्वारा 'गौजाजाली बिचली', वार्ड संख्या 60 में 616 वर्गफिट का प्लाट खरीदा। तदपरान्त हमारे द्वारा इस भूमि में एक झोपडी बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। 17 सितम्बर, 2017 को घर में गैस सिलेण्डर फटने से झोपडी में आग लगाने से, झोपडी सहित सारा समान जल गया। उसके बाद गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। हमारे पडोसियों द्वारा सहयोग कर हमें कुछ रोजमर्रा का समान उपलब्ध कराया गया। रहने के लिए फिर हमारे द्वारा तिरपाल लगाकर 01 वर्ष तक गुजारा किया गया, इस दौरान गर्मियों में हवा से तिरपाल उड जाने, बरसात में झोपड़ी के अन्दर पानी भर जाने व सर्दियों में जाडे से काफी परेशानी झेलनी पडी। फिर हमें हमारे पार्षद श्री मनोज मठपाल व मा. मेयर डा. जोगन्द्र पाल सिंह रौतेला द्वारा नगर निगम, हल्द्वानी कार्यालय मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने हेतु कहा गया। नगर निगम, हल्द्वानी में श्री सुरेश अधिकारी, सामाजिक विकास अधिकारी द्वारा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी व मेरा आवेदन भरवाया गया। मुझे नगर निगम कार्यालय द्वारा 04 किस्तों में रु. 2.00 लाख उपलब्ध कराये गये। मेरे द्वारा योजना के तहत 02 कमरे, 01 लॉबी, 01 किचन व 01 शौचालय निर्मित किया गया है।

लाभार्थी का संक्षिप्त विवरण

लाभार्थी नाम – रिंकी देवी
पति का नाम – लालाराम

अनुमन्य कारपेट एरिया – 30 वर्गमी

लागत – 4.80 लाख

केन्द्रांश – 1.50 लाख

राज्यांश – 0.50 लाख

लाभार्थी अंशदान – 2.80 लाख
अनुदान भुगतान माध्यम् प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी०बी०टी०)

हम दोनों अन्यत्र दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं व हम पति/पत्नी द्वारा रात को स्वयं काम कर अपने मकान का निर्माण कार्य किया गया। जब मैंने अपने आस–पडोस में मकान बनाने की बात कही तो सभी मेरा मजाक बना रहे थे कि ये कैसे मकान बनायेगी, परन्तु आज मेरा मकान पूर्ण हो चुका है, मैं मकान की मालकिन होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अब मेरे रिश्तेदारों की नजरों में भी मेरा मानसम्मान बढ़ चुका है, बच्चों के रहने की लिए अलग से कमरा है।

हम अपने परिवार की ओर से नगर निगम, हल्द्वानी व मा. प्रधानमंत्री, भारत सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं।

व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) की लाभार्थी श्रीमती रिंकी देवी

आवास योजना से पूरी हुई घर बनाने की उम्मीद

मेरानाम कविताराय है। मैं जनपद ऊधमसिंह नगर में नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 मे निवास करती हूँ। मैं और मेरे पति एक दैनिक श्रमिक का कार्य करते थे। हमारे परिवार में 02 लडकियों सहित हम कुल 04 लोग रहते थे। हमारे पास रहने को एक कच्चा मकान था जिसमें बरसात के मौसम में आंगन में जलभराव होने व छत से पानीटपकने के कारण हम लोगो की 3 से 4 महीनों की जिन्दगी काफी मुश्किलों भरी रहती थी साथ ही हमारे घर का राशन भी पानी के कारण खराब हो रहा था। जिस कारण हम आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे थे। बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सुना तथा नजदीकी जन सेवा केन्द्र में जाकर नया आवास पाने के लिए आनलाईन आवेदन किया।

लाभार्थी का संक्षिप्त विवरण

लाभार्थी कोड – 058003490274600017

लाभार्थी नाम – कविता राय

अनुमन्य कारपेट एरिया – 30 वर्गमी

लागत – 3.53 लाख

केन्द्रांश – 1.50 लाख

राज्यांश – 0.50 लाख

लाभार्थी अंशदान – 1.53 लाख

व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया)
लाभार्थी श्रीमती कविता राय

पक्के घर की दहलीज पर पहला कदम–

आवेदन करने के उपरान्त हमें वित्तीय वर्ष 2015–16 मेंनगर पंचायत से सूचना मिली कि हमारा नया आवास स्वीकृत हो गया है तथा हमसे कुछ औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त नया आवास का कार्य प्रारम्भ करने को कहा गया। नगर पंचायत द्वारा पहली किस्त जारी करने के साथ ही हमने शीघ्र ही अपने घर का कार्य आरम्भ कर दिया। परन्तु बीच में ही मेरे पति की मृत्यु होने के कारण हम लोगों की आजीविका पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिस कारण मैं लगभग एक वर्ष तक अपने मकान की छत नहींडाल सकी। बड़ी मुश्किल से मैंने विधवा पेंशन, दैनिक मजदूरी के बलबूते तथा आवास योजना की किस्तों के चलते अपने घर को पूरा किया। जिससे मुझे और मेरी लड़कियों को सुरक्षा के साथसाथ अपने स्वामित्व के आवास का लाभ मिला। काश मेरे पति भी मेरे साथ इस पक्के घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रख पाते।

आवास आवंटन एवं निर्मित आवास

निर्मित व्यक्तिगत आवास (नया)

मा मंत्री जी द्वारा आवास आवंटन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है। मिशन के विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। मिशन शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

1– सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास

त्रिस्तरीय संरचना (स्वयं सहायता समूह–क्षेत्र स्तरीय संघ–नगर स्तरीय संघ) का निर्माण, एस0एच0जी0 –ए0एल0एफ0 –सी0एल0एफ0 स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संघ को क्रमशः रू0 10 हजार तथा 50 हजार की आवर्ती निधि का सहयोग एवं शहरी गरीब आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु 10 लाख प्रति केन्द्र की अनुमन्यता।

योजना के प्रारम्भ से आतिथि तक 3837 महिला स्वयं सहायता समूहों एवं 138 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं 2660 समूहो एवं 66 क्षेत्र स्तरीय संघ को आवर्ती निधि।

नगर निकाय चम्पावत, रूद्रपुर एवं टनकपुर में नगर आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का संचालन प्रारम्भ।

2– स्व–रोजगार कार्यकम–

व्यक्तिगत् उद्यम हेतु 07 प्रतिशत की दर पर अधिकतम् रू0 2.00 लाख ऋण तथा समूह उद्यम (अधिकतम् 5 सदस्य) हेतु 07 प्रतिशत की दर पर अधिकतम् रू0 10.00 लाख ऋण। योजना के प्रारम्भ से आतिथि तक 8666 लाभार्थियों को रू0 122.50 करोड़ के ऋण की स्वीकृति एवं वितरण।

3– शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता–

फेरी व्यवसायी, तथा वेण्डर जोन को चिन्हित किये जाने हेतु नगर स्तरीय फेरी व्यवसाय सर्वेक्षण करना, पहचान पत्र तथा फेरी बाजारों का विकास। नगर निकाय में फेरी क्षेत्रों, स्थानों अथवा बाजारो का चिन्हांकन तथा सीमांकन नगरीय फेरी समिति द्वारा गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र, नियंत्रित फेरी क्षेत्र एवं फेरी रहित क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। योजना के प्रारम्भ से आतिथि तक 20297 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 19908 वेण्डर को पहचान पत्र वितरित।

4– शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना

प्रति 01 लाख शहरी जनसंख्या तथा जिला मुख्यालय मे स्थायी सामुदायिक आवासो/रैन बसेरा का निर्माण। रैन बसेरे में 50 से 100 व्यक्तियों के निवास एवं अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एव 10 प्रतिशत लाभार्थी वृद्ध, दिव्यांग अथवा विधवाओं हेतु आरक्षित। प्रति व्यक्ति न्यूनतम् 5 वर्ग मी0 अथवा 50 वर्ग फिट की उपलब्धता। योजना के प्रारम्भ से आतिथि तक रू0 788.04 लाख के 14 रैन बसेरा प्रस्तावों को स्वीकृति। जिसमें से 12 रैन बसेरे का संचालन, 01 का निर्माण पूर्ण एवं 01 रैन बसेरा (बागेश्वर) निर्माणाधीन।

5–कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार

योजना के प्रारम्भ से आतिथि तक 21373 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 7967 को वैतनिक रोजगार से तथा 607 को स्वरोजगार से जुड़ाव।

45

डे0–एन0यू0एल0एम0 योजना से हुए सपने साकार

नगर पालिका परिषद् बागेश्वर द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत ज्वाला देवी वार्ड में जय श्रीकृष्णा स्वंय सहायता समूह का गठन किया गया। समूह में 10 गरीब महिला सदस्य हैं जिनका खाता बैंक ऑफ इण्डिया बागेश्वर में है। समूह की प्रति महिला द्वारा रू0 200.00 कुल बचत रू0 2000.00 समूह खाते में प्रति माह जमा किये जाते हैं एवं समूह गठन के तीन माह पश्चात् डे–एन0यू0एल0एम0 के पैसा पोर्टल के माध्यम से समूह को रू0 10000.00 का रिवाल्विंग फण्ड भी मिला है, जिससे समूह के खाते में अब तक की कुल बचत रू0 64000.00 हो चुकी है। समूह गठन के एक वर्ष पश्चात् रू0. 1,12000.00 की बैंक द्वारा लिमिट भी बनाई गयी है।

समूह द्वारा स्थानीय मेलों में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का विक्रय किया जा रहा ह। इसके अतिरिक्त समूह द्वारा स्थानीय होटलों, दुकानों में भी अचार का विक्रय किया जा रहा है। समूह द्वारा प्रति माह लगभग रू0. 5000.00 के आचार का विक्रय किया जा रहा है। समूह के सभी सदस्य डे–एन0यू0एल0एम0 व पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना से बहुत खुश हैं कि उन्हें अपनी आजीविका को बढ़ाने हेतु यह धनराषि मिली जो उनकी आजीविका वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। जय श्री कृश्णा स्वंय सहायता समूह की इस सफलता को देखकर डे–एन0यू0एल0एल0 के अन्तर्गत गठित समूह की सभी महिलायें स्वरोजगार करने हेतु प्रेरित हो रही है।

जय श्री कृष्णा स्वंय सहायता समूह को प्रेरणा स्वायत्त सहकारिता समिति में पंजीकृत किया गया है। समूह की महिलायें स्वेटर बिनने का कार्य, डेयरी प्रोडेक्ट, एवं अचार बनाकर उसे विक्रय करने का कार्य अपने समूह खाते से अन्तः ऋण एवं सी0सी0एल0 से ऋण लेकर अपनी आजीविका को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे कि पी0एम0एफ0एम0ई0 योजनान्तर्गत समूह सदस्यों को योजना के विषय में समझाये जाने पर समूह के 09 सदस्यों द्वारा अचार के उत्पाद का व्यवसाय करने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत ऑनलाइन आवेदन करने पर समूह को रू0. 3,60,000.00 पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना से स्वीकृति हुये। जिस धनराशि से समूह ने अचार उत्पादन को वृहद विस्तार देने हेतु उपकरण व कच्चा माल खरीदा। समूह की महिलाओं द्वारा नीबू, मिर्च, आम, कटहल, अदरक, लहसुन इत्यादि का अचार बनाकर विक्रय करने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। समूह के अथक प्रयासों के उपरान्त माह जनवरी 2024 में उनके द्वारा लगभग रू0 1,00000.00 के अचार, नमकीन, धूप, पहाडी पिठां इत्यादि का विक्रय किया गया जिससे धनराशि रू0 50,000.00 का शुद्ध लाभ हुआ।

कामयाबी की बुलन्द आवाज दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन

समूह का नाम – माँ वैष्णो आजीविका स्वयं सहायता समूह
योजना का नाम – दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
गठन की तिथि/वर्ष – 15/7/2021
पता – कचहरी वार्ड नगर पालिका परिषद लोहाघाट।
नगर निकाय – नगर पालिका परिषद लोहाघाट ।

केन्द्र पोषित योजना के तहत दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद लोहाघाट, कचहारी वार्ड में माँ वैष्णो आजीविका स्वयं सहायता समूह का वर्ष 2021 में 22 महिलाओं के समूह का गठन किया गया। समूह गठन के उपरान्त नगर पालिका द्वारा उक्त समूह को आत्म निर्भर बनने हेतु योजनाओं से जुड़े लाभ की जानकारी दी गयी तथा उक्त समूह को आर्थिक विकास एवं व्यवसायिक गतिविधि हेतु रिवोल्विंग फण्ड रु0 10000.00 वितरित किया गया, जिससे समूह की महिलाओं द्वारा नगर पालिका से प्राप्त धनराशि से घर पर ही कढ़ाई बुनाई से नमूने तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को तैयार किया गया। जिससे महिलाओं की प्रथम मासिक आय रु0 8,500.00 धनराशि का व्यवसाय किया गया।

उक्त समूह द्वारा निरन्तर प्रयास के बाद महिलाओं के उत्पादों के विक्रय में बढ़ोत्तरी होने लगी जिससे समूह की महिलाओं द्वारा सी0सी0एल0 हेतु बैंक में आवेदन किया गया तत्पश्चात बैंक द्वारा समूह को एक लाख का ऋण दिया गया। वर्तमान में जिससे महिलाओं द्वारा ऊनी वस्त्र एवं ऊन के गणेष, टैडी बियर, ऊनी स्वेटर इत्यादि बनाये जाते है तथा हिमालयन ब्लूम के नाम से स्टॉल व ऑनलाईन के माध्यम से यूरोप एवं अन्य देषों में विक्रय किया जाता है। उक्त समूह द्वारा वर्तमान तक लगभग पाँच लाख रूपये तक का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन किया जा चुका है।

स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम.....................
नगर निगम हरिद्वार

दिनांक 09/11/2023 को जिलाधिकारी एवं महापौर नगर निगम हरिद्वार की अध्यक्षता मे डे0एन0यू0 एल0एम0 के अन्तर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे उत्पादो की ब्रिकी हेतु दीपावली मेले का उदघ ाटन किया गया।

महिलाओ द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद जैसे की गोबर से बने दीये, धूपबत्ती, अगरबत्ती, जूट के बैग, हैंडीकाफ्ट की वस्तुऐं आदि को बढावा मिल सके। उक्त तीन दिवसीय मेले मे महिलाओ को निशुल्क स्टॉल आवंटन किये गए जिसमे महिलाओ द्वारा कुल रू0 1,26,169/– की ब्रिकी की गयी।

दीपावली मेला हरिद्वार

48

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा देने की अभिनव पहल नगर निगम हरिद्वार

दिनांक 18/09/2023 को ऋषिकुल ओडिटोरियम मे जनपद हरिद्वार मे डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहो हेतु शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मा0 शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल द्वारा की गयी। जिसमे जनपद हरिद्वार की समस्त नगर निकायो मे से पंजीकृत कुल 45 महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादो की प्रदर्शनी एवं प्रतिभाग किया गया जिसमे समूह की महिलाओ द्वारा हस्त कला के उत्पाद, जूट के बैग, दोने–पत्तल, प्रसाद, चटाई, मन्दिरो मे चढाये गए फूलो से निर्मित धूपबत्ती, अगरबत्ती एवं वरमी कम्पोस्ट आदि के स्टॉल लगाये गए।

आजीविका मेला

समूह की महिलाओं के स्वरोजगार हेतु नगर आजीविका केन्द्र (नगर पालिका परिशद टनकपुर)

केन्द्र पोषित योजना द्वारा संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) के घटक सामाजिक संगठन एवं संस्थागत विकास (एस0एम0आई0डी0) के तहत गठित महिला स्वंय सहायता समूहों के आर्थिक विकास मे सहयोग किये जाने हेतु स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादो को बाजार उपलब्ध कराने एवं उत्पादो को नियत स्थान प्राप्त करने हेतु व शहरी गरीबो को रोजगार में सहयोग प्रदान करने हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर द्वारा नगर आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की स्थापना की गयी है। जिसका उदघाटन मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलो द्वारा दिनांक 30.08.2023 को किया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सी0एल0सी0 सेन्टर का उद्घाटन

नगर आजीविका केन्द्र नगर पालिका टनकपुर के अन्तर्गत गठित स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु उचित सहयोग प्रदान कर रहा है। जिससे नगर की स्वंय सहायता समूह की महिलाओं के व्यसाय में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है।

सी0एल0सी0 सेन्टर टनकपुर

योजना की उल्लेखनीय प्रगति

आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु जून, 2023 को कोच्ची (केरल) में दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) की स्पार्क रैंकिंग में हिमालयन एवं पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य के तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

हिमालयन एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्पार्क रैंकिंग में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए

योजना की राज्य में अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने एवं पूरे भारत वर्ष में राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोच्वी में राज्य को सम्मानित किया गया।

स्पार्क रैंकिंग भारत वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए

पी0एम0 स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना
योजना अवधि (01 जुलाई 2020 – 31 दिसम्बर 2024)

पी0एम0 स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0 स्वनिधि)

- कार्यशील पूंजी के रुप में रु0 10,000/- ऋण की सुविधा।
- ऋण अवधि एक वर्ष के लिये व मासिक ऋण वापसी की सुविधा।
- शुन्य ब्याज दर पर आधारित ऋण।
- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन, (रू0 100/प्रतिमाह कैश बैक) की सुविधा।
- ससमय या जल्द ऋण वापसी पर अगले अधिक कार्यशील पूंजी (रू0 20,000/50,000) ऋण की सुविधा।

पी0एम0स्वनिधि लाभार्थियों के बच्चों को सम्मान

योजना सभी नगरीय निकायों में 02 जुलाई, 2020 से प्रारम्भ की गयी है आतिथि तक कुल 43724 फेरी व्यवसायियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये गया है, जिसमें से बैको द्वारा कुल 33534 आवेदन पत्रों को धनराशि 47.02 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

पी0एम0 स्वनिधि योजना से बढ़ता व्यवसाय.........

डे–एन0यू0एल0एम0 नगर पालिका परिषद् बागेश्वर की फेरी व्यवसायी श्रीमती प्रेमा के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में रू.10000.00 ऋण लिया गया। दस हजार का ऋण चुकता करने के बाद रू0 20000.00 बीस हजार का ऋण लिया गया तथा उसे चुकता कर तृतीय चरण में रू0 50000.00 (पचास हजार) का ऋण लेकर उसने अपने फड़ में रखे गये सामान की मात्रा को बढ़ाया जिससे उसे प्रति माह रू0 15000.00 तक की आमदनी हो जाती है जिससे वह अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह से कर रही है।

ती प्रेमा अपनी दुकान में डिजिटल लेन–देन के माध्यम से चलाती हैं जिससे उन्हें लेनदेन करने में ानी होती जिसको लेकर वो काफी उत्साहित है और अपना व्यवसाय अच्छी तरह चला रही है तथा र्थिक रूप से मजबूत हुई है।

पी0एम0 स्वनिधि योजना से व्यवसाय को उड़ान.........

नगर निगम रुद्रपुर में फेरी व्यवसायी श्री राजाराम द्वारा फास्ट फूड की ठेली लगायी जाती है। पी0एम0 स्वनिधि योजना से इनके द्वारा प्रथम चरण में रू0 10 हजार तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्रमशः 20 हजार एवं 50 हजार का ऋण लिया गया है ।

योजना से ऋण लेकर इनके द्वारा अपनी आजीविका में वृद्धि करते हुए अपने परिवार का भरण–पोषण सफलतापूर्वक किया जा रहा है साथ ही अपनी आय में वृद्धि की जा रही है। इनके द्वारा लेन–देन हेतु डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुये ग्राहकों से अधिकतम लेन–देन क्यू0 आर0 कोड के द्वारा किया जाता है जिससे कैश बैक लाभ के माध्यम से भी इनकी आय में बढ़ोत्तरी हुयी है।

55

DEHRADUN
SMART CITY LTD.

देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना

देहरादून स्मार्ट सिटी

देहरादून शहर का चयन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वर्ष 2018 में तीसरे चरण के चयन में किया गया था। शहर और पैन सिटी के क्षेत्र आधारित विकास को विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शासनादेश के तहत विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की गई थी।

कोर सिटी क्षेत्र को क्षेत्र आधारित विकास कार्यों के लिए केंद्रित क्षेत्र के रूप में चुना गया था जिसमें शहर के लिए सभी टिकाऊ और आवश्यक घटकों को शामिल किया गया है। इन कार्यों में शामिल हैं – सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं और आईटी अवसंरचना की रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास।

पूरे शहर की परियोजनाएं आईटी सक्षम बुनियादी ढांचे से लैस करने पर केंद्रित हैं – जैसे शहर निगरानी प्रणाली, यातायात प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन और राज्य डेटा केंद्र का उन्नयन। साथ ही एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर में एकल आईटी प्लेटफॉर्म और निगरानी प्रणाली के लिए विभिन्न सुविधाओं का एकीकरण। विभिन्न परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और नागरिकों की सेवा में हैं जैसे इलेक्ट्रिक बस, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शौचालय, क्रेच बिल्डिंग, वाटर एटीएम, सरकारी कार्यालयों का डिजिटाइजेशन और डीआईसीसीसी – विभिन्न तरीकों से देहरादून के नागरिकों की सुविधा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

जो परियोजनाएं रुकी हुई थीं/धीमी गति से चल रही थीं, उन्हें अब पिछली कार्यान्वयन एजेंसियों से वापस ले लिया गया है और अब उन्हें राज्य एजेंसियों पीडब्ल्यूडी, यूकेपीजेएन, सिंचाई विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए आबंटित कुल धनराशि, ₹ 1000 करोड़ है। (50 प्रतिशत भारत सरकार, 50 प्रतिशत उत्तराखंड सरकार)। अब तक प्राप्त कुल धनराशि ₹ 688.00 करोड़ है, (₹ 325.50 करोड़ भारत सरकार ₹ 322.50 करोड़ उत्तराखंड सरकार)। अब तक देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया कुल व्यय ₹ 591.22 करोड़ है।

देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड स्वीकृत समय सीमा में परियोजनाओं के निष्पादन को तेजी से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।

परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

पूर्ण परियोजना

क्र०सं०	स्वीकृत योजना/कार्य का नाम	योजना प्रारम्भ होने की तिथि	वर्तमान स्थिति	लागत (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	स्मार्ट टॉयलेट्स	08-03-2019	कार्य पूर्ण	1.81	1.18	100
2	सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम	01-03-2019	कार्य पूर्ण	1.00	0.62	100
3	डिजिटाइजेशन ऑफ कलक्ट्रेट एंव सी डी ओ ऑफिस	15-07-2020	कार्य पूर्ण	0.56	0.56	100

क्र0सं0	स्वीकृत योजना / कार्य का नाम	योजना प्रारम्भ होने की तिथि	वर्तमान स्थिति	लागत (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
4	स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट	30-05-2019	कार्य पूर्ण	5.92	5.91	100
5	दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर	16-08-2019	कार्य पूर्ण	307.83	254.39	100
6	राष्ट्रीय ध्वज स्मारक	19-09-2020	कार्य पूर्ण	0.10	0.09	100
7	क्रेच बिल्डिंग	18-04-2020	कार्य पूर्ण	1.03	1.03	100
8	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	15-11-2019	कार्य पूर्ण	5.75	5.75	100
9	इलेक्ट्रिक बस	04-03-2020	कार्य पूर्ण	41.56	26.20	100
10	वाटर एटीएम पी पी पी मोड	20-02-2019	कार्य पूर्ण	1.98	0	100

80–90 प्रतिशत प्रगति वाली परियोजनाएं

क्र0सं0	स्वीकृत योजना / कार्य का नाम	योजना प्रारम्भ होने की तिथि	योजना पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	लागत (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
11	स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट	18-09-2020	31-03-2023	25.07	20.89	100
12	वाटर सप्लाई ऑग्मेंटेशन एंड वाटर मीटरिंग	16-12-2019	30-08-2023	36.4	25.90	100
13	पल्टन बाजार पेडेस्ट्रियनाइजेशन	07-11-2019	10-12-2022	13.81	7.07	100
14	परेड ग्राउंड रैजुवेनेशन	26-09-2019	07-02-23	21.19	14.58	100

शेष परियोजनाएं प्रगति पर हैं						
क्र0सं0	स्वीकृत योजना / कार्य का नाम	योजना प्रारम्भ होने की तिथि	योजना पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	लागत (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
15	स्मार्ट अपशिष्ट वाहन (नगर निगम एवं जल संस्थान के लिए)	--	--	21.28	15.36	100
16	फसाड वर्क्स – पल्टन बाजार	15-11-2022	13-07-2023	4.79	4.64	100
17	स्मार्ट पोल ऑन पी पी पी मोड	14-01-2020	31-03-2023	0.00	0.00	27
18	कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट रोड	15-09-2019	30-03-2024	190.54	148.86	85
19	स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज अलोंग स्मार्ट रोड	01-10-2019	31-03-2023			
20	मल्टी यूटिलिटी डक्ट अलोंग स्मार्ट रोड	01-10-2019	31-03-2023			
21	सीवरेज लाइन अलोंग स्मार्ट रोड	01-10-2019	31-03-2023			
22	वाटर सप्लाई अलोंग स्मार्ट रोड	01-10-2019	31-03-2023			
23	इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम	01-01-2020	31-03-2024	17.45	10.18	78
24	इंटीग्रेटेड सीवरेज स्कीम	01-01-2020	31-03-2024	28.41	20.09	55
25	सिटी इंवेस्टमेंट्स टू इन्नोवेट, इंटीग्रेट, एंड सस्टेन (सिटीज़)	13-05-2022	30-11-2023	11.27	1.16	70
26	इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग	28-08-2019	30-06-2024	204.46	18.45	1.25

पूर्ण परियोजनाओं का परिणाम

1 स्मार्ट स्कूल

स्मार्ट स्कूल (गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजपुर रोड, देहरादून, गवर्नमेंट बॉयज इंटर कॉलेज, खुर्बुरा, देहरादून एवं गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, खुर्बुरा, देहरादून) में छात्रों को इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है और छात्र एवं प्रशिक्षक की क्षमता व उत्पादकता को बढ़ाते हैं।

2 दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, के अंतर्गत आपदा प्रबंधन स्थितियों सहित शहर के यातायात को सुगम बनाना तथा बिजली, पानी सीवरेज एवं अन्य मूलभूत समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।

विशेषताएं –

- इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर; वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन।
- इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली वाहन पारगमन प्रबंधन प्रणाली।
- सिटीजन–सेंट्रिक सर्विस–पीए सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स, इमरजेंसी हेल्पडेस्क, एएल के साथ सिटी सर्विलांस, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सिटी वाई–फाई, पर्यावरण सेंसर आदि।

3 सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम

स्मार्ट शहरों में विकास को या तो मौजूदा बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के कामकाज में सुधार के लिए या नए बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें आज की दुनिया में संभव डिजाइन पहलुओं में प्रौद्योगिकी और दक्षता शामिल है।

देहरादून में नागरिक जुड़ाव को आभासी बातचीत, संवाद और चर्चा के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना है और इसलिए यह शहरी विकास का केंद्र है। यह सड़कों, पार्कों की सफाई पर रिपोर्ट करके किया जा सकता है।

4 राष्ट्रीय ध्वज स्मारक

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में, सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को अपनी पूरी शान में बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान और वफादारी है। फिर भी, जागरूकता की कमी न केवल लोगों में बल्कि सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी अक्सर देखी जाती है।

5 स्मार्ट टॉयलेट्स

स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में एबीडी क्षेत्र में 7 स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया गया है । स्मार्ट शौचालय परियोजना का उद्देश्य आम जनता को स्वचालित सुविधाओं वाले स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है।

एस0जी0आर0आर0 तालाब में भित्ति चित्रांण पेंटिंग का कार्य

6 डिजिटाइजेशन आफ कलक्ट्रेट एंड सी डी ओ आफिस

डिजिटाइजेशन ऑफ कलक्ट्रेट एंड सी डी ओ ऑफिस परियोजना के तहत सरकारी कार्यालय में कागज के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट और सीडीओ कार्यालय में पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया।

7 क्रेच बिल्डिंग

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए एक मॉडल क्रेच सुविधा प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्तावित दून चिल्ड्रेन्स डे–केयर सेंटर (क्रेच), एबीडी क्षेत्र में स्थित है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। क्रेच का भौतिक वातावरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त रखा जाता है। लेआउट में प्रदान की गई जगहों में गतिविधि क्षेत्र शामिल है।

8 इलेक्ट्रिक बसें, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें

इलेक्ट्रिक बस, परियोजना का उद्देश्य शहर में हरित वातावरण को बनाए रखना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन से कार्बन उत्सर्जन को एक निश्चित स्तर तक कम किया जा सकेगा। देहरादून शहर में संचालित 30 इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से अब तक लगभग 12.5 लाख यात्री सुगम यात्रा का लाभ ले चुके है ।

9 मॉडर्न दून लाइब्रेरी

मार्डन दून लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स एक जी 3 संरचना होगी जो छात्रों और नागरिकों को सभी शैक्षिक और साहित्यिक संसाधनों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाती है। लाइब्रेरी में निम्नलिखित स्मार्ट विशेषताएं भी होंगी–

- ई–पढ़ने की सुविधा
- आरएफआईडी टैगिंग
- स्मार्ट कार्ड
- स्व–चेक इन चेक आउट

10 वाटर एटीएम पी पी पी मोड

देहरादून शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के एक हिस्से के रूप में, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने देहरादून में 24 स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किये है। इसके द्वारा आम जनता को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाता है।

1 पल्टन बाजार पेडेस्ट्रियनाइज़ेशन

पलटन बाजार पेडेस्ट्रियनाइज़ेशन उद्देश्य पैदल मार्गों में सुधार करना और गैर–मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नियमित अंतराल पर बेहतर रोशनी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी।

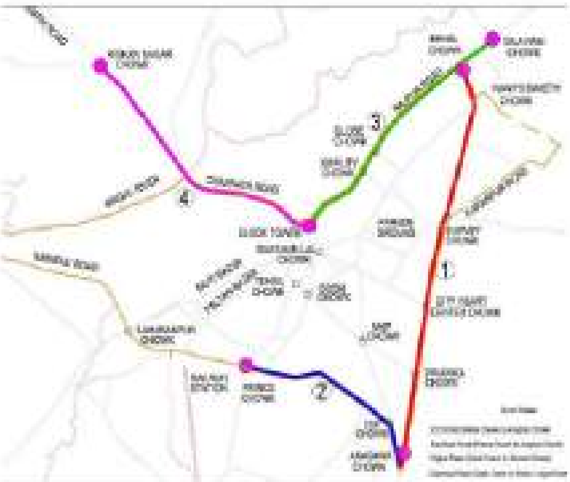

2 स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट

स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत सड़क के नीचे सर्विस डक्ट बनाई जाएगी। यह एक तरह की सुरंग होगी, जिसमें बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन, इंटरनेट की लाइनें होंगी। इससे किसी भी लाइन के खराब होने, नई लाइन बिछाने के लिए बार–बार सड़क को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली के तार झूलते नहीं दिखेंगे। शहर में सभी बिजली और टेलीफोन की लाइनें अंडर ग्राउंड होगी। सभी तरह के केबल सर्विस डक्ट के जरिये इधर से उधर होंगे। इससे खराबी आने की संभावना कम होगी और शहर भी सुंदर दिखेगा।

3 इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग

- एक छत के नीचे सभी सरकारी कार्यालय नागरिकों को आसानी से पहुंच प्रदान करते हैं। नया भवन प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग होगा जिसे निम्न को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्राकृतिक घटनाओं जैसे तापमान और/या भूकंप के कारण भार का प्रतिरोध।
- संरचनात्मक स्थायित्व और रख–रखाव।
- आर्थिक संरचना।
- ऊर्जा कुशल डिजाइन
- स्मार्ट आईटी हस्तक्षेप

4 परेड ग्राउंड रेजुवेनेशन

- एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र
- गांधी पार्क परेड ग्राउंड के बीच पैदल यात्री सुभाष रोड
- विक्रेताओं के लिए मोबाइल कियोस्क क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं।
- वॉक–वे, साइकिल ट्रैक, मेलों, परेड आदि के आयोजन की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

5 फसाड वर्क्स – पल्टन बाजार

पलटन बाजार देहरादून शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र है, और अधिकांश दुकानें काफी पुरानी हैं और बेतरतीब तरीके से बनाई गई हैं। साथ ही वे अलग–अलग साइनेज और अलग–अलग डिज़ाइन, रंग, पैटर्न और भाषा में उपयोग कर रहे हैं, जो एक सममित रूप देता है। पलटन बाजार एबीडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुखौटा कायाकल्प के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्से के रूप में विचार किया गया है।

6 स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट

शहर में मौजूदा 206 नलकूपों से जल उत्पादन की मात्रात्मक और गुणात्मक निगरानी के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण और 72 ओवरहेड टैंकों से जल वितरण प्रस्तावित किया गया है। यह जनता को आपूर्ति किए जा रहे पानी की उचित मात्रा और गुणवत्ता का स्वचालित नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। अधिग्रहीत डेटा जल संस्थान को जल आपूर्ति में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगा।

7 वाटर सप्लाई ऑग्मेंटेशन एंड वाटर मीटरिंग

एबीडी क्षेत्र में जल आपूर्ति वृद्धि पूरे एबीडी क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार के लिए प्रस्तावित है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) के तहत आरएफ टेक्नोलॉजी के साथ एएमआई (ऑटोमेटेड इंफ्रा स्ट्रक्चर) सिस्टम के साथ स्मार्ट मीटर को लागू करने के लिए स्मार्ट एनर्जी मीटर और हेड एंड सिस्टम के बीच दो–तरफा संचार को सक्षम करना है ताकि रिमोट रीडिंग, मॉनिटरिंग को सक्षम किया जा सके।

8 इंटीग्रेटेड सीवरेज स्कीम

स्मार्ट सिटी का चयनित क्षेत्र देहरादून का सबसे पुराना और अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र है। यह इलाका – ज्यादातर सीवरेज वाला है, लेकिन एबीडी एरिया में बिछाई गई सीवर लाइनें 40–50 साल पुरानी हैं और उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। अधिकांश सीवर लाइन और मैनहोल जर्जर स्थिति में हैं, जैसा कि जल संस्थान ने पुष्टि की है। ये सीवर अक्सर चोक हो जाते हैं और इनका सीवेज आसपास की खुली नालियों और कई जगहों पर नालों में बहा दिया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य एबीडी क्षेत्र में सीवर प्रणाली में सुधार करना है।

9 स्मार्ट अपशिष्ट वाहन (नगर निगम एवं जल संस्थान के लिए)

इस परियोजना का उद्देश्य नगर निगम और जल संस्थान को मानव इंटरफेस को कम करने और इस प्रकार मानव जीवन जोखिम को कम करने के लिए सफाई मशीनरी प्रदान करना है।

10 इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम

इस परियोजना का उद्देश्य एबीडी क्षेत्र में वर्षा जल निकासी प्रणाली में सुधार करना है क्योंकि वर्तमान प्रणाली विभिन्न हिस्सों में जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है।

11 सिटी इंवेस्टमेंट्स टू इन्नोवेट, इंटीग्रेट, एंड सस्टेन

चाइल्ड फ्रेंडली दून पहल का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल स्मार्ट शहरों के विकास के लिए एक अनूठी प्रयोग प्रयोगशाला बनना है ताकि ज्ञान आधारित, उन्नत और प्रभावी बाल अनुकूल गतिशीलता ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके जिसमें बच्चों के दृष्टिकोण शामिल होंगे और शहरों की योजना और प्रबंधन में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार यह पहल हिमायत और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से एक मजबूत ज्ञान आधार बनाने और शहर प्रशासन को तकनीकी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

12 स्मार्ट पोल ऑन पी पी पी मोड

68

UTTARAKHAND URBAN SECTOR DEVELOPMENT AGENCY (UUSDA)

Urban Development Department Govt. of Uttarakhand

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA)

69

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA)

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) का गठन वर्ष 2008 में शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया। संस्था के अन्तर्गत विभिन्न वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय अवस्थापना विकास कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

1. गतिमान परियोजना – उत्तराखण्ड एकीकृत एवं रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना(UIRUDP) दिसम्बर, 2021 में मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शिलान्यासित न्ल्न्क परियोजना का युद्धस्तर पर कार्य प्रगति पर है। देहरादून के बंजारावाला व मोथरोवाला में गतिमान पेयजल कार्यों के अन्तर्गत कुल 132 कि0मी0 लक्ष्य के सापेक्षतः 110 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जा चुका है। इसके साथ ही बंजारावाला, मोथरोवाला, यमुना कालोनी, देहराखास, रिंगरोड, नत्थनपुर, मोहकमपुर, मियांवाला, हर्रावाला क्षेत्रों में लक्षित कुल 262 कि0मी0 में से 212 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क बिछाये जाने का कार्य कर लिया गया है। उक्त क्षेत्रों में घरेलू पेयजल तथा सीवरेज संयोजन का कार्य भी सामानान्तर गतिमान है। इसके अतिरिक्त दौड़वाला में 11 एम0एल0डी0 तथा नकरौंदा में 18 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। सभी क्षेत्रों की कुल 182 कि0मी0 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। नैनीताल में कुल 11.9 कि0मी0 लक्ष्य के सापेक्षत : 7.9 कि0मी0 सीवरेज लाईन बिछायी जा चुकी है तथा 17.5 डस्य क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र का कार्य भी प्रगति पर है। सभी खोदी गई सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। परियोजना निर्माण कार्यों की पूर्णता अवधि जून 2025 तक है।

2. यू0यू0एस0डी0ए0 परियोजना हेतु ए0डी0बी0 द्वारा रू0 2686 करोड़ के ऋण स्वीकृत

एडीबी एवं यू0यू0एस0डी0ए0 के मध्य उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड एवं रेजिलिएन्ट शहरी विकास परियोजना (यू0आई0आर0यू0डी0पी0) – अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु कुल रू0 2686 करोड़ के स्वीकृत ऋण हस्ताक्षरित किये गये हैं। परियोजना के अन्तर्गत देहरादून के नवादा व रायपुर में सीवरेज और हल्द्वानी व टनकपुर में पेयजल व सीवरेज के कार्य किये जाने हैं।

- परियोजना के माध्यम से रायपुर के नेहरूग्राम, बालावाला, तुनवाला, नथुवावाला, मियांवाला, नकरौंदा समीपवर्ती क्षेत्रों में 148 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 15867 घरेलू सीवरेज संयोजन किये जायेंगे। 3.25 एम0एल0डी0 क्षमता का इंटरमीडिएट सीवेज पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किया जायेगा।
- देहरादून के नवादा समीपवर्ती क्षेत्रों में 52 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 7655 घरेलू सीवरेज संयोजन किये जायेंगे।
- हल्द्वानी में कुल 770 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क के साथ–साथ 125 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 39600 घरेलू पेयजल एवं 18200 सीवरेज संयोजन किये जायेंगे। 10.5 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जायेगा।
- टनकपुर में कुल 61 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 6388 घरेलू सीवरेज संयोजन किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA)

3. ऋषिकेश नगर एकीकृत अवस्थापना विकास परियोजना (RIUDP)

दो चरणों में सम्पादित की जाने वाली इस परियोजना हेतु जर्मन विकास बैंक द्वारा रू0 1900 करोड़ की अनुमानित धनाराशि वर्ष 2022–2023 में स्वीकृत किये जा चुके हैं। परियोजना की रूपरेखा पर सम्बन्धित हितधारकों एवं लाईन एजेंसियों से विस्तार से विचार–विमर्श किया गया है। जिसके क्रम में परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023–2024 के अन्तराल में परियोजना को धरातल पर प्रारम्भ किया जाना संभावित है। परियोजना के अन्तर्गत ऋषिकेश, तपोवन, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों एवं स्थानीयों हेतु सुविधाजनक यातायात गतिशीलता विकास इत्यादि कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

4. एशियन विकास बैंक (ADB) वित्तपोषित उत्तराखण्ड लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ULIP)

एशियन विकास बैंक (ADB) वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित लगभग रू0 2447 करोड़ के माध्यम से हल्द्वानी (City Mobility Plan, Drainage, Buiding and Other Development) कोटद्वार, चम्पावत, किच्छा, विकासनगर आदि नगरों में पेयजल तथा विकासनगर में पेयजल एवं सीवरेज के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

- परियोजना के माध्यम से हल्द्वानी में नगरीय गतिशीलता तथा नमो भवन (सभी राजकीय कार्यालयों हेतु एक प्रशासनीक भवन) का निर्माण कार्य के साथ अन्य कार्य किये जायेंगे।
- चम्पावत नगर हेतु 160 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 4523 घरेलू पेयजल संयोजन किये जायेंगे। कुल 2900 कि0ली0 पेयजल क्षमता हेतु 04 जलाशयों का निर्माण किया जायेगा। 3.5 एम0एल0डी0 क्षमत का पेयजल शोधन संयंत्र स्थापित किया जायेगा।
- कोटद्वार नगर हेतु 330 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 22196 घरेलू पेयजल संयोजन किये जायेंगे। कुल 4000 कि0ली0 पेयजल क्षमता हेतु 04 जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
- किच्छा नगर हेतु 402 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 20000 घरेलू पेयजल संयोजन किये जायेंगे। कुल 6800 कि0ली0 पेयजल क्षमता हेतु 04 जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
- विकासनगर नगर हेतु 131 कि0मी0 पेयजल नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 9400 घरेलू पेयजल संयोजन किये जायेंगे। कुल 3650 कि0ली0 पेयजल क्षमता हेतु 04 जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
- विकासनगर नगर हेतु 58 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क बिछाया जायेगा तथा 10098 सीवरेज संयोजन किये जायेंगे। 7.5 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जायेगा।

5. यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) वित्तपोषित उत्तराखण्ड लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ULIB)

यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित लगभग रू0 2766 करोड़ के माध्यम से पिथौरागढ़, सितारगंज, रूद्रपुर एवं काशीपुर में पेयजल के कार्य तथा पिथौरागढ़ व डोईवाला में पेयजल तथा सीवरेज के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। जिनकी डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी हैं व वित्तपोषण संस्था से स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी(UUSDA)

श्री चन्द्रेश कुमार, कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 के मार्गदर्शन में सभी परियोजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन हेतु तैयारी पूर्ण तत्परता के साथ की जा रही है। लक्षित परियोजना को पूर्णता अवधि से सम्पादित करना तथा पेयजल तथा सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पंहुचाना ही यू0यू0एस0डी0ए0 का उद्देश्य है।

<u>परियोजना के उद्देश्य व लाभ</u>

आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई इन परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत आमजन के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने व आर्थिक विकास हेतु, असमानता कम करने, लैंगिक समानता को लागू करने, सतत् शहरीकरण और समुदायों को संगठित करने, जलवायु कार्यों, जल जैविकी को विकसित करने, नगरीय जीवन योग्यता मानकों को पूर्ण करने, गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा और एक सुव्यवस्थित नगरीय विकास मानकों को पूर्ण करने में यह योजनायें सहयोगी साबित होंगी।

मोथरोवाला में एस0टी0पी0 का कार्य प्रगति पर

देहराखास में वर्षाजल निकासी का कार्य प्रगति पर

सीवर नेटवर्क बिछाने के बाद सड़क सुधार का कार्य

गहरी एवं बड़े व्यास की सीवर लाईनों का कार्य

Uttarakhand

विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी

विकसित भारत संकल्प यात्रा – शहरी विकास विभाग

परिचय :–

15 नवंबर, 2023 को जनजाति गौरव दिवस से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। इस यात्रा का उदेश्य केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाना और उनका लाभ देना है। इस ड्राइव के तहत उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गौरा देवी कन्यादान योजना और लखपति दीदी योजना सहित केंद्र और राज्य की कुल 17 योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान मौके पर लाभार्थियों को लाभ और योजनाओं का फीडबैक लिया जा जायेगा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिये विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।

यात्रा का उद्देश्य–

- आम जन मानस तक सरकारी योजनाओं की पहुँच प्रदान करना, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं, जिन्हे इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
- योजनाओं के बारे में आम जनमानस में जागरूकता बढ़ाना।
- लाभांवित परिवारों के अनुभवों को उन्ही की जुबानी साझा कराना।
- लाभार्थियों के जीवन में किस तरह से सुधार का प्रत्यक्ष जुड़ाव।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं में संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना।

विकसित भारत संकल्प यात्रा – शहरी विकास विभाग

उत्तराखण्ड राज्य में यात्रा:-

उत्तराखंड के मा0 राज्यपाल, श्री गुरमीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। शहरी क्षेत्र में श्री प्रेमचंद अग्रवाल, मा0 मंत्री जी, शहरी विकास उत्तराखण्ड ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गयी, जिसके उपरान्त प्रदेश में शहरी क्षेत्र उत्तराखण्ड में गढ़वाल मंडल की 167 लोकेशन और कुमाऊं मंडल की 115 लोकेशन पर दस गाड़ियों के जरिए इस ड्राइव को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थित शहरी निकायों में कुल 282 स्थानों में यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में कुल 2,30,382 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें 96,760 पुरुष एवं 1,33,622 महिलायें सम्मिलित थीं। यात्रा में आधार, शहरी निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री उज्वला योजना में आयुष्मान तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि शिविर लगाकर लोगों को लाभ दिया गया।

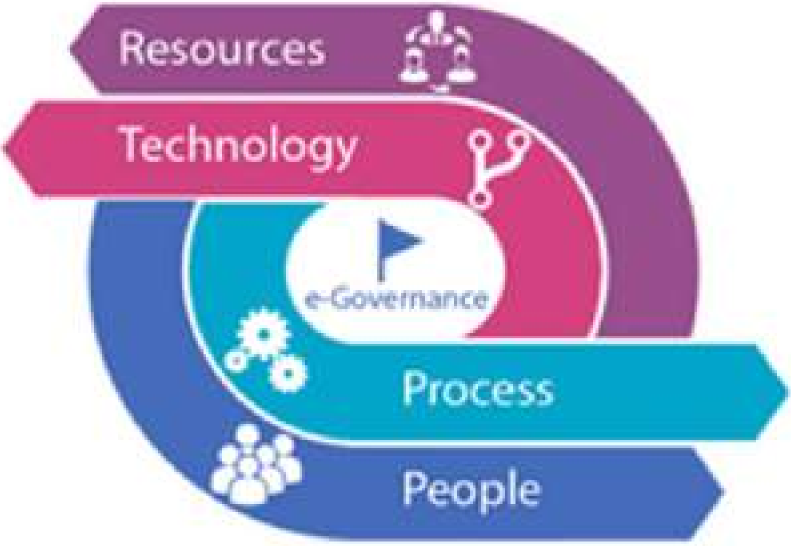

ई–गवर्नेंस

ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित सेवाएं–

शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं यथा ट्रेड लाईसेंस, रोड कटिंग, सम्पत्ति कर तथा म्यूटेशन व विभिन्न मदों में संग्रह की जाने वाली धनराशि हेतु नगर सेवा पोर्टल पर राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन0आई0यू0ए0) द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) के माध्यम से शहरी गर्वनेंस को डिजिटिलाईज करते हुए सुदृढ़ किया जा रहा है।

ट्रेड लाईसेंस

- वर्तमान में शहरी विकास निदेशालय द्वारा ट्रेड लाईसेंस, एम0सी0एस0 एवं सम्पत्ति कर पेमेंट को ऑनलाईन किया जा चुका है।
- उपरोक्त से न केवल आम जन को सुविधाएं उनके द्वार पर प्राप्त होगी अपितु नगर निकायों की आय में भी वृद्धि होनी आपेक्षित है।
- ट्रेड लाईसेंस में आतिथि तक कुल पोर्टल द्वारा 53133 ट्रेड लाईसेंस निर्गत कर रू0 5.36 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में नगर निकयों द्वारा पोर्टल के माध्यम से 12771 ट्रेड लाईसेंस निर्गत कर रू0 1.71 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

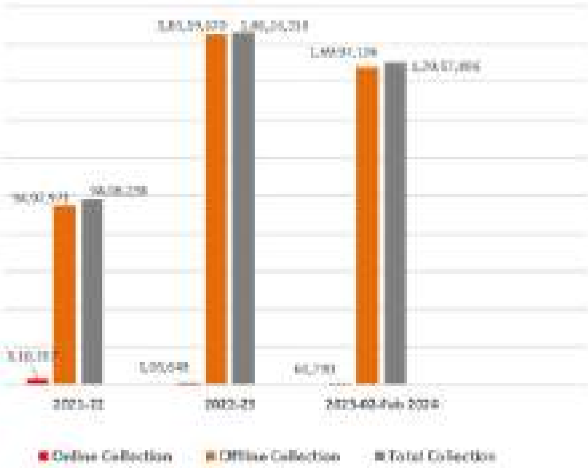

नगर सेवा पोर्टल

- नगर सेवा पोर्टल द्वारा एम0सी0एम0 में आतिथि तक कुल रू0 18.25 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नगर निकायों द्वारा पोर्टल के माध्यम से रू0 3.79 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

सम्पत्ति कर

आतिथि तक नगर सेवा पोटल में 69 निकायों की 4,40,308 सम्पत्ति डिजिटालाईज कर ऑनलाईन की जा चुकी है एवं कुल रू0 65.40 करोड़ का राजस्व निकायों द्वारा पोटल के माध्यम से प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नगर निकायों द्वारा पोर्टल के माध्यम से रू0 8.37 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

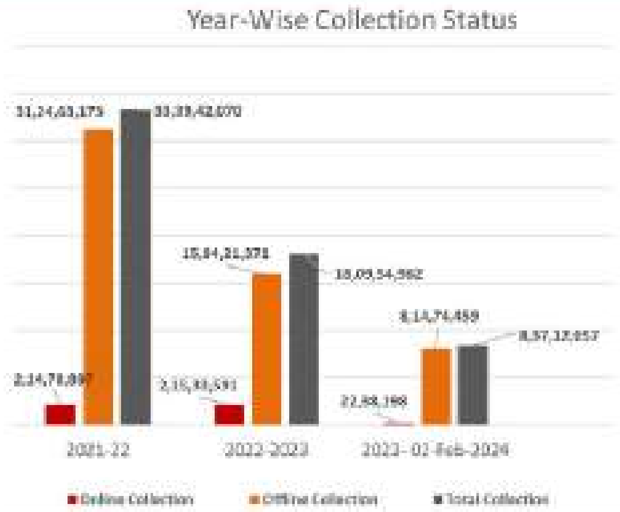

उक्त के अतिरिक्त विश्व बैंक के सहयोग से 4 नगर निकायों में सम्पत्तियों की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्रगति पर है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में नगर निकायों हेतु ऑनलाईन अर्बन ऑजरवेट्री का निर्माण, 10 निकायों में सम्पत्ति की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य एवं ऑनलाईन म्युनिसिपल एक्यूरल एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है।

फोटो गैलेरी

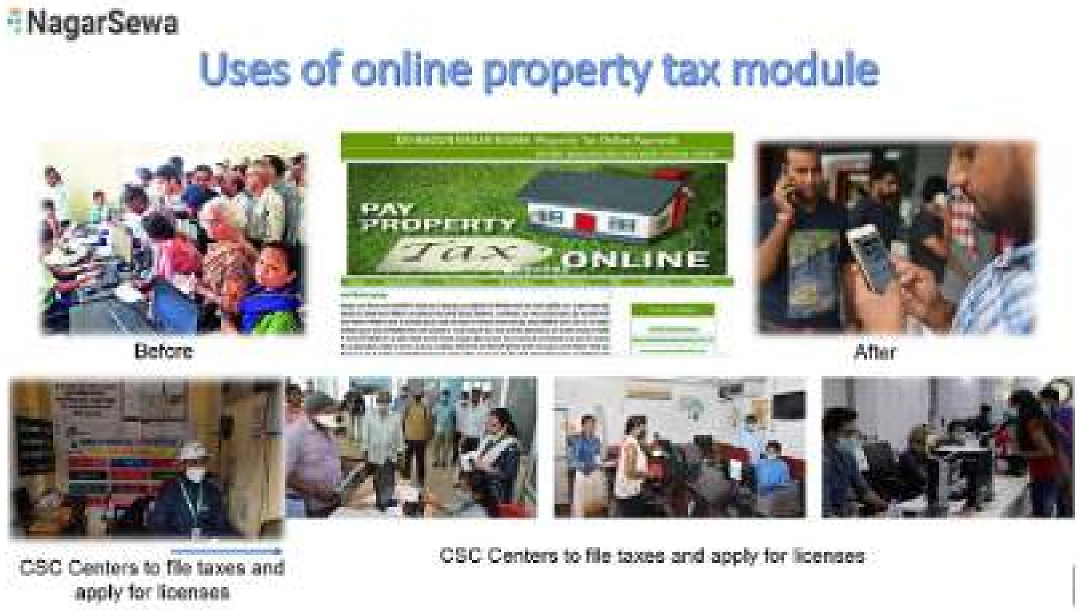
NagarSewa
Uses of online property tax module
PAY PROPERTY Tax ONLINE
Before
After
CSC Centers to file taxes and apply for licenses
CSC Centers to file taxes and apply for licenses

"डिजिटल अर्बन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म" विषय पर
02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

शहरी विकास विभाग की उपलब्धियां

- भारत सरकार की "स्पेशल असिस्टेन्ट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट" योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का चयन किया गया है। योजना में लगभग रु0 100 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्बन रिफॉर्म हेतु दिया जाना है। राज्य ने योजना के अन्तर्गत छः घटकों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार को प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त ही राज्य सरकार को अनुदान हेतु पात्रता प्राप्त हुई है।
- राज्य शहरी विकास संस्थान (एस0आई0यू0डी0) की स्थापना ए0टी0आई0 नैनीताल में की गई।
- उत्तराखण्ड को अर्बन लार्नाथोन 2023 के विजेता और उपविजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में नगर निगम देहरादून को उत्तराखण्ड में स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक लाख से कम जनसंख्या वाली निकायों में नगर निकाय मुनि की रेती को उत्तराखण्ड में स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की नगर पंचायतों में विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को विशेष भत्ता देने की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है। (केदारनाथ रु० 250/– प्रतिदिन अतिरिक्त, बद्रीनाथ व गंगोत्री रु० 200/– प्रतिदिन अतिरिक्त) साथ ही इन निकायों में रु० 2500/कार्मिक वर्दी भत्ता का शासनादेश जारी किया जा चुका है।
- अटल निर्मल पुरुस्कार की धनराशि रु0 1.00 करोड़ से बढ़ाकर रु0 2.00 करोड़ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है जिसके कम में बजट प्राविधान किया जा चुका है।
- राज्य ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में स्पार्क रैंकिंग में तृतीय स्थान तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पी0एम0स्वनिधि योजनान्तर्गत दिये जाने वाले ऋण में अतिरिक्त सम्पूर्ण ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की गयी जिससे फेरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो सके।
- जल–दिवाली कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को अमृत योजनान्तर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भ्रमण कराकर, शहरी आजीविका मिशन एवं अमृत योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभिसरण किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 25000 (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक) आवासों का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष 10000 आवास निर्मित किये जा चुके हैं, शेष आवासों का कार्य प्रगति पर है।
- भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 8500 आवासों का आवंटन किया जा चुका है।

शहरी विकास विभाग की उपलब्धियां

- प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को नये आवासों में प्रवेश करने पर रु0 5000.00 प्रोत्साहन की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है, जिसके कम में प्रथम चरण हेतु 11000 लाभार्थियों के लिए शासन द्वारा रू0 5.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- 14 नगर निकायों की जी0आई0एस0 मैपिंग की जा रही है जिससे निकायों की सम्पत्तियों का वास्तविक माप एवं सम्पत्ति कर का आंकलन किया जा सके जिससे निकायों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही नागरिकों को गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी।
- पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 149 कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिर तथा 81 कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर विभिन्न नगर निकायों में नियुक्तियां प्रदान की गयी।
- पालिका केन्द्रीयित सेवाओं के रिक्त 227 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।
- पंचम वित्त आयोग ने शहरी विकास विभाग हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु रू0 180.00 करोड़ की धनराशि प्रावधानित की है।
- राज्य शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान हेतु पंचम वित आयोग ने रू0 05.00 करोड़ की धनराशि प्रावधानित की है।
- राज्य की नगर निकायों में पार्कों के निर्माण हेतु रू0 81.63 लाख तथा नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रू0 826.00 लाख विभिन्न नगर निकायों को अवमुक्त किये गये।
- जी–20 के सफल आयोजन में सहयोग किया गया।

सेवा पखवाड़े में स्ट्रीट वेंडरों के बच्चों को सम्मानित करते हुए

वित्तीय विवरण
(IN CRORES)
35
30
25
20
15
10
5
0
2008-09
2009-10
2010-11
2011-2012
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-2021
82

वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय के सापेक्ष 22 फरवरी 2024 तक अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)										
क्र0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये कुल प्राविधानित धनराशि (लाख में)			वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त धनराशि (लाख में)			वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये कुल अद्यतन व्यय धनराशि (लाख में)		
		राजस्व	पूंजीगत	कुल योग	राजस्व	पूंजीगत	कुल योग	राजस्व	पूंजीगत	कुल योग
राज्य सेक्टर										
1	श0वि0नि0 अधिष्ठान व्यय	609	0.00	609	609	0.0	609	359.28	0.00	359.28
2	नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
3	स्थानीय निकाय प्रोत्साहन निधी	200	0.0	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
4	सड़क पर रेडीफेरी	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
5	सफाई कर्मचारी पारितोषिक योजना	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.00	0.0
6	सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य आरोहण योजना	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.00	0.0
7	नगर पालिकाओं में पार्क नि0	500.0	0.0	500.0	164.93	0.0	164.93	81.63	0.00	81.63
8	सफाई कर्मचारी बीमा योजना	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
9	श्वान पशु बन्ध्याकरण यो0	200.0	100.0	300.0	19.47	33.48	52.95	5.06	0.00	5.06
10	निदेशालय भवन निर्माण	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
11	हाईटेक शौचालय निर्माण	0.0	200.0	200.0	0.0	74.99	74.99	0.0	39.08	39.08
12	रैन बसेरों का निर्माण	50.0	100.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
13	अवस्थापना विकास निधी	1150.00	5000.0	6150.00	0.0	3232.48	3232.48	0.0	798.78	798.78
14	कावड़ मेला	641.51	0.0	641.51	60.0	0.0	60.0	60.0	0.00	60.0
15	**अवारा पशुओं हेतु आश्रम निर्माण/संचालन**	**500.0**	**500.0**	**1000.0**	**0.0**	**223.71**	**223.71**	**0**	**223.71**	**223.71**
16	**भूमि अधिग्रहण/भूमि क्रय**	**6360.0**	**0.0**	**6360.0**	**6195.69**	**0.0**	**6195.69**	**6195.69**	**0.00**	**6195.69**
योग		**10294.41**	**6400.0**	**16694.41**	**7119.09**	**3564.66**	**10683.75**	**6701.66**	**1061.57**	**7763.23**

क्र0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये कुल प्राविधानित धनराशि (लाख में)			वित्तीय वर्ष 2023–24 मे अवमुक्त धनराशि (लाख में)			वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये कुल अद्यतन व्यय धनराशि (लाख में)		
		राजस्व	पूंजीगत	कुल योग	राजस्व	पूंजीगत	कुल योग	राजस्व	पूंजीगत	कुल योग
केन्द्र पोषित योजनायें										
17	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	500.0	0.02	500.02	178.14	0.0	178.14	178.14	0.00	178.14
18	प्रधानमन्त्री आवास योजना	20769.80	0.0	20769.80	10637.86	0.0	10637.86	10637.86	0.00	10637.86
19	स्मार्ट सिटी	1000.0	19600.0	20600.0	1000.0	19600.0	20600.0	1000.0	19600.00	20600.00
20	स्मार्ट सीटी CITIIS Project	100.0	3249.0	3349.0	0.00	3248.0	3248.0	0.0	3248.00	3248.00
21	स्वच्छ भारत मिशन फेज–1	0.0	1500.0	1500.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
22	अटल नवीकरण मिशन फेज–1	1690.09	0.0	1690.09	80.00	0.0	80.00	0.0	0.00	0.0
23	स्वच्छ भारत मिशन फेज–2	1689.0	9090.0	10779.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
24	अटल नवीकरण मिशन फेज–2	1929.50	11100.0	13029.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
योग		27678.39	44539.02	72217.41	11896.00	22848.0	34744.00	11816.00	22848.00	34114.00
बाह्य सहायतित योजनायें										
25	नगर अवस्थापना सुदृढ़िकरण– 1(एडीबी)	2500.0	18300.0	20800.0	1175.0	18299.74	19474.74	1175.0	18299.74	19474.74
26	मध्यम श्रेणी के शहरों में अवस्थापना सुदृढ़िकरण–2(एडीबी)	1500.0	9000.0	10500.0	480.0	9000.00	9480.00	0.00	9000.00	9000.00
27	स्मार्ट सीटी (बाह्य सहायतित)	500.0	451.0	951.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
28	हल्द्वानी एकीकृत शहरी विकास अवस्थापना विकास निधि	2000.0	14900.0	16900.0	869.0	14900.00	15769.00	869.0	14900.00	15769.00
29	ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना	300.0	1100.0	1400.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
योग		6800.0	43751.0	50551.0	2524.0	42199.74	44723.74	2044.00	42199.74	44243.74
महायोग		44772.80	94690.02	139462.82	21539.09	68612.40	90151.49	20561.66	66109.31	86120.97

मुख्य अतिथि
पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखण्ड शासन
तीन
बिन
प्रतिदिन
गीला कूड़ा
सूखा कूड़ा
घरेलू हानिकारक कूड़ा
कूड़े को अलग-अलग कर के और सही कूड़ेदान का उपयोग से,
हम अपने घरों, शहर, और माँ गंगा को स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं !
उत्तराखण्ड सरकार
31/62 राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड 248001

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित स्थानीय निकायों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम
1	देहरादून	नगर निगम, देहरादून
2		नगर निगम, ऋषिकेश
3		नगर पालिका परिषद, मसूरी
4		नगर पालिका परिषद, विकासनगर
5		नगर पालिका परिषद, डोईवाला
6		नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर
7		नगर पंचायत, सेलाकुई
8	हरिद्वार	नगर निगम, हरिद्वार
9		नगर निगम, रूड़की
10		नगर पालिका परिषद, मंगलौर
11		नगर पालिका परिषद, लक्सर
12		नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर
13		नगर पंचायत, लण्ढौरा
14		नगर पंचायत, भगवानपुर
15		नगर पंचायत, झबरेड़ा
16		नगर पंचायत, पिरान कलियर
17		नगर पंचायत, ढंढेरा
18		नगर पंचायत, इंमलीखेड़ा
19		नगर पंचायत, पाण्डली गुर्जर
20		नगर पंचायत, रामपुर
21		नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर
22	टिहरी	नगर पालिका परिषद, टिहरी
23		नगर पालिका परिषद, मुनिकी रेती
24		नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर
25		नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग
26		नगर पालिका परिषद, चम्बा
27		नगर पंचायत, घनसाली
28		नगर पंचायत, कीर्तिनगर
29		नगर पंचायत, चमियाला
30		नगर पंचायत, गजा
31		नगर पंचायत, लम्बगांव
32		नगर पंचायत, तपोवन
33	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, पौड़ी
34		नगर निगम, कोटद्वार
35		नगर निगम, श्रीनगर
36		नगर पालिका परिषद, दुगड्डा
37		नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक

38		नगर पंचायत, सतपुली
39		नगर पंचायत, थलीसैण
40	चमोली	नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर
41		नगर पालिका परिषद, जोशीमठ
42		नगर पालिका परिषद, गौचर
43		नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग
44		नगर पंचायत, बद्रीनाथ
45		नगर पंचायत, नन्दप्रयाग
46		नगर पंचायत, गैरसैण्ड
47		नगर पंचायत, पोखरी
48		नगर पंचायत, पीपलकोटी
49		नगर पंचायत, थराली
50		नगर पंचायत, नन्दानगर
51	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
52		नगर पालिका परिषद, बड़कोट
53		नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़
54		नगर पंचायत, गंगोत्री
55		नगर पंचायत, पुरोला
56		नगर पंचायत, नौगांव
57	रूद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग
58		नगर पंचायत, केदारनाथ
59		नगर पंचायत, अगस्तमुनि
60		नगर पंचायत, उखीमठ
61		नगर पंचायत, तिलवाड़ा
62		नगर पंचायत, गुप्तकाशी
63	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
64		नगर पालिका परिषद, रानीखेत
65		नगर पंचायत, भिकियासैण्ड
66		नगर पालिका परिषद, द्वाराहाट
67		नगर पंचायत, चौखुटिया
68	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर
69		नगर पंचायत, कपकोट
70		नगर पंचायत, गरूड़
71	चम्पावत्	नगर पालिका परिषद, चम्पावत्
72		नगर पालिका परिषद, टनकपुर
73		नगर पालिका परिषद, लोहाघाट
74		नगर पंचायत, बनबसा
75	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
76		नगर पालिका परिषद, धारचूला

77		नगर पालिका परिषद, डीडीहाट
78		नगर पालिका परिषद, बेरीनाग
79		नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट
80		नगर पंचायत, मुनस्यारी
81	नैनीताल	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
82		नगर निगम, हल्द्वानी
83		नगर पालिका परिषद, रामनगर
84		नगर पालिका परिषद, भवाली
85		नगर पंचायत, कालाढूंगी
86		नगर पालिका परिषद, भीमताल
87		नगर पंचायत, लालकुंआ
88	उधमसिंहनगर	नगर निगम, रूद्रपुर
89		नगर निगम, काशीपुर
90		नगर पालिका परिषद, बाजपुर
91		नगर पालिका परिषद, गदरपुर
92		नगर पालिका परिषद, खटीमा
93		नगर पालिका परिषद, सितारगंज
94		नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज
95		नगर पालिका परिषद, किच्छा
96		नगर पालिका परिषद, जसपुर
97		नगर पालिका परिषद, नगला
98		नगर पंचायत, दिनेशपुर
99		नगर पंचायत, केलाखड़ा
100		नगर पंचायत, सुल्तानपुर
101		नगर पंचायत, महुआडाबरा
102		नगर पंचायत, शक्तिगढ़
103		नगर पंचायत, नानकमत्ता
104		नगर पंचायत, गुलरभोज
105		नगर पंचायत, लालपुर